खण्ड-239, अंक-3
मंगलवार, 30 माघ, शक संवत् 1884
(19 फरवरी, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 239 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१४१–१४५
प्रश्नोत्तर	१४५–१६३
उत्तर प्रदेश भारत प्रतिरक्षा (अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन) नियमावली, १९६३ (सदन की मेज पर रखी गई)	१६३
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	१६३
सूची में कम प्रश्न रखने पर आपत्ति	१६३–१६५
१९६३–६४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	१६५–२१४
अधिष्ठाता मंडल के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा ..	२१४
नत्थी	२१५

LEGISLATURE LIBRARY
JUN
TAR PRA

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १९ फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५४

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेश नारायण प्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह, यादव श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशवप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री

डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजाभानसिंह, कुंवर श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवीदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री

बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह,
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दूभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसजावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
राससुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुक्मसिंह राठौर, श्री
रुद्रप्रतापसिंह कुंवर,
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, खां
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ),

सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजन राम विशारद, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हुतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाला अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा सिंचाई उप-मंत्री, श्री रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार १९ फरवरी, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रिटायरमेंट एज

**१—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि १ फरवरी से ३१ मार्च सन् १९६३ तक की अवधि में रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों की अवकाश प्राप्त की अवधि ३१ मार्च सन् १९६३ तक क्यों नहीं की गयी जब कि २८ दिसम्बर सन् १९६२ से ३१ जनवरी सन् १९६३ तक की अवधि में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की अवकाश प्राप्ति की अवधि ३१ मार्च सन् १९६३ कर दी गयी है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

२८ दिसम्बर, सन् १९६२ से ३१ जनवरी, सन् १९६३ तक रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि ३१ मार्च, सन् १९६३ तक बढ़ाने वाले आदेश १९ जनवरी को उन कर्मचारियों पर भी लागू कर दिये गये हैं जो ३० मार्च, सन् १९६३ तक रिटायर होंगे ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न के प्रथम भाग के संबंध में भी आर्डर एक साथ ईशू क्यों नहीं किये गये, बाद को ईशू होने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पहले यह समझा गया था कि ३१ जनवरी, तक यह आर्डर ईशू कर दिया जायगा तमाम के बारे में किन्तु जब देखा गया कि उसमें देरी हो रही है तो यह बाद को ईशू किया गया ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

इस आर्डर के देरी से जारी करने के कारण एक फरवरी से १५ फरवरी तक कितने अधिकारी रिटायर हो चुके हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी बात नहीं है, मैंने जैसा कहा १९ तारीख को आर्डर हो गया था ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

केन्द्रीय सरकार ने जो इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित की है क्या उससे प्रभावित होकर आप भी वही निश्चय करने वाले हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसी पर हम अभी विचार कर रहे हैं। आपने यह भी अखबारों में पढ़ा होगा कि बहुत सी स्टेट्स उनको नीति से सहमत नहीं हैं।

श्री रामायणराय—

जिस समय ५८ से यह उम्र घटा कर ५५ की गयी थी उस समय यही प्रबल तर्क मुख्य मंत्री जी ने सामने रखा था कि केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारी राज्य सरकार में भी सेवा करते हैं, अतः दोनों के सेवा नियमों में समानता होनी चाहिये, क्या वही तर्क अब भी उनके सामने है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

तर्क तो दोनों तरफ के प्रबल हैं, इसी पर विचार हो रहा है कि किसको माना जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या यह सही है कि जो लोग ३० मार्च के पहले रिटायर होने वाले थे उनके रिटायरमेंट के आदेश जारी हो गये हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी तो ३१ मार्च के बाद रिटायर होने की बात है। आर्डर तो ३१ मार्च तक के लिये ही हैं, उसके बाद वे रिटायर हो जायेंगे, जो होने वाले होंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार के पास केन्द्रीय सरकार से कोई ऐसे आदेश प्राप्त हुये हैं जिसमें यह कहा गया है कि आप भी केन्द्रीय सरकार के अनुरूप अपने नियम बनायें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के आदेश नहीं भेजा करती है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

३१ मार्च तक अगर सरकार निर्णय नहीं कर पाई तो ३१ मार्च के बाद जो व्यक्ति रिटायर हो जावेंगे उनके लिये सरकार क्या विचार करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारे आदेश अभी तक यही हैं कि ३१ मार्च तक अवधि बढ़ा दी जाय। ३१ मार्च स क्या होगा, इस पर विचार हो रहा है।

श्री शराफ़त हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

बार-बार ५५ और ५८ का हेरफेर करने का क्या कारण है और क्या केन्द्रीय सरकार से ५८ साल करने का आदेश आया है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

केन्द्र से कोई आदेश तो नहीं है। मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री ने यह प्रश्न छेड़ा था। मुख्य मंत्रियों की बातचीत से ऐसा लगा कि अधिकांश प्रदेशीय सरकारें अभी ५८ नहीं करना चाहती हैं। मेरे भी विचार मांगे गये थे और मैंने कहा था कि चूंकि प्रदेशीय सरकार ने अभी ५८ से ५५ किया है, अभी केबीनेट ने कोई पुनः विचार विनिमय नहीं किया है। इसलिये अभी ५५ साल का नियम कायम है और जब केबीनेट सारे प्रदेशों की सरकारों के मत को अपने सामने रखकर विचार करेगी तब हम बता सकेंगे कि ५८ साल से कितने प्रदेशों की सरकारें सहमत हैं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अन्तिम निर्णय प्रदेशीय सरकार कब तक कर लेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अगले महीने में हम इस पर विचार कर लेंगे। अभी तो हमने यह निर्णय कर ही लिया है कि अच्छे और योग्य सरकारी अफसरों को जो फिजीकली फिट हैं उन्हें एक्सटेंशन या रिएम्पलायमेंट दे दिया जाय।

श्री रामायणराय—

जो अवधि बढ़ाई गई है यह पुनः न बढ़ानी पड़े, क्या ऐसा कोई अन्तिम निर्णय सरकार लेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब हो चुका है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

५५ साला आयु से कितने जिलाधीश और अन्य प्रकार के अधिकारी ३१ मार्च, ६३ तक रिटायर होने वाले हैं और उनमें से कितनों को कार्यक्षमता आदि गुणों पर कितने दिनों के लिये रिटेन करने जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिलाधीश तो अधिकांश आई० ए० एस० अफसर हैं और वे केन्द्रीय सरकार के नियम के अन्तर्गत जावेंगे। उसके अन्तर्गत भी केन्द्रीय सरकार ने यह अधिकार अपने लिये रख लिया है कि जब कोई व्यक्ति ५५ साल की उम्र का होने लगेगा और यदि केन्द्रीय सरकार उसे ५८ तक रखना मुनासिब नहीं समझती है तो वह ३ महीने पूर्व नोटिस दे देगी कि वह उसे नहीं रखेगी। यह मैं नहीं बता सकता कि कितने रखने हैं। मेरा खयाल है कि मार्च के पहले कोई जिलाधीश हटने वाला नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरी सूचना है कि १ से १५ फरवरी के बीच में आदेश ठीक से न पहुंचने के कारण या देर से पहुंचने के कारण काफी लोग रिटायर हो गये हैं, क्या मुख्य मंत्री जी उन्हें फिर से अपनी जगह पर रखने पर विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

रिटायर वही लोग हुये हैं जिन्हें हैड्स आफ डिपार्टमेंट्स ने एबव एवरेज नहीं समझा। हमारा आदेश यह था कि एबव एवरेज को रिएम्पलाय किया जाय या एक्सटेंशन दिया जाय।

खड्डा चीनी मिल से बकाया की वसूली

**२—श्री कैलाश (जिला देवरिया) तथा श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि खड्डा शुगर फैक्टरी ने इस वर्ष जब से मिल चलना शुरू हुई तब से आज तक गन्ने की कीमत किसानों को नहीं दी है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो अब तक कितना रुपया किसानों को गन्ने की कीमत के रूप में दिया गया है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

वर्तमान सीजन में इस मिल पर गन्ने के मूल्य के रूप में १५ फरवरी, १९६३ तक १७.४५ लाख रुपये वाजिब हुआ जिसमें से मिल द्वारा उक्त तारीख तक ३ लाख रुपया भुगतान किया जा चुका है। गन्ना आयुक्त ने मिल द्वारा १५ जनवरी, ६३ तक देय रु० ८.८४ लाख की वसूली के लिये ८ फरवरी, ६३ को रिकवरी सार्टीफिकेट जारी कर दिया है और शेष रकम की वसूली के लिये संबंधित जिलाधीश को उचित निर्देश भेज दिये हैं।

श्री कैलाश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल रुपया किसानों को कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस मिल के शुगर स्टाक्स के अगेन्स्ट बैंक को लगभग ३० लाख रुपया मिल के लिये एडवांस करना है। जैसे ही यह रुपया बैंक से आ जावेगा, तो यह कुल रकम बहुत जल्दी वसूल हो जायेगी ?

श्री कल्पनाथसिंह—

जो ३ लाख रुपया दिया गया है वह किस समय से किस समय तक दिया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कोई पीरियड इसमें नहीं है।

श्री रामायणराय—

जिन लोगों का बकाया ७ दिन से अधिक रखा गया है क्या नियम के अनुसार सरकार उन्हें सूद दिलावने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कानून के अन्तर्गत है कि उन्हें सूद दिया जाता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या सम्पूर्ण स्टाक है जिस पर बैंक एडवान्स देगा या इसके पहले कुछ और स्टाक था जिसे मिल ने बेचा ? यदि हां, तो उसे सीज कर के किसानों का रुपया देने के लिये क्यों नहीं बेचा गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस सीजन में जो स्टाक्स इकट्ठे हुये हैं उनके प्रति रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिये गये हैं। बैंक से उन स्टाक्स पर वे लोग रुपया ले रहे हैं, केवल कुछ फारमेलिटीज ही बाकी रह गयी हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दे दी गयी है कि उसका इन्तजाम जल्दी से करा दिया जाय जिससे लोगों की रकम मिल सके।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

बताया यह गया कि मिलों के पास स्टाक्स हैं उनको बैंक मार्गेज करेगा, उसकी फारमेलिटीज में कुछ देर हो रही है लेकिन मेरा कहना यह है कि उनकी जितनी कुल पैदावार हुई थी उसमें से कुछ उन्होंने बेच भी तो लिया है। तो जो स्टाक बेच लिया है क्या सरकार ने उसके रुपये को रिकवरी सर्टिफिकेट द्वारा सीज करने की कार्यवाही की ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इसकी सूचना नहीं है कि वे कितना सेल कर चुके हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने के अलावा मिल मालिकों ने जो अनियमित कार्य किया है और नियमतः ७ दिन के अन्दर रुपये का पेमेन्ट नहीं किया है तो क्या उस सिलसिले में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

नियम में यह दिया हुआ है कि अगर मिल वक्त पर रुपया नहीं देती है तो उस रुपये पर उनको सूद देना होगा और मिलों से वह सूद दिलाया जायगा, यह यकीनन होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इस बात को ध्यान में रखत हुये कि मिलों पर किसानों के गन्ने का १७ लाख रुपया बाकी है लेकिन दूसरी ओर लगान की वसूली में सरकार बहुत सख्ती कर रही है तो क्या मंत्रीजी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि मिलों से जो पर्चियां किसानों को मिलीं हैं उन पर्चियों के रूप में लगान वसूल कर लिया जाय या इस बात की हिदायत कर दें कि जिन किसानों के रुपये का पेमेंट नहीं हुआ है उनकी वसूली, जब तक उनका रुपया न मिल जाय, स्थगित कर दी जाय।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

यह बात गलत है कि जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है।

श्री कल्पनार्थसिंह---

जब सरकार को इस बात की सूचना मिल गयी है कि किसानों को उनके गन्ने का दाम पेमेंट नहीं हुआ है तो इस सूचना के मिलने से पहले या बाद में सरकार ने उस रुपये को मालगुजारी की तरह से वसूल करने का इरादा क्यों नहीं किया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

सीजन के जमाने में यह होता है कि गन्ने का दाम मिल मालिक देता है अगर कोई नहीं देता तो उस पर ब्याज दिलाया जाता है । लेकिन सीजन के बाद सरकार यह देखेगी कि कौन मिलें ऐसी हैं जो हैबिचुअल डिफालटर है उससे किसान को रुपया दिलाने की कोशिश की जायगी यदि फिर भी नहीं देती है तो लैंड रेवेन्यू के रूप में उस मिल मालिक के खिलाफ कार्यवाही करके वसूलयाबी की जायेगी ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि जो रिकवरी सर्टिफिकट्स इश्यू किये गये हैं उनके द्वारा किसानों को कितना पेमेंट किया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

रिकवरी सर्टिफिकेट ८,८४ हजार रुपये के इश्यू किये गये हैं इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये भी हिदायत भेज दी गयीं है कि और भी जो इस के अतिरिक्त रुपया हो उसको भी इसी प्रकार से वसूल करने की कार्यवाही की जाय जैसा कि रिकवरी सर्टिफिकेट के द्वारा वसूल किया जा रहा है ।

श्री कैलाश---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि पिछले साल भी रिकवरी सर्टिफिकेट्स जारी किये गये थे फिर भी कुछ मिलों ने भुगतान नहीं किया और इसकी वजह से कई मिलें बन्द हो रहीं हैं क्या इस साल इस विषय में कुछ अधिक सख्ती बरत कर उस रुपये को वसूल करने की कृपा मंत्री जी करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जैसा मैंने अर्ज किया कि सीजन के बाद हम देखेंगे कि यही मिल नहीं बल्कि प्रदेश की और ऐसी मिले जो हैबिचुअल डिफाल्टर हैं और अब भी डिफाल्ट कर रही हैं किसानों को पैसा देने में, उनके खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे और सख्त कदम उठायेंगे ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो अव्यवस्था है वह इन मिल मालिकान के आ जाने की वहज से है या कोई दूसरा कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

इसमें अव्यवस्था की तो कोई बात नहीं है । उनके ऊपर रुपया वाजिब है और वे दे नहीं रहे हैं । उनका स्टाक मौजूद है, उससे रुपया वसूल करने की कोशिश कर रहें हैं और वसूली लाजिमी हो जायगी, यह साफ जाहिर है ।

श्री नर्रसिहनारायण पांडेय---

क्या माननीय गन्ना विकास मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जब इस मिल के अथराइज्ड कंट्रोलर मौजूद थे तो उस समय किसानों के गन्ने की कीमत तथा मजदूरों की तनख्वाह का पेमेंट नियत समय पर हो जाया करता था, लेकिन जब से यह मिल नये मिल मालिकान के हाथ में आयी है तब से ये बाहर के या बैंक आदि के कर्जे जो इनके ऊपर है, उसका चुकता करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं बनिस्बत किसानों का पेमेंट या मजदूरों की तनख्वाह देने के, तो यह भी एक कारण है जिससे पेमेंट नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई निश्चित कदम उठायेगी जिससे अब भी किसानों और मजदूरों का जल्दी पेमेंट हो सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जैसा मैंने अर्ज किया कि जो रिकवरी सर्टिफिकेट भेजी गयी है, वहां से हमें सूचना मिली कि बैंक ऐडवांस होने ही वाला है, फारमलिटीज कुछ रह गई है, वह हो जाने के बाद किसानों का रुपया वसूल हो ही जायगा । फिर भी अगर कुछ बाकी रहा तो इस सीजन के बाद हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठायेंगे ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

आगरा कैनाल का रिमार्डलिंग

*१—श्री मनसाराम (जिला मैनपुरी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा कैनाल के रिमार्डिंग कराने पर कितना धन व्यय हुआ है ?

सिंचाई उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

आगरा कैनाल के रिमार्डलिंग पर दिसम्बर, १९६२ तक ६७,३०,०२७ रु० व्यय हुआ है ।

श्री मनसाराम—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ६२ के पहले इस नहर से कितनी आबपाशी होती थी और अब कितनी होती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सिंचाई तो बारिश पर और अन्य चीजों पर भी निर्भर होती है लेकिन सन् ६१–६२ में सिंचाई हुई है—३,२३,७०३ एकड़, उसके पहले सन् ६०–६१ में ३,१४,४९२ एकड़, सन् ५९–६० में पानी कम बरसा तो उस साल सिंचाई ज्यादा हुई यानी ३,९७,९४९ एकड़, सन् ५८–५९ में २,३१,०५७ एकड़ और सन् ५७–५८ में २,९४,९७४ एकड़ ।

श्री मनसाराम—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ६२ के बाद कितनी आबपाशी हुई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सन् ६३ का डिटेल तो अभी आया नहीं है । लेकिन खरीफ के बारे में मैं केवल निवेदन कर दूं कि १,३१,१११ एकड़ में सिंचाई हुई है ।

श्री रामचन्द्र बिकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिमार्डलिंग में क्या-क्या चीजें सम्मिलित हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

चौड़ा करना, पुलों को बढ़ाना, झालों को तोड़ना या ठीक करना, फाटकों को चौड़ा करना, नहर की क्षमता क बढ़ाने के लिये जो आवश्यक होता है, रिमार्डलिंग में वे सारी चीजें सम्मिलित हैं ।

श्री रामायणराय—

६७ लाख रुपया खर्च करने के पहले इसकी क्षमता क्या थी और अब इतना खर्च करने के बाद कितनी बढ़ गई है क्या मंत्री जी यह बतायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके पूर्व यों तो यह १९७४ में बनी थी और उस समय इसकी क्षमता १,१०० क्यूसेक की थी और उसके बाद बिना किसी विशेष बढ़ाने के कार्य के ही उस पर २,००० तक ओवरलोड चलता रहा और अब उसको ३,२०० कर दिया गया है ।

कांघी रजबहा का निर्माण

*२—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में ग्राम कांघी में कांघी रजबहा नामक नहर में १४ मील ३ फर्लांग पर कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

माइनर के मार्ग परिवर्तन का प्रश्न शासन के विचाराधीन था । इसलिये कार्य रोक दिया गया था ।

*३—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सरकार उसे फिर से प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कार्य पुनः प्रारम्भ करने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रजबहे का मार्ग किसी की दरख्वास्त के कारण परिवर्तन हुआ या यों ही ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसमें श्री शिवनारायण शुक्ल, ग्राम कांघी, जिला फतेहपुर ने शिकायत की थी और कहा था कि वह पहले जिस जगह से निकाली जा रही है उस जगह से नहीं बल्कि उनके बाग से होकर निकलने का विचार है जिसमें कि ४० वृक्ष कटेंगे, इस कारण ऐसा हुआ ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वजह से शिकायत हुई उसी स्थान पर यह पुल बना और बनने का आदेश दिया गया या पहले जहां बनने वाला था वहां ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ऐसा आदेश अब हो गया है जिससे पेड़ों को काटने की आवश्यकता न पड़े, इस तरह से नहर निकालने की व्यवस्था की जाय ।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह माइनर कितनी लम्बी है और कितनी आगे और जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यों तो यह प्रश्न इस से नहीं उठता लेकिन जिस जगह यह है वहां यह १४ मील का प्रश्न है ।

आजमगढ़ जिले में बस स्टेशनों के भवन

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या परिवहन मंत्री ११ दिसम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जमीन पर कब्जा मिल जाने के बाद कौन-कौन कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—

तामीर की लागत का तखमीना बना, टेन्डर मांगे गये उन पर विचार करके एक ठेकेदार का टेन्डर मन्जूर किया गया और उसने काम शुरू कर दिया ।

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बस स्टेशन रसड़ा और विल्थरा रोड जिला बलिया के भवनों का धरातल सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क से नीचा होने के कारण बरसात में पानी जमा हो जाता है जिससे यात्रियों तथा बसों का आना-जाना रुक जाता है और परेशानी उठानी पड़ती है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

जी हां।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दोहरीघाट और मधुबन जिला आजमगढ़ के राजकीय बस स्टेशनों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में करने की योजना है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

दोहरी घाट में राजकीय बस स्टेशन बनने का काम शुरू हो गया है। मधुबन में अभी जमीन प्राप्त की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन भवनों का धरातल पी० डब्लू डी० की सड़क से नीचा होने की जांच पड़ताल इनको बनाने से पहले नहीं की गई थी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

जांच पड़ताल के बाद ही तो बस स्टेशन बनना शुरू हुआ था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब जांच पड़ताल करने के बाद बस स्टेशन बना तो फिर धरातल नीचे क्यों हो गया और पानी लगा रहता है, क्या फिर से बनाने के लिये कुछ तखमीना हुआ ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

यह एतराज सही है इस पर जांच की जायगी और एक आम सर्कुलर इश्यू कर दिया गया कि इसको पहले से देख लिया जाया करे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मंत्री जी बतायेंगे कि इसका तखमीना क्या था और अब जो धरातल नीचा हो गया है उसके पूरा करने की व्यवस्था की जा रही है और उसमें कितना रुपया व्यय हो रहा है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

अर्थ वर्क और एप्रोच रोड बनाने के लिये तखमीना बनाया जा रहा है। जब कम्प्लीट हो जायगा तब बताया जा सकेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आधा उत्तर दिया गया है। पहले जो बस स्टेशन बना था उसका क्या खर्चा था ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

उस अफसर के खिलाफ जिसने जानबूझ कर धरातल नीचा रखा था जांच कराने की मंत्री जी कृपा करेंगे या उस अफसर का नाम बतायेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने पहले ही अर्ज किया इसके बारे में जांच पड़ताल की जायगी।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

नाम तो बतायें।

श्री उपाध्यक्ष—

नाम की कोई खास जरूरत नहीं है और न नोटिस ही होगा । उन्होंने बता दिया कि जांच की जायगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जैसा मंत्री जी ने कहा सर्कुलर इश्यू कर दिया गया है तो धरातल नीचा रहा और इंजीनियर ने गल्ती की इसको महसूस करते हुये इस कार्यवाही के बाद सारे सूबे में सर्कुलर इश्यू कर दिया गया बिन कोई वजह के ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वह तो बहुत जरूरी है कि जब कोई जमीन ली जाय तो उसका धरातल वगैरह देख लिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मंत्री जी बतायेंगे कि तामीर का तखमीना क्या था और कौन-कौन भवन बनवाने के लिये तखमीना था ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

सूचना की जरूरत है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैंने प्रश्न ४ के बारे में सप्लीमेन्टरी किया है इसके लिये कहते हैं सूचना की जरूरत है । उत्तर में दिया है कि तामीर की लागत का तखमीना बना । मैं पूछ रहा हूं तखमीना क्या था और किन-किन भवनों का था और उसके लिये ही मंत्री जी नोटिस चाहते हैं तो कैसे सदन का काम चलेगा ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—

श्रीमन्, मुझसे गलती हुई । जैसा कि मैं समझ रहा था माननीय सदस्य शायद प्रश्न संख्या ५ के बारे में कह रहे हैं । प्रश्न ४ के बारे में मेरे पास इत्तला है कि १२,००० रुपये का एस्टीमेट बना ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

फिर आधा जवाब दिया । कौन-कौन भवन बनने वाले थे ?

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये क्रास ऐग्जामिनेशन तो होता नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

साफ लिखा हुआ है लागत का तखमीना बना । मैं पूछना चाहता हूं किन-किन भवनों का तखमीना था?

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी, सूचना हो तो बता दें ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—

यह तो पूरी डिटेल की बात है । मैंने बता दिया १२,००० रु० के टेंडर मांगे गये और ११,७३५.११ का टेंडर स्वीकार हो गया है रनिंग रूम बनाने के लिये ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

प्रश्न संख्या ५ में दो राजकीय बस स्टेशनों के भी धरातल नीचे होने की बात कही गई । तो क्या उनके धरातल के नीचा होने के बाद विभागीय अधकारियों से पहले ही सूचना मिल गई थी या प्रश्नकर्ता के प्रश्न के बाद मिली और तब आदेश जारी किये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन---

अगर इत्तला न मिली होती तो उसको ऊंचा करने का प्लान क्यों बनाते। वह तो बात जाहिर है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---

जिन लोगों को रसड़ा और बिल्थरा रोड बस-स्टेशनों की जानकारी है वे इस बात को जानते हैं मुझको जानकारी है और उसी जानकारी की बिना पर मैं यह कह रहा हूं कि इन दोनों बस स्टेशनों की जमीन इतनी नीची है और नीची जमीन के हिसाब से जो फ्लोर की कुर्सी थी वह भी नीची बनी है, तो अब जब पूरा धरातल ऊंचा किया जायगा तो कुर्सी को भी ऊंचा करना पड़ेगा तो रिमार्डलिंग में भवन का खर्चा बहुत बढ़ेगा तो जो खर्चा बढ़ेगा उसका कुछ खमियाजा उन लोगों से भी लेंगे जो जिम्मेदार हैं इस गलती के ?

श्री मुजफ्फर हसन---

इतनी तफसील तो मौजूद नहीं है लेकिन यह मैंने जरूर कहा है कि क्यों ऐसा हुआ इसकी जांच की जायगी, कौन उसके लिये जिम्मेदार है यह जाना जायगा और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ फैसला हो सकेगा कि उस पर कुछ कारवाई हो सकेगी या नहीं।

[१९ फरवरी, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१---श्री मनसाराम---

[हटा दिया गया]

*२-३---श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*४-६---श्री रक्षपालसिंह---

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*७---श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)---

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर की आडिट रिपोर्ट

*८---श्री गंगाप्रसादसिंह---

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ से अब तक केन्द्रीय कर्मशाला कानपुर (Roadways Central Workshop, Kanpur) का कितने बार आडिट हुआ है और क्या सरकार उन आडिट रिपोर्टों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

१० बार। यह रिपोर्ट काफी बड़ी है, यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे कार्यालय में आकर देख लें।

श्री गंगाप्रसादसिंह---

क्या यह सही है कि सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर के संबंध में आडिट रिपोर्ट ने १९५७-५८ की अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ८ वर्ष से मोटर के बहुत से पार्ट्स बेकार पड़े हैं और उसमें से बहुत से खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो उनका किस तरह से डिसपोजल हुआ है और उसकी वजह से कितने सरकारी धन की क्षति हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन---

यह बात सही है कि उस वक्त कुछ स्पेयर पार्टस् ज्यादा यों खरीद लिये गये थे कि कोरिया की लड़ाई चल रही थी, चीजों की कीमत बढ़ गयी थी और समझा गया कि स्टाक कर लिया जाय। बाद में बाहर की गाड़ियां आनी बन्द हुई और नयी गाड़ियां चलने लगीं जिसकी वजह से इन पार्टस् का ज्यादा काम नहीं है और उसमें नुकसान भी हुआ। अब फौजी जरूरत की वजह से कुछ इन स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ रही है और थोड़ा-थोड़ा वह निकलना शुरू हुआ है।

श्री गंगाप्रसादसिंह---

अब तक कितना डिसपोज आफ हो गया है और कितनी धनराशि का अभी डिसपोजल होना बाकी है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

यह तफसील नहीं है ।

श्री रामायणराय---

माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि जो आडिट रिपोर्ट है उसे माननीय सदस्य उनके कक्ष में जाकर देख लें । आडिट रिपोर्ट अगर वे पूरी नहीं बता सकते हैं, जो कि सम्भव भी नहीं है शायद उनके लिये, तो क्या केवल इतना बताने की कृपा करेंगे कि आडिट ने मुख्य-मुख्य क्या आब्जेक्शन किये हैं इस विभाग के बारे में क्योंकि अभी जो उत्तर वे रहे हैं उससे एक वैधानिक प्रश्न उठता है । किसी भी स्टोर के लिये एक सीमा निश्चित होती है कि इतनी धनराशि का सामान खरीदा जा सकता है । अतिरिक्त खरीद के लिये सरकर से आज्ञा लेनी पड़ती है । तो क्या इन लोगों ने कोई इजाजत सरकार से उस अतिरिक्त खरीद के लिये ली थी या अपनी ओर से खरीद लिया ?

श्री मुजफ्फर हसन---

यह तफसील तो इस वक्त सामने है नहीं । जो मुख्य आब्जेक्शन है वह यही था कि एक बड़ी तादाद में स्पेयर पार्ट्स खरीद लिये गये थे । जाहिर है कि जब इस तरह की इमरजैन्सी आती है जैसी कि कोरिया की लड़ाई के वक्त में हुई थी तो डिपार्टमेंट ने उसको खरीदारी जरूरी समझी होगी और खरीद लिया ।

श्री रामायणराय---

मान्यवर, सवाल यह नहीं है । इसको जरा स्पष्ट करा दें कि जो भी खरीद की गई है सरकार की इजाजत से या विभागीय अधिकारियों ने अपने मन से खरीद लिया है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

जरूर सरकार से आज्ञा ली होगी । विभाग बिना सरकार की आज्ञा के कैसे खरीद सकता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाता हूं कि सदन में कोई भी मंत्री "होगी" कह कर जवाब नहीं दे सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें उन्होंने कहा कि तफसील के लिये नोटिस नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, हमारी वैधानिक आपत्ति "होगी" पर है ।

श्री उपाध्यक्ष---

जवाब तो उतना ही देना चाहिये जितनी सूचना हो । नहीं तो कहना चाहिये कि सूचना नहीं है ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

मान्यवर, क्या मंत्री जी के लिये यह जरूरी है कि सदन में हर बात को रट कर बैठे ?

श्री गंगाप्रसादसिंह---

क्या यह सही है कि लाखों रुपये के रबर के टायर पड़े रहे और उनका कोई उपयोग नहीं हुआ ? यदि हां, तो सरकार का कितना नुकसान हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन--
कोई तफसील नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव--
क्या यह सही है कि बहुत से स्पेयर पार्टस् खरीद लिये गये थे जो आउट आफ यूज हो गये थे ? इस तरह से धन का दुरुपयोग हुआ है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--
श्रीमन्, जो पार्ट्स उस समय खरीदे गये थे वे पैट्रोल इंजिन के थे। वे समाप्त हो गये और डीजिल के इंजिन चलने लगे तो वे बेकार हो गये। अब वे गाड़ियां नहीं हैं जिनमें वे इस्तेमाल किये जा सकें।

वाराणसी जिले में कृषि फार्मों से आय

*९--श्री ऊदल--
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में तहसील चन्दौसी व मड़ुआडीह में तथा आराजीलाइन में जो सरकार के ऐग्रीकल्चर फार्म हैं उनमें पिछले पांच वर्षों से क्या आय हुई, कितना व्यय हुआ तथा पैदावार कितनी हुई ?

कृषि उपमंत्री (श्री शिवराजसिंह)--
वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१५ पर)

श्री ऊदल--
क्या मंत्री जी सूचना को देखने की कृपा करेंगे कि चन्दौली फार्म में पहले मुनाफा था लेकिन ६०-६१ और ६१-६२ से घाटा शुरू हुआ। इसी तरह से मड़ुआडीह फार्म से पहले मुनाफा था लेकिन बाद में घाटा शुरू हुआ। इसी तरह से आराजीलाइन फार्म में हर साल घाटा है। जितने आपने फीगर्स दिये हैं और पहले भी घाटा है तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि इन फार्मों के अलावा जिन पर घाटा है उसको किस तरह से पूरा किया जाय। इस पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री शिवराजसिंह--
मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पैदा कर दिया। इन तीन फार्मों पर घाटे की मुख्तलिफ वजूहात हैं। सब फार्मों पर घाटा नहीं हो रहा है और काफी ऐसे फार्म हैं जो मुनाफे पर चल रहे हैं। इसके अलावा मिकैनाइज्ड फार्मों के संबंध में एक कमेटी बैठी थी १९५८ में। उसकी रिपोर्ट १९५९ में प्राप्त हो गई और सरकार ने उसकी सिफारिशों पर फैसले लिये हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट फार्म कमेटी बैठी थी। उसकी सिफारिशों के संबंध में भी सरकार ने फैसला ले लिया है और फार्मों को हर तरह से सुधारा जा रहा है। हमने फैसला किया है कि जो फार्म जितना खराब है उसको उतनी ही बड़े अफसर की जिम्मेदारी है कि वह उसको संभाले। इस प्रकार से जिन फार्म्स पर सबसे ज्यादा घाटा है उन फार्म्स को डिप्टी डाइरेक्टर को सौंपा है कि उन फार्म्स के घाटे को घटा कर उनको मुनाफे पर चला कर दिखायें तभी उसके कैरेक्टर रोल में अच्छी इंट्री दी जायगी।

श्री ऊदल--
क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि चंदौली फार्म, मड़ुआडीह फार्म और अराजीलाइन फार्म कितने-कितने एकड़ के फार्म हैं और एकड़ों को देखते हुये इनकी पैदावार बहुत कम है, इसके बारे में सरकार की क्या राय है ?

श्री शिवराजसिंह---

मान्यवर, चंदौली का फार्म ३३.४३ एकड़ का है जिसमें ३१.७५ एकड़ जेरे काश्त है। पिछले पांच वर्षों में लगातार इसकी उपज बढ़ती गयी है। १९५७-५८ में इसकी उपज १९ मन ५ सेर प्रति एकड़ थी। वह बढ़ कर १९६१-६२ में २३ मन ११ सेर प्रति एकड़ हो गयी, जो काफी अच्छी उपज कही जा सकती है। क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र वाराणसी, मडुआडीह फार्म का कुल क्षेत्रफल ७७.६० एकड़ है। इसमें ७६.४३ एकड़ जेरे काश्त है। १९५७-५८ में इसकी उपज १३ मन १४ सेर प्रति एकड़ थी। १९६१-६२ में वह बढ़कर २४ मन प्रति एकड़ हो गयी जो काफी अच्छी उपज कही जा सकती है।

श्री रामायणराय---

मान्यवर, प्रश्न यह है कि उपज में कितनी वृद्धि हुई। प्रश्न यह है कि मुनाफे में जा रहें हैं या घाटे में जा रहें हैं। मान्यवर, मेकेनाइज्ड फार्म को हमने देखा। ४० रुपये मन पैदा किया था तो कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है यह मैटीरियल प्वाइंट है जिससे जान सकेंगे कि इन फार्म्स पर लाभ हो रहा है या हानि। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये फार्म्स सीड मल्टिप्लिकेशन फार्म्स हैं, पशुओं की अच्छी नस्ल पैदा करने के लिये फार्म्स हैं, शोध कार्यों के लिये फार्म्स हैं या कमर्शियल फार्म्स हैं ?

श्री शिवराजसिंह---

चंदौली का फार्म उन्नत बीज पैदा करने के लिये है। क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र वाराणसी, मडुआडीह रिसर्च स्टेशन है जहां पर अच्छी बीज भी पैदा करते हैं और अनुसंधान भी किया जाता है। मैकेनाइज्ड रटेट फार्म आराजी लाइन पर सीड भी पैदा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त गंगातिरी नस्ल की गायों के सांड़ पैदा किये जाते हैं और गायों को पाला जाता है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

मंत्री जी ने कहा कि कुछ फार्म्स में मुनाफा भी होता है। क्या वह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुल फार्म्स को मिला कर हानि होती है या लाभ, ओवर आल पिक्चर क्या है ?

श्री शिवराजसिंह---

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

मंत्री जी ने यह बताया कि जितना ही बड़ा जिस फार्म पर घाटा है उतना ही बड़ा अफसर उस पर रखा गया है, इसके अलावा सरकार ने क्या फैसला लिया है जिससे घाटे को दूर किया जा सके ?

श्री शिवराजसिंह---

मान्यवर, फार्म के संबंध में विभिन्न फैसले लिये गये हैं। उसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री रामायणराय---

मान्यवर, लगभग ८ लाख रुपये प्रति वर्ष इन फार्म्स पर घाटा हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस कमेटी की सिफारिश पर मंत्री जी ने अमल करना शुरू किया है उस अमल के बाद यह घाटा कुछ कम हुआ है या नहीं, इससे क्या वह सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री शिवराजसिंह---

मान्यवर, घाटे की खास वजह यह है कि जितनी भूमि इन फार्मों में ली गई है वह खरीदी गई है और उस भूमि की लागत पर काफी बड़े रेट से सूद दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जितनी भी वहां पर बिल्डिंग्स बनी हैं जितनी वहां पर सड़कें और फेंसिंग है और जितने भी ट्यूबवेल्स और बैल और मशीनरी वगैरह हैं उन पर काफी बड़े रेट से डेप्रिशयशन दिया जाता है। इसके

अतिरिक्त जो सुधार इन जमीनों पर किये गये हैं, आम तौर से मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म या और दूसरे फार्म्स उन जमीनों पर खोले गये थे जो जमीनें अच्छी और उपजाऊ नहीं थी, तो सोचा यह गया था कि इन जमीनों पर कृषि विभाग अपनी जानकारी से और अपने रिसर्च के नतीजों से अच्छी फसल पैदा कर सकता है और इनको उपजाऊ बना सकता है, इसलिये काफी मात्रा में धन खर्च करना पड़ा है, इन फार्मों की जमीन को उन्नत करने में और जब इन फार्म्स की बैलेंस शीट तैयार की जाती है तब उसमें जितनी उन्नति उन जमीनों के अन्दर हो जाती है, वह लागत नहीं लगायी जाती है, अगर वह लागत भी लगायी जाय तो मैं सदन को विश्वास दिलाता चाहता हूं कि तसवीर दूसरी होगी, और यह तमाम स्टेट फार्मस जितने हैं ये बजाय घाटे के नफे के हो जायेंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या कृषि मंत्री इस बात को देखते हुये कि ५८-५९ की रपट में इस बात की भी चर्चा की गई है कि जो घाटा हो रहा है उसका एक कारण यह भी है कि इसमें मैल-ऐडमिनिस्ट्रेशन रहा है, सुपर-वीजन खराब रहा है और यह खर्चे जो हैं यह नाजायज किये गये हैं, तो आगे यह चीजें न होने पायें, इसके लिये उन्होंने क्या इन्तजाम किया है ?

श्री शिवराजसिंह---

श्रीमन्, माननीय सदस्य की जानकारी गलत है ।

श्री रामायणराय---

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि इन फार्म्स के ऊपर कुछ ऐसे औजार खरीद लिये गये जिनका इन फार्म्स पर कोई उपयोग नहीं हो रहा है जैसे हस्तिनापुर में एक पास्चुराइज्ड प्लान्ट है, इसके अलावा कुछ फार्म्स ऐसे हैं जहां जमीन अगर १०० एकड़ है तो ट्रैक्टर चार या पांच खरीद लिये गये जो बेकार पड़े हुये हैं, इसी तरह जमीन अगर १०० एकड़ है तो उसको सींचने के लिये चार चार ट्यूबवेल लगा लिये गये, तो इस तरह से भूमि और उसका उपयोग दोनों बातों को दृष्टि में न रखकर इन फार्म्स को चलाया गया जो मुख्य कारण है इन फार्मों पर घाटे का ?

श्री शिवराजसिंह---

मायन्वर, यह प्रश्न केवल तीन फार्मों के संबंध में था । लेकिन आपने इजाजत दी है तो मैं निवेदन कर दूं कि शुरू-शुरू में जब जमीनें बंजर थीं तो उन जमीनों को तोड़ने के लिये बड़ी मशीनें खरीदी गई । तत्पश्चात् वह मशीनें दूसरे फार्मों को ट्रांसफर होती रहीं । जो मशीन किसी फार्म के मतलब की नहीं रही उनका बाद को नीलाम भी कर दिया गया । यह बात सही है कि आराजी लाइन का फार्म जिसके संबंध में प्रश्न है, उस फार्म को शुरू-शुरू में १५३० एकड़ पर चलाने का सरकार का इरादा था लेकिन यह जमीन मिलीटरी कैम्पिंग ग्राउन्ड थी जो सरकार के लेने के पहले वहां ठेकेदार के कब्जे में थी और छोटे-छोटे काश्तकार उनको जोता करते थे । बाद को वहां एजीटेशन हुआ और सरकार को १५३० के बजाय यह फार्म ३४५.५७ एकड़ पर चलाना पड़ा । इस तरह से जितनी भूमि खरीदी गई.... (व्यवधान) ।

एक सदस्य---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी लेक्चर दे रहे हैं और दूसरे सवालों का समय बीता जा रहा है ।

*१०-१२---श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३-१४---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५-१६--श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--
[५ मार्च १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७-१९--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--
[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रतापगढ़ बस स्टेशन पर रनिंग रूम निर्माण योजना

*२०--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--
क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ रोडवेज बस स्टेशन पर ड्राइवरों एवं कन्डक्टरों के रात्रि विश्राम के स्थान की कोई व्वयस्था अब तक नहीं है जिससे उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है? क्या सरकार उनकी इस तकलीफ को दूर करने के लिये कोई कदम उठाने का विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री गनेशीलाल चौधरी--
जी हां, रनिंग रूम के लिये भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रतीपाल--
क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वहां के स्टेशन मास्टर जो ड्राइवर शाम को बाहर से लौटकर आते हैं उनको रनिंग रूम के न होने पर गाड़ियों में सोने नहीं देते, तो क्या विभाग के फंड से किराये का मकान लेकर ड्राइवरों और कंडक्टरों के रहने की व्यवस्था सरकार करेगी?

श्री गनेशीलाल चौधरी--
१९६३-६४ के बजट में रनिंग रूम के लिये २० हजार रुपये की व्यवस्था है और जल्दी ही उस पर कार्यवाही शुरू हो जायगी।

श्री रक्षपालसिंह--
क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो असुविधा है वह केवल एक स्टेशन की नहीं है प्रदेश भर के सभी स्टेशनों की है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था सभी स्टेशनों पर करेंगे जहां पर कंडक्टर और ड्राइवरों को रहने की असुविधा होती है?

श्री गनेशीलाल चौधरी--
सरकार के सामने इसका प्रश्न सदैव रहता है कि अधिक से अधिक सुविधा इन लोगों को दी जाय। ज्यों ज्यों धन उपलब्ध होता जायगा सब जगह कार्यवाही की जायगी।

*२१--श्री चन्द्रबलीसिंह--
[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

लघु सिंचाई योजना

*२२-श्री रामसुन्दर पाँडेय-
क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने लघु सिंचाई योजनाओं में ५० प्रतिशत वृद्धि करने हेतु कोई पत्र जनवरी, १९६३ के द्वितीय सप्ताह में भेजा है? यदि हां, तो वह क्या है और सरकार द्वारा उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर रामनारायण पॉडेय---

कुछ समय पहले भारत सरकार से लघु सिंचाई योजनाओं की वृद्धि के विषय में एक पत्र प्राप्त हुआ फलस्वरूप भारत सरकार तथा प्लानिंग कमीशन को कुछ अतिरिक्त लघु सिंचाई योजनाओं का प्रोग्राम भेजा गया । इसके बाद भारत सरकार ने नवम्बर १९६२ में ५० प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव भेजा । क्योंकि भारत सरकार को बढ़ोत्तरी के सुझाव पहले ही भेजे जा चुके थे इसलिये इस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बल्कि भारत सरकार का ध्यान इस पत्र व्यवहार की ओर दिलाया गया जिसमें यहां से पहले ही सुझाव भेजे गये थे और उनसे अनुमति प्रदान करने के लिये अनुरोध किया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार की ओर से भारत सरकार को जो सुझाव दिये गये थे वह क्या सुझाव थे ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---

अगस्त, १९६२ में फूड एण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भारत सरकार ने एक खत इस सरकार के लिये भेजा जिसमें लिखा कि २० फीसदी पैदावार बढ़ाने के लिये तीसरे प्लान में कुछ छोटी योजनायें बढ़ा दी जायं। इसके फलस्वरूप सितम्बर के महीने में हमारे यहां के नियोजन विभाग ने उनको ७ करोड़ ३६ लाख से ऊपर की एक योजनाओं की लिस्ट बना कर भेज दी और यह लिख दिया कि जैसे दूसरे प्लान में हुआ करता था और छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये २५ फीसदी सबसिडी मिलती रही, वह सबसिडी दी जाय और ट्यूबवैल पर भी २५ फीसदी सबसिडी दी जाय। यह लिखकर भेज दिया । इसके बाद उनका जवाब आना बन्द हो गया । फिर जब लड़ाई शुरू हुई तब एक खत फिर आया और उसमें भी यही लिखा कि लघु सिंचाई योजनाओं के लिये ५० फीसदी बढ़ा दिया जाय। एक और खत उनके डिप्टी डेवलपमेंट मिनिस्टर का आया कि वह पैसा उठाया नहीं जा रहा है। इसके जवाब में फिर लिखा दिया गया कि आपको जो सितम्बर के महीने में यहां से लिखा गया था जिसमें इस बात पर जोर दिया था कि २५ फीसदी सबसिडी दी जाय इसको आप ध्यान में रखकर जवाब दीजिये और उसका समावेश कर लिया जायगा किन्तु उसके बाद से कोई जवाब नहीं आया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन को अतिरिक्त लघु सिंचाई योजना का प्रोग्राम क्या भेजा गया था और भारत सरकार ने क्या उसका वही उत्तर दिया जो नवम्बर, १९६२ में आया है ?

श्री राममूर्ति---

मैंने अर्ज किया कि ७ करोड़ ३६ लाख से कुछ अधिक रुपया की लघु सिंचाई योजनायें बनाकर उनको भेजी थी लेकिन जोर इस बात पर दिया गया कि जैसे दूसरे प्लान में होता रहा है उसी प्रकार से सबसिडी २५ फीसदी की छोटी योजनाओं के लिये मिलनी चाहिये। इस बात का कोई जवाब नहीं देता । हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी यह लिखा था कि अगर इसका जवाब दे दिया जाय तो रुपया उठा लिया जायगा और काम किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जो प्रतिमास प्लानिंग कमीशन की बैठकों में जाया करते हैं क्या उनके द्वारा इन योजनाओं के विषय में, जो प्रदेश की बहुत बड़ी योजनायें है, उनके संबंध में कोई चर्चा उठाई गई है कि भारत सरकार या प्लानिंग कमीशन जल्दी उत्तर प्रदेशीय सरकार को जवाब दे ?

श्री राममूर्ति---

उनके द्वारा वक्तनफवक्तन चर्चा उठाई जाती है। ५,७ रोज पहले प्लानिंग कमीशन के रिप्रिजन्टेटिव यहां आये थे और मेरी उनसे बातचीत हुई थी । मैंने इस बात पर जोर

दिया लेकिन और सब बातें तो उठा करती हैं वे असली बात का जिक्र नहीं करते। हम उसके लिये उनको जवाब देने को कहते हैं लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

उत्तर प्रदेश सरकार की लघु योजनाओं में कौन कौन स्कीमें शामिल हैं ?

श्री राममूर्ति--

इसमें १२५० मील ट्यूब वेल की पक्की नालियां बनाना, ४२०० मील कच्ची नालियां बनाना, ५०० नये ट्यूब वेल बनाना, ५०० ट्यूबवेलों को बिजली लगाना, ३० मील घाघरा कैनाल सिस्टम को बढ़ाना, बेतवा कैनाल सिस्टम पर उरई डिवीजन में एक्सटेंशन, ऐसे ही दरियाबाद ब्रांच का बढ़ाव, माधोपुल डिस्ट्रीब्यूटरी का बढ़ाव, हरीपुर माइनर का बढ़ाव, विजयपुर बंध और ५०,००० से कम की लागत जितनी योजनायें है वे सब इसमें है। और इसमें है गोलापार नहर जो बनी हुई है उसकी क्षमता बढ़ाना, इसके साथ ही दूसरी गोलापार नहर की क्षमता को बढ़ाना । यह सब मिला कर ७ करोड़ ३६ लाख की योजनायें है ।

*२३-२४--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*२५--श्री गंगाप्रसाद सिंह--

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*२६-२८--श्री गयाप्रसाद--

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

घाटमपुर तहसील में सिंचाई

*२९--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत कहां और कितने कुलाबे ऐसे हैं जहां चकबन्दी के कारण नालियां खत्म हो जाने से सिंचाई नहीं हो सकी ?

श्री राममूर्ति--

ऐसा कोई कुलाबा नहीं है।

वृद्धावस्था तथा राजनीतिक पीड़ित पेन्शन

*३०--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे विधान मंडल के सदस्य हैं जिनको राजनीतिक पीड़ित होने के नाते पेंशन मिलती है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

कोई नहीं ।

*३१--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि वृद्धों और राजनीतिक पीड़ितों से पेंशन हेतु डाक्टरी मुआइना फीस न ली जाय ?

नोट--तारांकित प्रश्न २२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री मुजफ्फर हसन—

वृद्धों (राजनैतिक पीड़ितों से बुढ्ढावस्था पेंशन) राजनीतिक पीड़ित पेंशन के सिलसिले में जब सरकारी तौर से डाक्टरी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाता है तब उनसे कोई डाक्टरी मुआइना फीस नहीं ली जाती है।

अतारांकित प्रश्न

१–४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किय गये ।]

५—श्री सुरेंद्रविक्रम (जिला शाहजहाँपुर) तथा श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर)—

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया जाय ।]

६–८—श्री गयाप्रसाद—

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

९–११—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[५ फरवरी १९६३ के लिये प्रश्न १–३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

वाराणसी तहसील में नलकूपों का सुधार

१२—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी तहसील के ट्यूबवैल ताड़ी दुल्लीपुर परगना पंद्रह की जो नाली दक्षिण से उत्तर को जाती है उसके बीच में एक नाला पड़ता है उसमें साइफन आज तक क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री राममूर्ति—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—नाले पर साइफन लगा दिया गया है।

१३—श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि उक्त तहसील के नलकूप बेलवा में जो नाली पश्चिम से दक्षिण की तरफ जाती है उसमें लखीमपुर के बीच से पश्चिम के लिये एक नाली निकालने का प्रस्ताव था? क्या उस पर विचार हो गया है? यदि हां, तो नाली कब तक निकाल दी जावेगी ?

श्री राममूर्ति—

ग्राम लखीमपुर के लिये चार फर्लांग पक्की गूल प्रस्तावित है। धन उपलब्ध होने पर इस गूल का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में हो जाने की आशा है।

रामगंगा प्रोजेक्ट

१४—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामगंगा प्रोजेक्ट में कुल कितना स्टाफ काम करता है (हर पदाधिकारी तथा कर्मचारी की अलग-अलग संख्या दी जाये) और उस पर कितना रुपया सालाना खर्च होता है पहली अप्रैल, १९६२ के बाद उसमें क्या-क्या काम हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

रामगंगा प्रोजेक्ट पर १०९१ कर्मचारी काम कर रहे है। इनकी †सूची 'अ' संलग्न है।

---

†छापी नहीं गई।

इस स्टाफ पर लगभग १३.८० लाख रुपया वार्षिक खर्च होते हैं।

रामगंगा प्रोजेक्ट पर १ अप्रैल, १९६२ के बाद जो कार्य हुये उनका विवरण संलग्न †सूची "ब" में दिया हुआ है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मुझे प्रश्नों के संबंध में एक निवेदन करना था....

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में करियेगा।

उत्तर प्रदेश भारत प्रतिरक्षा (अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन) नियमावली, १९६३*

मन्त्री के सभा-सचिव (श्री बृजबिहारी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट, १९६२ की धारा ३८ के अन्तर्गत बनायी गयी तथा राजस्व (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३/१-ख, दिनांक १ फरवरी, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भारत प्रतिरक्षा (अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन) नियमावली, १९६३ को सदन की मेज पर रखता हूं।

नियम ५२ के अंतर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत चार सूचनायें आयी हैं जिनमें दो चेचक के बारे में है। चेचक के ऊपर पहले भी सूचना आयी थी और उसे मैंने अस्वीकार कर दिया था इस विषय पर प्रश्न भी हो चुके हैं। फिर भी मैंने यह देख कर कि बांदा में इससे मौतें ज्यादा हो चुकी हैं इसे सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिय भेज दिया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

बांदा में २००० लोग मर गये हैं अभी हाल ही में, मंत्री जी से वक्तव्य मांग लीजिये।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

कानपुर में बड़ा असंतोष है और उसके लिये भी एक प्रस्ताव है। उसे आपको स्वीकृत करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका भी है। उसे मैंने उचित कार्यवाही के लिये सरकार के पास भेज दिया है। उस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

उचित कार्यवाही में क्या-क्या होता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अटेंशन ड्रा होती है। चौथा है इटावा तथा आगरा में डाकुओं की समस्या के बारे में यह बात पुरानी है, लेकिन फिर भी मैंने इसे सरकार के पास भेज दिया है।

सूची में कम प्रश्न रखने पर आपत्ति

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, कल आप के सम्मुख यह प्रश्न रखा गया था कि प्रश्न हम लोग भेज देते हैं और.....

श्री उपाध्यक्ष—

वह बात हो चुकी है। आप इस वक्त विराज जाइये।

---

†सूची छापी नहीं गई।

*छापी नहीं गई।

[श्री उपाध्यक्ष]

कल रामसुन्दर जी से थोड़ी सी बातचीत हुई, उन्होंने यह चीज शुरू की थी। तय हुआ कि माननीय अध्यक्ष के सामने हमलोग मिल कर बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय अस्वस्थ हैं और चूंकि २ दिन बाद ४ दिन की छुट्टी हो रही है उसके बाद बात कर लेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, लेकिन इधर जो कार्यवाही चल रही है, उसमें इतना संकुचित दृष्टिकोण कभी कभी हो जाता है कि एजेंडे पर रखना चाहते हैं तो नहीं आते। तो यह चीज तब तक के लिये कम से कम रोकी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी दो दिन ऐसी ही व्यवस्था चलेगी, उसके बाद फिर तय होगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, आज के एजेंडे में सिंचाई विभाग से संबंधित जितने प्रश्न हैं वह प्रायः सब स्थगित हैं---एक या दो को छोड़कर और जैसा कि नरसिंहनारायण जी ने कहा अब तक परम्परा यह थी कि प्रश्न पहले के दिये जाते थे, १-१ सौ एक दिन में आये हैं। और तीन प्रश्न नियमतः लिये जाते थे एक सदस्य के लेकिन किसी दिन ७ सवाल, किसी दिन ९ सवाल आज कल यही देखने में आ रहा है और सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

कम प्रश्न आने की यह वजह नहीं है कि कोई नयी बात हो गयी है। दो चार दिन में ही आप देखेंगे कि एक सौ से ऊपर प्रश्न आयेंगे। इसकी वजह यह है कि नये सत्र के शुरू में २० दिन की नोटिस होती है तो २० दिन के बाद शुरू हुए। बहुत लोगों के प्रश्न लैप्स हो गये और बहुत लोगों ने नोटिस कम दिया। इसके अलावा रामसुन्दर जी से बात हो गयी है और छुट्टी के बाद हम सब मिलेंगे उसी वक्त माननीय अध्यक्ष के सामने यह प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेंगे और जैसा तय होगा वह किया जायगा।

श्री कल्पनाथसिंह---

पहले यह नहीं होता था। अब कार्यवाही विभाग ने यह बात लिख कर भेज दिया हम लोगों के पास कि ३ से अधिक प्रश्न होने के नाते ये प्रश्न अस्वीकृत किये गये। अगर आप कहें तो आपके पक्ष में लिखित सूचना आपके सामने रख सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो ६-७ महीने से चला आ रहा है। ठीक है, आप रामसुन्दर जी के साथ आ जाइये, आपका समाधान हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

कल तय हुआ था कि २१ फरवरी के पहले माननीय अध्यक्ष से बात हो जायगी और आज फरमा रहे हैं कि छुट्टी के बाद होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आप जानते हैं कि उनकी तबियत अच्छी नहीं है। २८ को व पहली को उनसे बात हो जायगी।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकार माननीय अध्यक्ष ने तो सुरक्षित नहीं कर रखा है कि आप निर्णय ले ही नहीं सकते। आप नियम ५२ के प्रस्ताव और कामरोको प्रस्ताव सभी पर निर्णय लेते हैं तो आपको तो पूरा हक है, फिर इसमें विलम्ब करने का क्या कारण है। मेरा नम्र निवेदन है कि जो निर्णय लेने में अधिक विलम्ब करके माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जाइये । मुझे प्रश्नों के बारे में पावर्स डेलीगेटेड हैं । उसका जैसा मैंने इंटरप्रीटेशन लगाया उस हिसाब से मैं चल रहा हूं । उस पर चूंकि कुछ माननीय सदस्यों को आपत्ति है तो उसको देख लिया जायगा कि कौन सा इंटरप्रीटेशन सही है । मेरा इरादा कतई माननीय सदस्यों के अधिकारों पर हस्तक्षेप करने का नहीं है । स्पीकर कान्फ्रेन्स में भी यह प्रश्न उठा था कि प्रश्नों के बारे में कुछ ऐसा नियंत्रण किया जाय कि उनकी संख्या सैकड़ों तक न पहुंचे । लोक सभा में ३० से अधिक प्रश्न एजेन्डे में नहीं आते । अब आप सबकी बातों पर विचार होगा । उसके लिये जो तारीख होगी वह आपको बता दी जायेगी, आपको उसके लिये बात करने का मौका मिलेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय–

एक तरफ आप कहते हैं माननीय अध्यक्ष के सामने मामला जायेगा, दूसरी तरफ लोक सभा का उदाहरण दे रहे हैं .....

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप बार-बार सवाल पर सवाल करते जायेंगे तो मुझे ऐसा ही कहना पड़ेगा, आप उसे उसी वक्त लाइये, अभी नहीं ।

१९६३–६४ के आय-व्ययक पर सामन्य विवाद (क्रमागत)*

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, कल मैं कह रहा था कि जो बजट पेश हुआ है, उसमें आन्तरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के लिये कोई कदम आगे नहीं उठाया गया है । हमारे पुलिस उप मंत्री, माननीय नवलकिशोर जी ने एक माननीय सदस्य को चैलेन्ज किया है कि वे उनका रिकार्ड्स पुलिस से मंगवायेंगे । इस संबंध में मैं चन्द बात कह कर दूसरी बात कहूंगा । वे क्यों माननीय रामसुन्दर पांडेय जी का ही केवल चरित्र रिकार्डस मंगवायेंगे ? आज रामसुन्दर पांडेय जी जिस जगह पर हैं आज से कुछ दिन पहले माननीय सी० बी० गुप्त भी उसी जगह पर थे और आपके सबसे बड़े राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, जिनके हाथ में आज बागडोर है, भी उसी जगह पर थे । माननीय गेंदासिंह जी को शायद याद होगा कि उस समय मार्श स्मिथ और हैलेट ने पंडित नेहरू के बारे में क्या राय कायम की थी ? आप उसे भी मंगा कर देखिये । आपका पुलिस इंस्पेक्टर हमारे बारे में क्या राय देगा ? उस समय जो लोग उनको माला पहनाते थे वे उधर बैठे हुये हैं, जिन्होंने थाने पर हमला किया था, कुछ कार्य किया था, इधर बैठे हुये हैं । उस समय तो सभी को चोर आदि बनाया गया । इस तरह से हमारी देशभक्ति को चैलेन्ज न किया जाय । आप पुलिस मंत्री हो गये, तो कोई बड़े भारी देशभक्त नहीं हो गये । आप अपनी तरफ वालों के भी रिकार्ड्स मंगवा कर देखें । आप सी० बी० गुप्त के बारे में भी, स्वतंत्रता के पहले का रिकार्ड मंगवाकर देखें आपको पता चल जायगा ।

अब मैं आन्तरिक सुरक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं हमारे सभी साथियों ने कहा कि होम फ्रन्ट की लड़ाई मजबूत होनी चाहिये । आप कहते हैं कि शिकायत न करिये इससे मनोबल घटता है । लेकिन अगर आप लोकतंत्र की रक्षा के लिये मजबूत कदम उठायेंगे तो किसी प्रकार भी किसी सदस्य के यहां कुछ शिकायत करने से मनोबल गिर नहीं सकता । आप अपने विभागों को देखते हैं कि नहीं उनमें क्या हो रहा है ? आपका एक सप्लाई विभाग है। उसमें क्या क्या नहीं होता ? इस गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वे देश की क्रीम हैं । वे सम्मानित सदस्य हैं, चुन कर आये हैं इसलिये उनको अपना व्यवहार भी वैसा ही सम्मानित करना चाहिये ।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मेरा कितना समय बाकी है ।

---

*१८ फरवरी, १९६३ की कार्यवाही से ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ९ मिनट कल बोल चुके थे, ६ मिनट में से आज ४ मिनट बोल चुके हैं, २ मिनट अब आपके बाकी हैं ।

श्री उमाशंकर—

श्रीमन्, तारतम्य मिलाने के लिये मुझे एक मिनट और दे दिया जाय । आपकी पूर्ति विभाग की दुकानें खुली हुई हैं । प्राइवेट दूकानों और सरकारी दूकानों में कुछ फर्क तो होना ही चाहिये । मगर विशेषता क्या है ? सड़ा अनाज इन दूकानों से दिया जाता है । यह वह गल्ला है । इसको माननीय खाद्य मंत्री जी और पत्रकार महोदय देख लें । पूर्ति विभाग के भंडारों की कोई एक बोरी पर एक रुपया देता है, तो उसको अच्छा गल्ला दिया जाता है लेकिन जो एक रुपया नहीं देता है उसको गल्ला खराब दिया जाता है । सरकारी दूकान को तो एक आदर्श दूकान होनी चाहिये ।

ईंटों के भट्ठे आजमगढ़ में खोले गये हैं । जितने नये भट्ठों के लाइसेंस दिये गये हैं, उनमें से हर भट्ठे वाले से ५००–५०० रुपया वसूल किया गया है । आपकी पुलिस के और सी० आई० डी० के बड़े से बड़े अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, क्या उनको यह बात मालूम नहीं है ? यह आन्तरिक सुरक्षा का नमूना है । अगर इस प्रकार से परेशान किया जायगा तो किस प्रकार से लोकतंत्र चलेगा हम लोग तो अल्पमत में हैं, हम तो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा हो जिससे हमें बोलने और लड़ने का अवसर मिल सके । ब्लाक डेवलपमेंट आफीसर एक गजटेड आफीसर हैं वह किसी आदमी के लिये रिकमेंड करता है कि अमुक आदमी के पास पहले भी भट्ठा रहा है, इसको दिया जाय, सप्लाई आफीसर उसको नहीं मानता और अपने आफीसर को जांच के लिये भेजता है जो घूस खाता है । इसके बारे में मैंने जिलाधीश आजमगढ़ को लिखित दिया । इतना मैं मानता हूं कि आजममगढ़ के कलेक्टर लोकतंत्र की इज्जत करने वाले हैं, ऐसे कलेक्टर बहुत कम होते हैं । लेकिन एक चना क्या भाड़ को फोड़ सकता है ? यहां जितने भी छोटे कर्मचारी और आफीसर बैठे हुए हैं वे एक न एक मंत्री के पीछे लगे हुए हैं । यह दिक्कत हमें रोजाना आती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष भर में सदन के सामने यह बजट का एक ऐसा मौका आता है, जब कि सरकार ने इस पिछले वर्ष में क्या क्या काम किया है, हम उसमें क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं, सरकार ने जहां गलती की हो उन गलतियों को बतलाया जावे और जहां ठीक काम किया हो उसे भी बतलाया जावे । आने वाला जो साल है, चूंकि अभी शुरू हो जायगा, उसके लिये हम क्या विशेष परिवर्तन इस बजट में चाहते हैं, उसके लिये हमें सुझाव देना बहुत आवश्यक होता है और इसलिये जैसा कि हमारे नेता विरोधी दल ने कहा था कि यह समय विरोधी दल के सदस्यों के लिये अधिक उपयोगी है और उनके लिये अधिक समय की आवश्यकता होती है । लेकिन कल और आज जो अभी भाषण हुये, उन्हें सुन कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ सदस्य गवर्नमेंट की आलोचना तो करना चाहते हैं लेकिन वह आलोचना इतनी एक पक्षीय है कि हमें गवर्नमेंट की बुराई दिखलाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया केवल उन बातों को ही बतलाते हैं लेकिन गवर्नमेंट ने जनता के लिये क्या क्या अच्छा काम किया, उस तरफ हम लोग एक शब्द भी नहीं कहना चाहते हैं । और इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माननीय सदस्य एक पक्षीय आलोचना करके न अपने आपको संतुष्ट कर सकते हैं और न मैं यह समझता हूं कि अपने विचार से दूसरे लोगों के विचारों में कोई परिवर्तन ही कर सकते हैं ।

जहां तक सुझाव देने का संबंध है, बड़े ध्यान से मैंने माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को सुना और अन्य माननीय सदस्यों को भी सुना । एक बात बड़े जोर से कही गयी है कि गरीबों से, किसानों से टैक्स वसूल करने की कोशिश की जाती है, मिल मालिकों से नहीं, उन पर रियायत की जाती है । मैं नहीं जानता कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात की गयी है । जहां तक

मिल मालिकों का संबंध है, यदि सरकार को उन लोगों के साथ रियायत ही करनी होती तो उन पर टैक्स ही क्यों लगाया जाता ? यदि उन पर रियायत करनी होती तो वसूली में जो सख्ती की जाती है या उनके विरुद्ध जितनी कार्यवाही की जाती है, वह क्यों की जाती ? इसलिये हमें यह मान लेना चाहिये कि सरकार किसी के साथ रियायत नहीं करती ।

हां, एक बात जरूर है कि न्यायालय खुला हुआ है, वहां कोई भी आदमी जा सकता है, रिट लगाया जा सकता है, दूसरी ओर ऐसी कानूनी पेचीदिगियां हैं जिनको पैदा करके वे रियायत ले सकते ह । और उस रियायत में अगर गवर्नमेंट किसी तरह से हस्तक्षेप करे, किसी तरह की और कोई बात उठावे तो फिर गवर्नमेंट के खिलाफ यह कहा जाता है कि सरकार अदालती कामों में भी दखलन्दाजी करती है । यहां पर कई बार यह बात सुनने में आयी विरोधी दल के माननीय सदस्यों की तरफ से कि सरकार अब अदालतों के कामों में भी हस्तक्षेप करने लगी है और अगर सचमुच किसी को थोड़ी सहूलियत देने की बात की जाय या थोड़ी बहुत दखलन्दाजी की जाय, तो न मालूम कितनी आलोचना और प्रत्यालोचना सरकार की की जा सकती है । इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि नुक्ताचीनी करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन एक बात को ध्यान में रख कर ही नुक्ताचीनी करनी चाहिये कि काश, हम सरकार में हों और हमें सरकार का इन्तजाम करना हो तो हम किस तरह से अपने कार्य का संचालन करेंगे । हमारे यहां मनुस्मृति में स्पष्ट यह तरकीब बतायी गयी है कि हमें उस तरह की आलोचना नहीं करनी चाहिये । जिस आलोचना को हम खुदबर्दाश्त नहीं कर सकते या जिस आलोचना पर हम खुद नहीं चल सकते । इसलिये विरोधी दल के सदस्यों से मेरी यह करबद्ध प्रार्थना है कि आलोचना चाहे जिस प्रकार की जाय लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि यदि आप सत्तारूढ़ हों, आपके ही हाथ में शासन हो तो क्या आप उन बातों को निभा सकते हैं या नहीं ।

इस बजट के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और मैं यह अनुभव करता हूं कि इस समय हमारे प्रदेश के लिये जिन बातों की आवश्यकता थी, उन सभी बातों की ओर माननीय वित्त मंत्री जी ने ध्यान दिया है । और इस तरह उन्होंने यह प्रयत्न किया है कि कोई भी ऐसी बात बाकी न रह जाय जिससे प्रदेश में किसी प्रकार की दिक्कत या मुसीबत हमारे सामने आये । उदाहरण के लिये मैं यह कह सकता हूं कि यहां पर चीन के आक्रमण की बहुत चर्चा हुई कि हमारी सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, इस संबंध में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक लड़ाई का संबंध है उसके लिये जहां हम सब को उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये, वहीं पर इसकी मुख्य जिम्मेदारी हमारी केन्द्रीय सरकार की है और केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या किया । आज मैं उन बातों के बारे में नहीं कहूंगा, केवल इतना कहूंगा कि प्रदेश में इन दिनों में सुरक्षा के कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आई । कहीं पर भी कोई भी यह नहीं कह सकता है कि चीन के आक्रमण से किसी को खाने के लिये गल्ला न मिला हो या कहीं पुलिस के कार्य में ढिलाई आई हो या आपस में किसी के द्वारा एक दूसरे को तंग किया गया हो, लूटमार की गई हो । यह जिम्मेदारी हमारी प्रादेशिक सरकार की थी और हमारी सरकार ने उसको बहुत अच्छी तरह से निभाया और इस ढंग से निभाया कि जिसे देखकर हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि इन दिनों प्रदेश में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसको देखकर कहा जा सके कि आपातकालीन स्थिति में सरकार ने उस संबंध में अनुकूल आचरण नहीं किया । जहां तक आगे की योजनाओं की बात है इन सब चीजों के लिये बजट में प्राविजन किया गया है । ग्रामीण रक्षादल की योजना है, पुलिस पर व्यय बढ़ाया जा रहा है और उसके साथ साथ प्रान्तीय रक्षा दल और जो दूसरी संस्थाओं रक्षा के लिये हो सकती हैं उन सब का गठन करने के लिये धन राशि रखी गई है और सबसे अच्छी बात यह की गई है कि उन सबका इस प्रकार से संगठन किया जा रहा है कि जिससे जनता का उनमें ज्यादा हाथ रहे और प्रदेश के लोग यह समझें कि जो कुछ हो रहा है वह हमारे द्वारा और हमारे लिये किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के लिये यह बहुत आवश्यक चीज है ।

इसके साथ साथ अगर हम बजट के सारे आइटम्स को देखें तो मानना होगा कि जहां तक हमारे बजट का संबंध है, अगर हम योजना के आइटम्स को निकाल दें तो हमारे बजट में लगभग

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

१२ करोड़ से ऊपर का लाभ होता और योजना को छोड़कर अगर सूबे का हिसाब देखें तो बचत ही होनी चाहिये ताकि वह योजना में व्यय हो सके । उधर के विरोधी सदस्य प्रायः कहा करते हैं कि कहीं पर भी बचत की कोशिश नहीं होती और कटौती व्यय में नहीं होती ताकि सामान्य प्रशासन के व्यय में कमी की जा सके परन्तु अब हमें प्रसन्नता होनी चाहिये कि हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने करीब सवा करोड़ रुपये के बचत की है और बजट भाषण को देखने से मालूम होता है कि वह आगे भी इस दिशा में प्रयत्नशील रहेंगे और वह चाहते हैं कि जहां तक संभव हो हम आवश्यक कटौती करके जो कुछ भी धनराशि बचे उसे हमें अपनी योजनाओं में व्यय करना चाहिये । इस साल में करीब ८५ करोड़ रुपया योजनाओं के लिये है और अगले वर्ष के लिये यह कहा जा सकता था कि प्रयोजनाओं में कुछ कटौती होगी लेकिन नहीं, इस वर्ष से ज्यादा माननीय वित्त मंत्री जी ने करीब ९२ करोड़ की राशि रखने का प्रयत्न किया है । यदि यह आपातकालीन परिस्थिति न होती तो यह राशि १०२ करोड़ की हो सकती थी लेकिन उस स्थिति के होते हुये भी कोई विशेष कटौती नहीं हुई है और ज्यों की त्यों धनराशि रखने का प्रयत्न किया गया है । सब प्रयत्न करने के बाद हमें करीब ५ करोड़ का घाटा रहेगा । जैसा मैंने कहा यह प्रयत्न माननीय वित्त मंत्री जी का रहेगा और यही इस वक्त तक रहा है कि यह जो हमें घाटा पड़ रहा है ५ करोड़ का इसको पूरा करने के लिये अगर जरूरत होगी तो नये टैक्स लगाये जायेंगे । लेकिन मंत्री जी प्रयत्न यही कर रहे हैं कि नये टैक्स न लगें और ५ करोड़ का घाटा पूरा हो जाय ।

कई सदस्यों ने कहा कि यह बजट पुराने ढांचे पर ही बना है । यह बात ठीक है । लेकिन एक बात जानना चाहता हूं कि समाजवादी सिद्धान्तों को मानने वाली सरकार में हर साल कोई नई बातें थोड़े ही होंगी । उदाहरण के लिये पुलिस, शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, योजना, चिकित्सा आदि बातों को छोड़ कर क्या और कोई नये आइटम्स लिये जाये । ये सब बातें होती ही रहेंगी और इन पर जो इस साल व्यय हो रहा है अगले साल उन पर ज्यादा खर्च निश्चित होगा । जहां तक नई बातों का संबंध है सरकार ने आपात स्थिति को देखते हुए नई योजनाओं को सामने रखा है । लेकिन एक दिक्कत सरकार की है और वह यह है कि नयी योजनाओं के लिये नये टैक्स चाहिये । लेकिन जिस समय किसी नये टैक्स की बात होती है तो उसका विरोध किया जाता है । मैं समझ नहीं पाता जब हम चाहते हैं कि नई योजनायें आयें तो नये टैक्सों के लिये भी तैयार रहना चाहिये । एक बात हमेशा कही जाती थी कि हम तैयार हैं नये टैक्स लगें लेकिन फजूल खर्ची न हो । जैसे पहिले भी कहा जा चुका है कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके कामों में किसी तरह की फजूल खर्ची हो । यह तो एक मान्यता का प्रश्न हो जाता है कि एक आदमी जिसको १,००० रुपया मिलता है वह समझता है उसका गुजारा नहीं हो रहा है, १०० रुपये पाने वाला आदमी भी यही समझता है । तो आखिर को असली किफायतशारी कहां है । जिस आदमी की जितनी तनख्वाह होती है उसके अनुरूप ही उसका खर्च भी बढ़ जाता है । और अगर कहीं सरकार किसी प्रकार के कटौती करती है और सुरक्षा आदि में न्यूनता आ जाय तो कहा जाता है देखिये वहां पर गलत ढंग से आदमियों को हटाया है । अभी प्रश्नों के समय बराबर यही पूछा जा रहा था कि क्या रिटायर होने की उम्र ५५ से ५८ वर्ष बढ़ायी जा रही है । मैं समझता हूं कि यह हम मान करके चलें क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ५५ से ५८ साल किया है हमारे यहां भी सरकार इस बात को जरूर करेगी । उस समय हम यह भूल जाते हैं कि आखिर इससे खर्चा बढ़ेगा या कम होगा । जहां हमें कोई नई बात कहनी होती है तो सरकार से कहते हैं कि सरकार को इस विषय में जरूर खर्च करना चाहिये, लेकिन वहां हम यह भूल जाते हैं कि जहां हम समझते हैं यहां खर्च करना जरूरी है वहां जो आदमी सरकार में बैठे हैं उनकी राय में कहीं और खर्च करना जरूरी है और वह अपनी राय से खर्च करेंगे, यद्यपि राय सबकी सुनेंगे, लेकिन सोलह आने उनकी बात पर अमल करना संभव नहीं हो सकता । अतः मैं विरोधी दलों के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि समालोचना अच्छी चीज है और इस मौके पर जरूर करनी चाहिये । लेकिन नुक्ताचीनी इस तरह की हो कि जब आपके हाथ में सत्ता होगी तो आप उन बातों को निभा सकेंगे या नहीं । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण को जिस लहजे में रखा है मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मगर इतना कहने का साहस रखता हूं कि माननीय मंत्री जी ने उसमें अपने बनारस की परम्परा का निर्वहन नहीं किया है। श्रीमन्, आप जानते हैं वाराणसी, काशी वह स्थान है जहां सब का विरोध कर के महात्मा बुद्ध ने अपना अमर संदेश दिया बुद्ध धर्म का, और शंकराचार्य ने बड़ी तेजी से उनके बुद्ध धर्म को काटा और जितने उस शंकरपुरी के बड़े देव, महात्मा और विद्वान हुये हैं उन्होंने बड़ी प्रखरता और कठोरता के साथ सत्य को कहा। माननीय वित्त मंत्री के भाषण से मैं दो, तीन स्थल सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण में एक जगह कहा है :

" . . . .उस समय हम में से कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि निकट भविष्य में हमारे पावन देश की पवित्र सीमा एक ऐसे देश द्वारा आक्रान्त होगी जिससे हमारा सांस्कृतिक मैत्रीपूर्ण संबंध सहस्त्राब्दियों से रहा है . . . . . ।" फिर मंत्री जी आगे कहते हैं :

"फलतः हम स्वीकार करते हैं कि यह हमारी कल्पना और हमारे अनुमान से परे था कि हमारी मातृभूमि का धवल-मुकुट, नगाधिराज वह हिमालय, जो युग युग से शांति और साधना का प्रतीक रहा है विदेशियों से पदाक्रांत हो कर, भीषण रण-भूमि में परिवर्तित हो जायगा ।"

मैं माननीय मंत्री जी की खिदमत में एक किताब पेश करना चाहता हूं जिसका नाम है "भारत-चीन संबंधों की मुख्य घटनायें १९४७–१९६२"। यह भारत सरकार की किताब है और इसमें १५ अगस्त, १९४७ से लेकर १० मई, १९६२ तक कब कब चीनियों ने भारत भूमि को आक्रान्त किया है। माननीय मंत्री जी के दिमाग में शायद यह है कि चीन का यह हमला अभी हुआ है। इसमें लिखा है कि बाराहोती में जून, १९५५, दमजान में १५ सितम्बर, १९५५, शिपकीला में १ तथा २० सितम्बर, १९५६, हाट स्प्रिंग में अक्तूबर, १९६० और डम्बु गुरु में अगस्त, १९६१ में चीनियों ने घुसपैठ की। यानी १२ जुलाई, १९६२ तक लगातार चीन के हमले हुये ह। मैं बाराहोती का प्रश्न उनकी खिदमत में रखना चाहता हूं। इसी विधान सभा में जब बाराहोती का प्रश्न उठाया गया था तो वाराणसी के मुख्य मंत्री माननीय सम्पूर्णानन्द ने क्या कहा था उस पर मैं मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह ३० दिसम्बर, १९५९ की उत्तर प्रदेश की विधान सभा की कार्यवाही है। उसमें माननीय सम्पूर्णानन्द ने कहा है : "यहां पर बाराहोती का जिक्र किया गया है। वह बाराहोती हमारा है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। लेकिन चीन की तरफ से बराबर कोशिश होती रहती है कि वहां पर किस तरह से कब्जा किया जाय। एक तरह से घुढ़दौड़ रहती है कि कौन वहां पर जल्दी पहुंच जाय और जाकर कब्जा करे।" उन्होंने ऐसा ही १ सितम्बर, १९५९ को भी कहा है। और उसी बाराहोती को हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने कोलम्बो प्रस्तावों को मान कर संदिग्धावस्था में छोड़ दिया। मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की भूमि और उसकी आजादी पर माननीय प्रधान मंत्री के रहते और उनके शासन काल में हमला हो विदेशियों का और माननीय प्रधान मंत्री बाराहोती को संदिग्धावस्था में छोड़ दें जबकि यहां के मुख्य मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बाराहोती हमारा है। हमें दुःख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा।

एक बार जब मुख्य मंत्री जी पिथौरागढ़ के दौरे पर गये थे तो उन्होंने कहा था कि हम चीनियों को तिब्बत पार खदेड़ देंगे। इस पर हमारी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से उनको बधाई दी गयी थी लेकिन यहां आ कर फिर न मालूम क्यों बदल गये। यह बड़ी संदिग्धावस्था है। केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री हैं माननीय जगजीवनराम। चन्द्रवरदाई की परम्परा इस देश में चल पड़ी है। यह बड़ी खराब परम्परा है अब वह स्थिति आ गयी है। उधर हमारी निगाह नहीं जा रही है। माननीय जगजीवनराम जी ने बिहार में कहा कि हमको दो "ग" और एक "न" चाहिये। हमको गन, गल्ला और नेहरू चाहिये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के मंत्री ऐसी बात कहें। यह कैसी परम्परा है? मैं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से पूंछना चाहता हूं कि यद्यपि इंगलैंड ने चर्चिल की मदद से लड़ाई जीती लेकिन

[श्री उग्रसेन]

क्या कोई बता सकता है कि किसी भी मंत्री ने वहां पर बर्फिल की तारीफ की। यह कौन सी परम्परा चलाई जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां पर आज जो नेहरू बचाओ अभियान चल रहा है उससे मुल्क कतई नहीं बच सकता है। बाराहोती चला जायगा, तकलाकोट चला जायगा और बदरीनाथ पर भी हमें खतरा नजर आ रहा है, अगर इसको आंखों से ओझल करेंगे तो मुल्क की आजादी बच नहीं सकती है। इसलिये मैं कहता हूं कि आज आवश्यकता है कि हिमालय बचाओ, देश को बचाओ न कि नेहरू को बचाओ या गुप्ता को बचाओ अभियान चलाओ। अगर चलाओगे तो मुल्क बरबाद हो जायगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तो हमें यह संकल्प लेना है। इतिहास साक्षी है कि हिमालय स्वतंत्र और भारतवर्ष का भाई है। मैं संकल्प करता हूं कि भारत सरकार इसके बचाने के लिये जो भी प्रयत्न करे मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान को १५ अगस्त, १९४७ की आजादी मिले और तिब्बत आजाद हो। हमने अपने घोषणापत्र में भी कहा था कि अगर तिब्बत को आजादी मिलती है तो हिन्दुस्तान और तिब्बत की सीमा मैकमोहन लाइन होनी चाहिये। अगर तिब्बत गुलाम होता है तो हमारी सीमा कैलास और मानसरोवर झील के साथ साथ पूर्ववाहिनी सांगपों होनी चाहिये। माननीय वित्त मंत्री जी तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। हिमालय की गरिमा के संबंध में मैं एक आध वाक्य पढ़ देना चाहता हूं :—

"कैलास, मानसरोवर, बदरीनाथ, केदारनाथ, अमरकंटक आदि हिमालय की सुविस्तृत विपुल पर्वतमालायें भारतवर्ष की केवल भौगोलिक सीमायें नहीं हैं, और न वे हमारी राजनीतिक वैभव के केवल प्रहरीमात्र हैं। वे हैं उससे भी अधिक हमारी विराट आध्यात्मिक एवं अधिदेव संस्कृति के महान् साक्षी। इसी की शांत कन्दराओं में एवं उपत्यकाओं में ऋग्वेद से लेकर आज तक अविच्छिन्न रूप से हमारी कला, साहित्य एवं दर्शनों का वर्चस्व विकसित हुआ है। चाहे वे वेद, उपनिषद् और पुराणों के मानने वाले हों, इसके चरणों में अपना सिर झुकाया है। इसी हिमालय के पृष्ठ भाग पर कैलास पर्वत है जहां श्रीमान् महाराज धिराज कुबेर अपने समस्त गंधर्व गुह्यकों के साथ निवास करते थे। आज भी वहीं हमारे देवाधिदेव शिव हैं, जिनके मंदिर की घंटा ध्वनि को सुनने के लिये भारतीय आत्मायें आजीवन लालायित रहती हैं। उसी के समीप एक दिव्य सरोवर है, जहां अनादि काल से देवलोक के समस्त अजर अमर देवता, गंधर्व एवं सिद्ध स्नान किया करते हैं। इसी पर्वत से लोक पावन सरयू प्रसावित होती है। आगे चलकर कांचन वर्ण का एक सुविशाल पर्वत मिलता है।" क्या कमलापति त्रिपाठी जी इस भागीरथ पर्वत को भूल जायगें जिस भागीरथ ने वाराणसी का ही कल्याण नहीं किया बल्कि हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक कल्याण किया है।

श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधान मंत्री जी और गुप्ता जी के राज्य में इस हरे पर्वत का क्या हो रहा है? कैलास पर्वत कहां गया? मानसरोवर कहां गया? आज मानसरोवर झील में जहां पहले हंस चला करते थे, चीन के छोटे छोटे जहाज उतर रहे हैं। चीनियों को यहां पर हवाई पट्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज मानसरोवर झील में चीनियों की पनडुब्बी उतर रही हैं हमको गुलाम बनाने के लिये, हमारी संस्कृति, हमारी आजादी को नष्ट करने के लिये और आपके गुप्ता जी के और बनारसीदास जी के दौरे हो रहे हैं। मुझे इस पर हंसी आती है कि इनके दौरे हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारा कितना हिस्सा दुश्मन के हाथ में चला गया यहां तक कि वैलोंग भी चला गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वे आगे बढ़ते और तेजपुर चला जाता तो लखनऊ, कानपुर आने में उनको कितनी देर लगती। मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूं कि आपने शंका की कि चीनी हमारे मनोबल के कारण जो जगह जगह पर प्रकट हो रहा है, डर कर भाग गये हैं। वे इसलिये भाग गये हैं कि उन्हें इतनी दुविधा वाला प्रधान मंत्री मिला और उन्हें यह शक हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि जनता प्रधान मंत्री को हटा न दे। मैं सवाल करना चाहता हूं कि उसने भूटान पर नेपाल पर, बरमा पर क्यों नहीं हमला किया इस लिये कि सीटी नैटो में चले जाते। मगर

वाहरे द्विधा का प्रधान मंत्री। लड़ाई हारने का एक कारण था —इस देश की सरकार और इस देश के प्रधान मंत्री की द्विविधा। जब तक इस देश में ऐसे प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री रहेंगे तब तक क्या होगा। मैं आपसे कहता हूं कि देश बचाइये, हिमालय बचाइये। इसके लिये आप हमारी अगुवाई करें। हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला कर चलेंगे। आप को मैं जो आप सोये हुये हैं जगाना चाहता हूं। मैं चन्द्रबरदाई के उस अंश को जरूर मानता हूं। पृथ्वीराज संयुक्ता के साथ रंगमहल में मस्त था। चन्द्रबरदायी प्रचार करके पृथ्वीराज को रणस्थली में लाये। मथुरा में कितने कितने भद्दे गाने रंडियों से गवाये गये। मैंने सुना कि नेफा में सिपाहियों का मनोरंजन करने के लिये फिल्म स्टार्स गये थे। अगर मेरा बस चलता तो मैं दिलीपकुमार, देवानन्द और सुरइया से कहता कि जाओ मंत्रियों का मनोरंजन करो जा कर, नेफा के मोर्चे पर तुम्हारी जरूरत नहीं है।

यह सरकार कहती है कि सुरक्षा कोष में चन्दा दो। देवरिया में बाराबंकी में त्रिवेदीगंज को बिलकुल लूट लिया। गोरखपुर में फरेंदा तहसील के तहसीलदार ने वहां के व्यापारियों को बिठा कर २५ हजार रुपया लिया। और कितना वसूल हुआ? केवल ४१ करोड़। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दिन का खर्चा है ११ करोड़। सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण जी ने कहा कि आधा खर्चा कम कर दो साढ़े पांच करोड़ रोज बचेगा। ४१ करोड़ पाये हैं। चार दिन सरकार चलने का खर्चा पाये हैं। जब मध्य एशिया में लड़ाई चल रही थी तो एक दिन का ४० करोड़ रुपया खर्चा हुआ करता था। बहुत शोरे सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरए खूं भी न निकला। क्या हुआ चार दिन का भी सरकार का खर्च नहीं दे पाये। मैं आप को सुझाव देता हूं माननीय नवलकिशोर जी। चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण कीजिये। सम्पूर्णानन्द अवार्ड को नहीं मान रहे हैं। मिल मालिक चाहते हैं उसका उतना ही अंश माने जो मिल मालिकों के फायदे के लिये हो। ४५ हजार मजदूर हल्ला कर रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। कपड़े की मिलों का राष्ट्रीयकरण कीजिये। हम आपको अरबों दे रहे हैं। तब आप देश की रक्षा कर सकते हैं। इस सरकार के लिये शर्म की बात है कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर कलेक्टर से बी० एल० डब्लू तक सिवा इसके कोई काम नहीं है कि सुरक्षा कोष के लिये चन्दा मांगे लेकिन फिर भी केवल ४१ करोड़ इकटठा कर सके।

द्वितीय सुरक्षा पंक्ति का बड़ा शोर सुनते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि द्वितीय सुरक्षा पंक्ति कैसे खड़ी होगी। होम गार्ड से वह नहीं खड़ी होगी प्रान्तीय रक्षक दल से नहीं खड़ी होगी द्वितीय रक्षा पंक्ति का मतलब यह है कि पहाड़ के लोगों को गुरिल्ला युद्ध के लिये ट्रेनिंग दीजिये। दूसरे ऐसे नौजवानों को ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाय कि जब फौज के लोग लड़ें तो उनकी जगह ले सकें। यह दो ही नियम, दो ही उद्देश्य द्वितीय रक्षा पंक्ति के होते हैं। अब एन० सी० सी० के बारे में मैं आप को बताऊं। एन० सी० सी० की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश में ५० हजार आदमियों को दी गई और जब उनसे दरख्वास्तें मांगी गईं लड़ाई में जाने के लिए तो कुल ६४ आदमियों की दरख्वास्तें आयीं। तो यह हालत है। अभी उस दिन देवरिया में इनका इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था, मैं तो घबरा गया कि कहां से इतने कप्तान आ गये, पूछा तो मालूम हुआ कि एन० सी० सी० के हैं। तो ट्रेनिंग तो इतने आदमियों को आप दे रहे हैं और अगर उनसे पूछा जाय कि नेफा में जायेंगे तो कहेंगे कि हमको तो जरा लखनऊ के ही दफ्तर में रख दिया जाय। इसलिये जितनी यह एन० सी० सी० की कतार खड़ी कर रहे हैं, जितने होम गार्ड तैयार कर रहे हैं, जितने प्रान्तीय रक्षा दल खड़ा कर रहे हैं, सबसे आप एक बांड भरवाइये कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको लड़ाई के मोर्चे पर जाना पड़ेगा। तब गुप्ता जी के रिश्तेदार के रिश्तेदार, नाना के नाना के नाना, साले के साले के के साले उसमें नहीं रहेंगे। तब तो वह कहेंगे कि अरे राम राम, उसमें जाकर कट जाना पड़ेगा, लड़ाई पर जाना पड़ जायेगा। लखनऊ में ही रहना अच्छा है।

आप योजनायों की बातें करते हैं। आपकी योजनायें बेकारी लाने वाली हैं, रिक्शावालों की तादाद बढ़ाने वाली हैं, भुखमरी बढ़ाने वाली हैं, बीमारी बढ़ाने वाली हैं, इन योजनाओं में २४ सौ करोड़, ४८ सौ करोड़ और १२ हजार करोड़ यह सब बिलकुल बेकार जा रहा है। अक्सर

[श्री उग्रसेन]

मंत्री लोग खास तौर से मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम तो योजनाओं में लगे थे। सन् १९५० में चीन और हिन्दुस्तान दोनों मान्यवर, करीब करीब बराबर-बराबर इस्पात की पैदावार करते थे। उस समय चीन की इस्पात की पैदावार १० लाख टन थी और भारत की भी यही थी। सन् १९६१ में १७० लाख टन चीन की पैदावार हो गई और हिन्दुस्तान की रही ३० लाख टन। इसी तरह से कोयले वगैरह की भी है। तो वह भी उत्पादन कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है, कि आपकी प्लानिंग ऊपर से है और चीन की नीचे से है। जिस मुल्क की जनता भूखी है अज्ञान है, बीमार है, अज्ञान के अन्धकार में पड़ी हुई है, वह कोई दूसरी सुरक्षा की पंक्ति दे सकेगी, इसको माननीय मंत्री जी ही जाने और योजना में क्या है? प्रति व्यक्ति आमदनी ले लीजिए। एक खेत का मजदूर आठ आना रोज पाता है, १ रुपया भंगी पाता है और हमारे साहब लोग कितना पाते हैं? विलायत में ५ और ७ गुने का फर्क है लेकिन हमारे मुल्क में ३०० गुने का फर्क है। इतना फर्क दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। प्रति व्यक्ति आमदनी के कुछ आंकड़े श्रीमन्, मैं देना चाहता हूं—अमरीका में १,८५७ डालर प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी है, कैनाडा में १,२८४ डालर, स्विटजरलैंड में ९२७ डालर, ब्रिटेन में ७१५ डालर और भारत में ५ डालर। अमेरिका में १० हजार रुपया वार्षिक अगर एक व्यक्ति की आमदनी है तो वहां का राष्ट्रपति १२ हजार रुपया रोज खर्च करता है और यहां प्रति व्यक्ति आमदनी २८५ रुपया है तो यहां का प्राइम मिनिस्टर २५ हजार रुपया रोज खर्च करता है। यह है हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री मुगले आजम की शान और ठाट-बाट।

संकटकालीन स्थिति का बड़ा नाम लिया गया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुबे जी ने इसका नाम लिया। मैं दुबे जी से कहना चाहता हूं कि संकटकालीन स्थिति क्या है आज? जनसंघ की कार्यकारिणी ने भी प्रस्ताव पास किया है कि झूठे संकटकाल का हौवा सरकार ने बना रखा है। हां, कम्यूनिस्ट लोग कह सकते हैं क्योंकि उनके लिए जरूर संकटकालीन स्थिति है। बहुत से बेचारे बेगुनाह पकड़कर बन्द कर दिये जा रहे ह। बम्बई में जिसको पकड़ना होता था उसको कह देते थे "लाल बाउटा छै" और पकड़ लेते थे। उसी तरह से कम्युनिस्ट लोग आज पकड़े जा रहे हैं। बात भी ऐसी है कि जिसके ऊपर जरा भी शक हुआ कह दिया कि कम्युनिस्ट है और पकड़ लिया। अभी इधर उड़ीसा प्रान्त में सोशलिस्ट पार्टी के श्री कृष्ण पटनायक एम० पी० और ६ नेताओं को इसी तरह पकड़ लिया। तो इसीलिए इमर्जेंसी है कि गद्दी बरकरार रहे। इमर्जेंसी में कुछ खर्चा भी आपने कम किया है? क्या इमर्जेंसी है इसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस समय यहां पर गुप्त जी नहीं है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस कुर्सी पर बैठ कर रंगरेलिया मचाने की चेष्टा न करें। मैं उसके संबंध में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। जरा मुलाहिजा फरमायें "जरा आहिस्ता ले चल करवाने कैफ हस्ती को, किसतेह जेहन आलम सख्त नाहमवार है साकी"। गुप्त जी इस बात को समझते नहीं है कि यह मार्ग कितना कंटकाकीर्ण है। आज चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया है और करता जा रहा है लेकिन भारत सरकार के पास इसकी कोई योजना नहीं है। चीन आगे बढ़ आया है लेकिन कोलम्बो प्रस्ताव करते हैं कि १२,००० वर्ग मील के लगभग का एरिया और चीन के पास रहे। हमारे प्रधान मंत्री लोक सभा में इस बात का एलान करते हैं कि हम भारत की एक एक इंच भूमि से चीन को खदेड़ देंगे और निकाल कर दम लेंगे। बात समझ में नहीं आती है। मैं और क्या आपको बतलाऊं, इमर्जेंसी का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इमर्जेंसी का मंत्रिमंडल क्या है और उस पर क्या खर्च होता है। आप लोग जरा इस पर गौर फरमायें।

आज जो देश के अन्दर इमरजेंसी है उसमें जो इमरजेंसी कैबिनेट बनी हुई है उनको जरा आप देखें। पन्त जी के जमाने में सन् १९३७ में मंत्रिमंडल का खर्चा कुल ६६,२९९ रुपया था। फिर उनके जमाने में ही सन् १९४६ में वह खर्चा बढ़कर ९२,६०० रुपये हो गया। फिर उनके जमाने में ही सन् १९५० में वह खर्चा ४,९१,३०० रुपये हो गया। दिसम्बर, १९५४ में जब कि यहां सम्पूर्णानन्द जी का मंत्रिमंडल बना तो उसका खर्चा ६,५२,८०० रुपये हो गया। फिर उनके ही जमाने में सन् १९५७ में वह खर्चा ६,८१,७०० रुपये हो गया। अब आप गौर

फरमायें कि जब गुप्ता जी चोर दरवाजे से दिसम्बर, १९६० में पधारे हैं तो उनका कितना था और अब वह कितना हो गया है। सन् १९५७ में सम्पूर्णानन्द मंत्रिमंडल के जमाने में ६,८१,७०० रुपये खर्चा था लेकिन जब से गुप्त जी पधारे तो उनका खर्चा कितना हो गया इसको भी जरा देखने की कृपा करें, जब दिसम्बर, १९६० में इनका मंत्रिमंडल बना तो उसका खर्चा ४,७५,००० हो गया। पहले से वह खर्चा कम हुआ इसमें सन्देह नहीं लेकिन जब संकटकालीन स्थिति है तो उसका खर्चा केवल वेतन पर ३,६१,२०० रुपये हो गया है। मोटरकार का खर्चा १,२०,४०० रुपये हैं। उनके यात्रिक भत्ते के लिये १,९७,८०० रुपये का खर्च है। अब आज के जमाने में मोटर की क्या जरूरत है। अब तो एयर कंडीशन्ड डिब्बे हो गये हैं तो उनमें चल सकते हैं। मन्त्रियों को मोटर कार की क्या जरूरत है मगर उनके लिये मोटर कारों की खरीद की जाती है। और उस पर १,३०,५०० रुपये का खर्चा आया है। यह सब खर्चा ८,०९,९०० रुपये आता है। इनके लिये जो खर्चा आज हो रहा है और संकटकालीन स्थिति में इतना रुपया आज इस मंत्रिमंडल पर खर्च किया जा रहा है। यह इस इमार्जेन्सी के समय में मितव्ययिता है जिसके लिये कहा जाता है कि कम खर्च किया जा रहा है। इस खर्चे को पूरा करने के लिये ही कहा जा रहा है कि १८ करोड़ ४५ लाख के रुपये के टैक्स लगाने हैं। क्या इस योजना को पूरा करने के लिये ही मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि तीसरी योजना को पूरा करने के लिये हमको ४५ करोड़ रुपये के टैक्स लगाने पड़ेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप ५४ करोड़ रुपया तो मिल मालिकों से वसूल कर लीजिये जो उनके पास बकाया पड़ा हुआ है फजूल खर्ची को रोकिये और किफायत कीजिये।

मैंने एक किताब पढ़ी है उसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। उस किताब का नाम ब्रिटिश वार इकोनामी है। वह हैन्काक द्वारा लिखी गई है। वह किताब युद्ध कालीन अर्थ व्यवस्था के ऊपर लिखी गई है उसमें यह बताया गया है कि सन् १९१४ में जब कि मूल्यों का सूचकांक १०० था तो जनवरी सन् १९१५ में वह ११७ हो गया और जुलाई सन् १९१५ में वह ११५ हो गया यानी कुछ कम पहले से हो गया। फिर जुलाई १९२० में वही फिगर जो पहले ११७ था सन् १९१५ में वह १९२० में ३०८ हो गया और उसी जुलाई में २५२ हो गया यानी कम हो गया। फिर उसके बाद जनवरी, १९४० में वह फिगर १२८ हो गया और जुलाई में ११२ हो गया। उसके बाद सन् १९४० के मुकाबले में जनवरी १९४६ में वह फिगर १८० हो गया और जुलाई में १३२ हुआ। सन् १९१४ में जो वहां की अर्थव्यवस्था थी वह सन् १९४६ में आकर सुधरी। बीच के समय में कुछ दाम बढ़े लेकिन बाद को बहुत वहां की अर्थ व्यवस्था में सुधार हुआ। उनकी आमदनी भी इसी तरह से बढ़ा। सन् १९१४ में ११५ हुई, १९२० में २१५ और जनवरी, १९४० में १६३ और सन् १९४६ में १६१ हो गई। तो उन्होंने अपनी अर्थ व्यवस्था को इतनी अच्छी तरह से रखा। मैंने पढ़ा कि उन्होंने तमाम वैज्ञानिक कमेटियां बनायीं जिनका काम था कि हर विभाग के लिये सुझाव दें, साधन जुटायें, मसलन पशुपालन में किस तरह से ज्यादा दूध पैदा किया जाय, ज्यादा मक्खन लाया जाय, ज्यादा अंडे पैदा किये जायं। हर विभाग के लिये वैज्ञानिक कमेटी बनी। हमारे यहां भी रिसर्च होता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या कहीं भी वैज्ञानिक कमेटी बनी है। मैं समझता हूं नहीं है।

हमारी हार का एक कारण अंग्रेजी भी है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां की जनता दूसरी जबान बोलती हो और वहां की सरकार की दूसरी जबान हो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चीनी सिपाही और अफसर दोनों चीनी में बोलते थे, लेकिन हमारे सैनिकों को देख कर तामिल और तैलागू में या हिन्दी में आदेश देते थे धोखे में डालने के लिये। यह भी उन्हें किसी गोविन्द सहाय जी जैसे फेलों ट्रैवलर ने सिखायी होगी जो वहां पेकिंग में दावतें खाने जाते हैं। माननीय कृष्णनन्दजी को भ्रम है कि हम डर गये और डर कर मैनिफेस्टो में वैसी बात लिख गये। ऐसा नहीं है। उड़िया लोग उड़िया चाहते हैं, बंगाली बंगाली चाहता है, गुजराती गुजराती चाहता है, लेकिन केन्द्र से वह अंग्रेजी में बात करें यह क्या है। जो हिन्दी के केन्द्र हैं उनका कामकाज हिन्दी में हो और जब दूसरे हिन्दी में बात करने काबिल हो जायं तो वे

[श्री उग्रसेन]

उनके साथ आ जायेंगे। इसमें किसी को विरोध नहीं हो सकता। आपको देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी सार्वजनिक रूप में करनी होगी और यह जबतक आप ५० लाख से अंग्रेजी को नहीं हटाते, यह नहीं हो सकता। आज साढ़े ४२ करोड़ जनता पर यह अंग्रेजीदां, ज्यादा आमदनी वाले, चन्द कुर्सियों पर बैठे हैं और हम पर, हरिजनों पर, रामप्यारे जी पर शासन कर रहे हैं। मैं आज उनको खोज रहा था। वे इस समय नहीं मिलेंगे। ५,००० वर्ष से यह हरिजन दबे हुए हैं। सोशलिस्ट पार्टी की नीति ६० फीसदी की है। उसमें हरिजन, स्त्रियां आती हैं। हरिजनों तो क्या, ब्राह्मण और ठाकुरों के घर की यहां तक कि गुप्ता जी के घर की औरत भी काफी बैकवर्ड हैं, काफी पिछड़ी हुई हैं। उनको केवल समान अधिकार दे कर ही नहीं उठाया जा सकता उन्हें विशेष अवसर प्रदान करें।

अब दाम के बारे में चन्द शब्द कह दूं। गन्ने का दाम बाकी है। चीनी ८ आने से लेकर १२ आने सेर तक बिकनी चाहिये, लेकिन बस्ती और ट्रांन्स-राप्ती एरिया में बिकती है डेढ़ दो रुपये सेर। उत्तर प्रदेश के किसानों का डेढ़ दो सौ करोड़ का लास होता है गलत दाम, नीति से। प्लानिंग कमीशन, बलवंतराय मेहता कमेटी नन्दा साहब, सभी ने कहा कि प्राइस कमीशन बनेगा, लेकिन पता नहीं वह कब बनेगा। हमारी दाम-नीति को आपको मान लेना चाहिये। वह एक रामवाण है इसके लिये। देवरिया, बस्ती की चीनी मिलों ने बड़ा चन्दा दिया, लेकिन वहां की सिंचाई योजनायें रखी रह गयीं। किसानों को उससे कोई फायदा नहीं मिला मैं बतलाना चाहता हूं कि यदि इस वर्ष नैपाल बाँध नहीं बन पाया तो सारा पूर्वी उत्तर प्रदेश डूब जायगा। सरकार को चाहिये कि एक ऐसी योजना बनायें कि जिसमें जितने पिछड़े प्रदेश हैं, मिर्जापुर, दुद्धी, राबर्ट्सगंज, सब की समस्याओं को देख कर कोई अपना निर्णय दे ताकि उनसे वहां कुछ काम हो सके।

अगर इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा देख कर फैसला देंगे तो यही होगा जैसे कि ७ अंधे आदमी हाथी देखने गये किसी ने सूंड को टटोला तो कह दिया कि केला है किसी ने कान देखा तो कहा कि सूप है। हाथी पूरा देख नहीं पाये उसी तरह से यदि देखेंगे आयोग तो कोई फायदा नहीं होगा।

मंत्री जी सबसे बड़ी मार यह है कि अपने राष्ट्रीय क्षेत्र के मजदूर हैं वह स्थायी नहीं किये जाते। हाइडिल में १७ हजार मजदूर काम करते हैं और केवल ढाई हजार स्थायी हैं। रोडवेज में २२ हजार में से ४,६ हजार हैं। उत्तर प्रदेश की श्रम मंत्राणी ने आदेश दे दिया कि वर्क्स कमेटी हाइडिल में बने लेकिन कोई लाभ नहीं होता। हाईडिल में ४८ मजदूर मर गये मुआवजे का नाम नहीं। बिजली का गलत इस्तेमाल होता है। अगर ३ बिजली बनती हैं तो २ बिजली इस्तेमाल होती हैं और एक लाइन की क्षति में चली जाती है। मैं पूछता हूं कि लाइन की क्षति को क्यों नहीं मिटाते? पी० डब्ल्यू डी० के मजदूर मेडिकल के मजदूरों की कोई नहीं सुनता। इसी तरह से रोडवेज के हैं कंडक्टर वगैरह और बिजली के लाइन मेन। इन को सबको राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाता। अगर दिया जाता तो वह अपनी बात यहां आकर रख सकते थे। शिकायत उस पुलिस कप्तान के यहां की है कि हिन्दी के आशुलिपिक थे और ५० रुपया तनख्वाह कम हो गयी अंग्रेजी का टाइप राइटिंग नहीं जानते थे हिन्दी का जानते थे। उन्होंने कहा कि हमको राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार होता तो अपनी बात के लिए लड़ सकते थे। मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा कि ७०० लोग निकाले जायंगे मगर यहां पर सचिवालय में सब बरकरार हैं। सचिव हैं, अनुसचिव हैं, उपसचिव, सहायक सचिव, कनिष्ट सचिव हैं, उभयनिष्ट सचिव हैं, वरिष्ठ सचिव हैं---एक भी नहीं निकाला जायगा। १३-१३ साल तक विराजमान रहते हैं और विधान मंडल के सचिव पर नोटिस हो गयी, यह इतना बड़ा पाप हो गया कि वह विधान मंडल चला रहे हैं।

इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल, अपनी सीमा का सवाल, बाराहोती का सवाल--- यह तब तक हल नहीं होंगे जबतक नीचे जो गड्ढे में गिरे हुए हैं उनको उठाने के लिये कार्यशैली नहीं बदलेगी और इस संबंध में योजनाएं सरकार की नहीं बनेंगी। मैं आशा करता हूं कि मंत्री

जी हमारे निवेदन पर गौर करेंगे और यदि कोई सुझाव काशी के गुरु को मान्य हो तो उन्हें मानने की कोशिश करेंगे ।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा इरादा तो बजट पर बोलने का नहीं था लेकिन जब मैंने अपने वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच सुनी जो कि इतनी सुन्दर भाषा में जोरदार शब्दों में थी कि मैं भी मुग्ध हो कर सुनता रहा लेकिन जब वह उस का आखिरी पृष्ठ पढ़ने लगे तो मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने मुझे कुर्सी पर से उछाल दिया हो धक्का देकर गिरा दिया हो। उसमें उन्होंने पूंजीपति और पैसे वाले लोगों के पास जो बकाया है उसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किसानों ने, मजदूरों ने और मध्यम वर्ग के लोगों ने खुशी खुशी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में धन दिया। और उन्होंने सदन को भी बधाई दी कि जो कुछ भी वे टैक्सेशन मेजर्स यहां लाये, हम सब ने उसको सपोर्ट किया। साथ ही जब उन्होंने यह कहा कि बड़े-बड़े पैसे वालों को भी उन गरीबों का अनुसरण करना चाहिये, यह भी कहा कि अनुसरण करना तो दूर रहा उन्होंने बकाया भी नहीं दिया, सुरक्षा कोष में भी पैसा नहीं दिया, और यह कहा कि उनको इस बात से प्रसन्नता होती यदि वे लोग बकाया दे देते और सरकार को कोई सख्त कार्यवाही न करनी पड़ती यह बातें मेरी समझ में कुछ आयी नहीं। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री की बाबत यह कहा जाता है कि वे लौह पुरुष हैं आइरन मैन। यह बात तो सरदार वल्लभभाई पटेल तथा नैपोलियन के बारे में कही जाती थी। नैपोलियन के बारे में यह बात कही जाती थी, मगर उसमें एक कमजोरी थी। वह यह थी कि जब वह जोजेफाइन के सामने जाता था तो घुटने टेक देता था। इसी तरह से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भी जब पूंजीपतियों के सामने जाते हैं तो अपने घुटने टेक देते हैं और उनका वही हाल हो जाता है जैसा कि नैपोलियन का जोजेफाइन के सामने जाकर हो जाता था। लेकिन नैपोलियन में कुछ समझ थी, जब योरोप में संघर्ष हुआ, उस वक्त उसने जोजेफाइन के सामने जाना छोड़ दिया। तो मैं बड़े अदब से माननीय मुख्य मंत्री जी से, वे इस समय नहीं हैं, माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इन पूंजीपतियों से और बड़े-बड़े आदमियों से अपना पिंड छुड़ा लें और सख्ती के साथ पेश आयें। आज हमें देश की जनता को यह बताना होगा कि हम युद्ध किसके लिये कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यदि हम उनको यह नहीं बता सकते तो हम उनका सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते। उनका सहयोग लेने के लिये यह जरूरी है कि हम जिस किसी की जैसी है सियत हो उसी के मुताबिक उससे धन, सामग्री तथा जो भी साधन उपलब्ध हों, लें। स्टेज बाई स्टेज चलें, पहले पैसे वालों से लें, फिर उससे कम हैसियत वालों से और आखिर में जो गरीब है उसकी जेब को टटोलें।

दूसरी बात मैं यह भी समझता हूं कि एक बार हमारे इसी सदन में १९३९ में कुछ उपद्रव हुआ था। उस समय स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा जी ने प्रताप में एक लेख लिखा था---"या तो छोड़ो या राज्य करो"। वह हम लोगों में से कुछ को अच्छा लगा, कुछ को बुरा लगा। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को यह फैसला करना होगा कि हम इस कमजोरी को बरदाश्त नहीं कर सकते, हम अपील नहीं कर सकते इन पूंजीपतियों से, उसको सख्ती के साथ वसूल करेंगे। फिर आज तो देश संकटकालीन अवस्था से गुजर रहा है। आज एक प्रश्न यह भी उठा है कुछ सदस्यों की तरफ से कि यह संकटकालीन अवस्था है कहां ? क्या संकटकालीन अवस्था जब युद्ध चलता रहे, तभी कहते हैं ? मैं समझता हूं, जब युद्ध चलता है, उस समय तो संकटकालीन अवस्था नहीं होती क्यों नहीं ? उस समय आपको कोई वातावरण बनाने की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं बन जाता है। लेकिन जब युद्ध नहीं होता हो, उसके लिये तैयारी करनी हो, तो हमारे सामने कठिनाई आती है कि जनता के दिल में उतना जोश नहीं होता और आवश्यकतायें उतनी ही रहती हैं या बढ़ जाती हैं। तो संकटकाल की अवस्था तो है। उसमें जो सरकार का बकाया है उसे सख्ती के साथ वसूल करना चाहिये। बकाया ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जिस अनुपात से उन्हें धन देना चाहिये वह उनसे लिया जाय और किसी प्रकार की दया नहीं दिखानी चाहिये।

[श्री जगनप्रसाद रावत]

श्रीमन्, वित्त मन्त्री जी ने कुछ संकेत किया था नये टैक्सों के लिये। कुछ उन्होंने डैफीसिट के बारे में भी कहा। मैं हमेंशा से यह कहता आया हूं कि डैफीसिट बजट स्वस्थ बजट होता है। उस से मालूम होता है कि सरकार के पास जितना पैसा है उससे कुछ ज्यादा करने का इरादा रखती है। इसलिये प्रगतिशील देशों के बजट में सदैव डैफीसिट हुआ करता है। लेकिन साथ ही साथ वह कमी साल के अन्त में जाकर सरप्लस में नहीं बदल जाती है। अगर सरप्लस हो जाता है तो प्रगतिशीलता की प्रतीक न होकर इस बात की प्रतीक हो जाती है कि बजट बनाने वालों में कमी है, अयोग्यता है। मेरे सामने आडिट रिपोर्ट सन् १९६२ की है। इसके पेज १३ पर कुछ आंकड़े दिये हैं, जिनमें यह भी है कि हमारा बजट १९५६-५७ में था १६८.४१ करोड़, खर्चा हुआ १४२.४७ करोड़ और बचत है २५.९४ करोड़, १९५७-५८ में १८३.४७, इसमें खर्च हुआ था १५९.६६ करोड़ और बचत हुई २३.८१, १९५८-५९ में १८८.४ में से खर्चा १६२.८८ और बचत थी २५.१६ करोड़, १९५९-६० में १६२.८५, खर्च हुआ १३३.६६ और बचत थी २९.१९ करोड़, १९६०-६१ में बजट था २७३.४९, खर्च २४७.९४ और बचत हुई २५.५५ करोड़ की।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

२७३ करोड़ कभी नहीं हुआ। कुछ गलती है।

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसमें छपा है, गलती हो सकती है।

१९६१-६२ में भी मेरा खयाल है कि लगभग ३५ करोड़ की बचत होगी और ऐसे ही १९६२-६३ में इसके आसपास आंकड़ा आवेगा। और अगर आप तफसील से देखें तो ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो विभागों में ही यह बचत होती हो। १९६०-६१ के एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स के पृष्ठ २ से ८ तक ये ब्योरेवार आंकड़े हैं कि किस विभाग के लिये कितनी ग्रान्ट दी गई, कितना खर्च हुआ और कितना बचा। मैं उन सबका देकर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन इसमें बीसियों विभाग ऐसे हैं जिनमें ५ लाख से ऊपर बचत हुई है। खास-खास मैं बता दूं जिन पर आप ताज्जुब करेंगे। स्टेट ट्रेडिंग में १३ करोड़ की और एग्रीकल्चर की स्कीमों में २.६३ करोड़ की। लोन्स ऐंड एडवान्सेज में २ करोड़ २९ लाख की बचत है। जो नये टैक्स के प्रप्रोजल्स आने वाले हैं वे गालिबन इस बजट के पास हो जाने के बाद अप्रैल या मई में आप लावेंगे। उस समय तक आपके पास सन् १९६१-६२ के भी आंकड़े आ जावेंगे और सन् १९६२-६३ के भी आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनमें आपको काफी बचत हो जाय जैसा कि पिछले सालों में होता रहा है, तो आप नये टैक्सेशन प्रोपोजल्स न लावें। जब मैं यह निवेदन करता हूं तो मेरा मतलब उन टैक्सेशन प्रापोजल्स स नहीं है जो आप पैसे वालों पर, धनी लोगों पर, लाना चाहते हों। उन पर भरपेट लावें। मेरी आपके साथ पूरी हमदर्दी है। मैं केवल यही चाहता हूं कि वे टैक्सेशन प्रापोजल्स न आवें जो मिडिल क्लास वालों पर, गरीब, किसान, मजदूरों पर पड़ते हैं। पैसे वालों से आप लीजिये, मेरी उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है।

पिछली मर्तबा हमारी २ फसल के लिये किसानों पर लैवी लगी थी। अगर इस बजट में आप ऐलान कर देते कि इसके बाद वह लेवी लगने वाली नहीं है तो हमें बहुत सन्तोष होता। अगर मेरा यह अनुमान ठीक निकले कि १९६१-६२ में २५/३० करोड़ का सरप्लस होगा जो खर्च नहीं हो सका और १९६२-६३ में भी ऐसा ही होगा, तो आप ने एमर्जेंसी लैवी जो वसूल कर ली है उसे वापिस कर दीजिये और आयन्दा के लिये उसे खत्म कर दें।

ला ऐंड आर्डर के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। ला ऐंड आर्डर की हालत हमारे सूबे में सन्तोषजनक नहीं है। अक्सर पुराने आंकड़े देकर कहा जाता है कि अबकी बार १ या २ डकैतियां कम पड़ी हैं फलां साल से। १५, १६ साल तक जो कुछ भी ला ऐंड

आर्डर की हालत रही हो उसे हम बर्दाश्त कर सकते थे क्योंकि उससे हमें ज्यादा खतरा नहीं था। आज जब हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरा पैदा हो गया है तो ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन हमें किसी हालत में भी, किसी भाव पर भी, ठीक करनी है, और उसे आप पूरी ताकत से ठीक करने की कोशिश करें।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी छोटे काम को भी करने से पूर्व आदमी को सोचना पड़ता है। चतुर पुरुष काम को करने से पहले सोचते हैं, लेकिन मूर्ख उसको करने के बाद सोचते हैं। घर में एक मुखिया के मरने पर जब दूसरा मुखिया आता है इसी प्रकार जब राज्यों का परिवर्तन होता है तो वे तीन बातें सोचते हैं। हमारे घर में संगठन हो जाय, दूसरी बात सोचनी पड़ती है कि मेरे ऊपर तो किसी का कर्जा नहीं अथवा मेरा तो किसी पर पैसा बाकी नहीं है। तीसरी बात सोचनी पड़ती है कि हमारा कोई शत्रु तो नहीं है। जब अंग्रेज यहां से गये तो चर्चिल ने कहा था कि हम तो जा रहे हैं लेकिन यहां ऐसा पलीता लगा दिया है जिसका असर बाद को होगा। मैं उनके विषय में इस समय और तो कुछ कहना नहीं चाहता हूं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप यह सोचें कि आजकल जो हमारी अंग्रेजों से मित्रता चल रही है वह मित्रता और सहयोग किस वजह से है। कहीं उसमें उनका तो कोई मतलब नहीं है।

श्री कृष्णपाल सिंह (जिला रायबरेली)—

श्रीमन्, यह भगदड़ हो रही है, इसको भी तो रोकिये।

श्री उपाध्यक्ष—

भगदड़ को तो मैं नहीं रोकना चाहता, लेकिन आप बातचीत न करें। शोर न हो।

श्री लोकपालसिंह—

तो हमें देखना चाहिये कि वह सहयोग किस लिये है—

सहते ही बने कहते न बने। मन ही मन पीर पिरोवौ करे।

सुरक्षा पर जो आप तीन, साढ़े तीन प्रतिशत व्यय कर रहे हैं वह बहुत ही कम है। राम राम कहने से राम तो मिल सकता है लेकिन सुरक्षा-सुरक्षा कहने से सुरक्षा नहीं हो सकती, न सगठन संगटन कहने से सगठन ही हो सकता है। हम हर काम सुरक्षा के लिये ही करना होगा, वही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिये। सब लोग ही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। वृक्ष अपने कांटों से करता है, बैल अपने सींगों से करता है, गैंडा सीगों से करता है, गदहा लात से करता है, बरैया डंक से करती है, और मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है। लेकिन हमने उस बुद्धि को प्रयोग नहीं किया। पंचशील और अहिंसा से देश की रक्षा नहीं हो सकती। कोई भी राज्य सत्ता अपनी रक्षा केवल फौज से ही कर सकती है, हथियारों से कर सकती है, नीति से कर सकती है—

सुख सोवे जब सूरमा, तो निश्चय उत्पात।
छुद्र गधेरी देत है ऐराकी के लात।
चूमत चरन शृगाल के, गजमद मर्दन शेर।
झपटत बाजन पै लवा यही दिनन के फेर॥
समय होत बलवान है पुरुष नहीं बलवान।
भीलन लूटी गोपिका वे अर्जुन वेही बान।
सूर समर करनी करें कहि न जतावहिं आपु।
विद्यमान रन पाय रिपु कायर करहिं प्रलाप॥

उसका कारण केवल यह है कि हमारी जितनी भी योजनायें हैं वे सब स्वप्न के आधार पर बनी हैं। आपने कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही नहीं की। आप तो सोचते रहे कि हमारी संसार में अहिंसा के कारण ख्याति हो गई है।

[श्री लोकपालसिंह]

आपको यह स्वप्न दिखाई पड़ा कि अमेरिका और इगलैंड के लोग तपस्वी हो गये हैं। और वे साबरमती आश्रम में आकर रघुपति राघव राजाराम का जाप करने लगे। उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति भारतवर्ष को दे दी है और अपनी फौज के सिपाही चर्खा-कर्घा कातने लगे हैं। आपको यह स्वप्न हुआ कि फौज के बड़े-बड़े आफिसर सन्यासी होकर पंचशील का राम जपने लगे हैं। रामफल, तोपें आदि लड़ाई की जितनी चीजें हैं वे सब अजायबघर में रख दी गई हैं, हमारे हवाई जहाज सर सपाटे की सामग्री बन गये हैं, हिन्दू-मुस्लिम मेल हो गया है, मुसलमान शादी-ब्याह होने लगे हैं, धर्म का भूत भाग गया है, भारतवर्ष स्वर्ग बन गया है और कांग्रेसी स्वर्ग के देवता हैं, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा सब एक चीज हैं और होली, दिवाली, मिलाद-शरीफ, बड़ा दिन ये सब मिलकर मनाये जाने लगे हैं। आपका यह भी स्वप्न था कि सोशलिस्ट सेना सेक्रेटेरिएट के चपरासी बन गये हैं, स्वतन्त्र पार्टी के लोग कुली-कबाड़ी बन गये हैं, और जनसंघ के लोगों को रिक्शा खींचने का काम दे दिया गया है, कम्युनिस्ट लोग आप में घुल मिल गये हैं जिससे यह नहीं मालूम पड़ता कि आप कम्युनिस्ट हैं या व कम्युनिस्ट हैं, दाल में बटाई है या बाल है बटाई में। आपका परस्पर ऐसा मेल हो गया है कि यह मालूम ही नहीं पड़ता कि—

सारी मध्य नारी है, या नारी मध्य सारी है,
सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है।

यह पता ही नहीं पड़ता कि सारी है कि नारी है.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय लोकपालसिंह जी, अब आप बाद में जारी रखें। अब हम उठते हैं, दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री लोकपाल सिंह—

कांग्रेस का स्वप्न अधूरा रह गया था, शेष भी सुनिय, अहिंसा, पंचशील, अनशन ऐसे अमोघ अस्त्र अब उसके पास आ गये हैं जिनसे सारा विश्व और सारे सरहदी पठान भयभीत हो जाते हैं। आज उनके इन अमोघ अस्त्रों से चीन और रूस भी परेशान हैं, इन्हीं अस्त्रों से अंग्रेज घबराकर भाग गया। अब ग्राम पंचायतों ने राजसत्ता को सम्भाला है, अदालतों का काम न्याय पंचायतों ने सम्भाला है।

श्री अधिष्ठाता—

यह आप कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री लोकपालसिंह—

यह मैं पहले ही बता चुका था कि मैं 'कांग्रेस का अधूरा स्वप्न' सुना रहा हूं। मैं पढ़ नहीं रहा हूं मैं वैसे ही सुना रहा हूं। खद्दर पल्टन-पल्टन नम्बर ६ ने जलसेना का काम सम्भाला है और थलसेना का काम करघा पल्टन नम्बर ८ ने सम्भाला है और नभ सेना का काम चरखा पल्टन नम्बर ९ ने। यह कांग्रेस का स्वप्न है। राजा राम स्वर्ग में सोचने लगे हैं कि बेकार में लंका दहन किया और उसपर चढ़ाई की अगर अनशन रावण के दरवाजे पर कर देते तो सीधे विजय हो जाती। स्वर्गस्थित महाराज युधिष्ठिर भी अब सोचने लगे हैं कि बेकार ही महाभारत में सारे परिवार का नाश किया, अगर दुर्योधन के दरवाजे पर अनशन कर देते तो कितना अच्छा होता, आधा राज्य वैसे ही मिल जाता और इतना नाश भी न होता। श्री अब्दुल्ला भी यहां हाजत कबूल कर के आये और उन्होंने पंचशील को पंचछील कर के माना और वह अब पंचछील का राग अलाप रहे हैं। कम्युनिस्ट नेताओं ने उन के पास

सन्देश भेजा होगा, वह उनके कहने से हट गये तो उनके ही कहने से वह आये भी होंगे। जब इस तरह से हमारी योजना बगैर पैसे की है तो फिर बजट में परेशानी किस बात की। आप इस स्वप्न पूर्ण योजना पर भी बजट बनाते हो।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कोई स्वप्न नहीं दिया, मेरा कोई स्वप्न नहीं है।

श्री लोकपालसिंह—

मेरा मतलब सरकार के स्वप्न से है, मैंने आपका सुधार मान लिया है। फिर उसने पंचछील कर ही डाला।

कवि वेद अजा नित ही तो कटे गज सिंह कभी न कटे न कटेंगे।
धनहीन के मान सर्वस्व घटे, धनवान के मान घटे न घटेंगे॥

यही हमारी दशा है लेकिन उस पर आप सन्तोष कर रहे हैं कि अब तो चीन पीछे हटने लगा है—

दुम्मी हटो न जानिये, नहिं के हरि छपकन्त।
जो बैरी हंसि के मिले, कुशल करें भगवन्त।

और सुनिये—

क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। अव्यवस्थित चित्तानान्तु प्रसादोपि भयंकर।

यह स्थिति बड़ी भयंकर होती है। हमें तो 'शठं शाठ्यं समाचरेत्' पर इनके साथ चलना चाहिये।

आततयीतन मायान्तं हन्यादेवा विचारयन् रन्धया शासद्व्रतान्।

आततायी का हनन करो। मनु का वाक्य है दुष्टों का दमन करो। अथर्ववेद का कथन है। अग्नेतं भस्मात्कुरु, यह यजु वेद का कथन है। अर्थ है जो तुम्हें सतावें उसे खाक कर दो। चाणक्य का कथन है जो राजा न लड़ने वाला होता है उसको पृथ्वी खा जाती है द्वाविदौ ग्रसते भूमिः सर्पो विलशयानिव। राजनं चाविरोद्धार, साधुन चाप्रवासिनयम, जैसे सर्प चूहे को खा जाता है बगैर बल के कहीं राजा होता है, बगैर बल के कहीं मल्ल होता है? दल बिन राजा बल बिन मल्ल। जल बिन कुआं सुनो यह गल्ल। विरोधी दल के लोगों से आप बड़े रुष्ट हो जाते हैं, उनके सही सुझावों पर आप क्यों नहीं चलते।

आज कल ऐसे शख्स को समझो गनीमत ए पदम।
बात बुरी कहे दिल का मगर बुरा न हो॥

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)—

माननीय सदस्य मेगना का रटा कोई पढ़ रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता—

वह अपना नोट पढ़ रहे हैं।

श्री लोकपालसिंह—

हमारा श्री युधिष्ठिर वाला सिद्धान्त है कि चीन से लड़ने के लिये हम सब मिलकर आप के साथ हैं।

वयं पंचः वयं पंचः वयं पंचः शतंचते, अन्यत्र च विवादेषु वयं पंचोत्तरं शतम्।

आप हम पर विश्वास करें। जरा कम्युनिस्टों से सतर्क रहें। सब आदमी एक से नहीं होते।

खुदा पंच अगुश्त एक सां न कर्द। न हर जन जनअस्त, न हर मर्द मर्द॥

[श्री लोकपाल सिंह]

हमसे मिलजुल कर रहते हैं लेकिन शतरंज के मोहरे की तरह हमको कुचलने के लिये तैयार रहते हैं।

यारां चकद्र राहे दुरंगी दारद्व ।
मसहफ व बगलो दीने दुरंगी दारद्य ।।
पैवस्ता वह म चू मुहराये शतरंज।
दरदिल हमा फिक्के खाना जंगी दारद ।।

आप कुर्सी के लोभ में बदनाम हो गये हैं ।

सरमद बकूचये इश्क वदनाम शुदी। अज दिने यहूद सूये इस्लाम शुदी।।
मालूम न शुद अज खुदाग्रो अहमद । बरगश्ता वसूये लछमनो राम शुदी।।

गैर हमेशा गैर ही होता है ।

इस आस्तीं के सांप से होगी कभी न खैर ।।
है अपना आखिर अपना है गैर सदा गैर।।

सीतापुर में पौरुष का हाथी पाला जा रहा है, मेरे एक मुसलमान दोस्त जो वहां पर बड़े अफसर हैं उन्होंने बताया यहां पर बहुत से अफसर ऐसे हैं जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं।

न अब जान जहमत वतन में सहेगी। यह तूती अरब के चमन में रहेगी ।

माननीय नवलकिशोर जी इस ओर ध्यान दें। सीतापुर में जो ११वीं बटालियन है उसमें पाकिस्तानी जज्बात के लोग हैं।

तूफान भी है सैलाब भी मल्लाह है कुछ दीवाना सा।
जब ऐसी शकिस्ता किस्ती हो साहिल की तमन्ना कौन करे।

वेद में युद्ध के जो सिद्धान्त हैं उनको मान कर कांग्रेस को जिन्दा रखने की बात न सोचिये बल्कि देश को जिन्दा रखने की बात सोचिये।

हमदम चमन को फिकर कर न कि आशियां पै मर।
है फजले खुदा जो कि हवा आज टल गई।

आज के इस युद्ध ने हमारी यह दुर्दशा कर दी है कि अब किसी को गर्व करने की जरूरत नहीं रह गई। भारत का सिपाही अब घमंड नहीं करेगा।

अब जनि कोइ भाषहि भटमानी। वीर विहीन मही मैं जानी।

यह जरूर कहा करेगा कि हमारे बाप के बाप के बाप के बाप वीर रहे, अपनी वीरता कोई भारत वासी नहीं कहेगा।

वीर रहे वरवीर रहे, बहु युद्ध किये बहु जंग सम्हारे।
पूरण पुंज प्रताप रहे, सच जीत लिये क्षण में रण सारे।।
नीति के ज्ञाता विधाता रहे, सुखदाता रहे जग के अति भारे।
बाप के बाप के बाप, के बाप के बाप के बाप के बाप हमारे।।

श्रीमन्, अपने बल से शक्ति आती है, गैर के बल से शक्ति नहीं आती। समुद्र जिस जलाशय में था उससे कमल ने कहा—

वारिधि तात रहे विधि से सुत आदित्य सोम सहोदर दोऊ,
द्वय भगिनी रहीं रम्भा रमा मघवा मधुसूदन सी बहनोऊ,
तुच्छ तुषारइतो परिवार कियो न सहार बिलोकत सोऊ,
सूखि सरोज गयो जलमाहिं सो भीर परै पे भयो कब कोऊ।

इस पर समुद्र ने कहा—

जाको सुता हरि के गृह सुन्दरि ईश गिरीश के शीश प्रवीना ।
इन्द्र गजेन्द्र दियो हय सूरज देवन धेनु दया कर दीन्हा ।
श्री मुनिजी जब कोप किये तब तीन चुल्लू भरि के मोहिं पीना ।
एते बड़े पे विपत्ति परी तब सिन्धु सहारु कहीं किन कीन्हा ।

विपत्ति पड़ने पर कोई अपना नहीं होता। अपना ही बल हमेशा काम आता है। आप अपने को समझिये और हम दोनों हाथ आपकी मदद के लिये उठायेंगे, आप चाहे एक ही उठायें लेकिन संकटकालीन स्थिति का विचार करते हुये उसके लिये आप कदम उठाइय, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे चलेंगे, हम तिरंगे के नीचे अपना सिर कटा देंगे। यदि तुम्हारे कारखाने में गोली की कमी हो जाय तो हम तोप के गोलों के स्थान पर सिर लगा देंगे और बारूद की कमी पड़ जाने पर श्री मुकर्जी की चिता की धूल बटोर कर लादेंगे, वह बारूद का काम करेगी।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो आय-व्ययक प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं। मुझे खुशी होती है कि ऐसे संकटाकालीन समय में जिस ढंग से आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया है इससे सुन्दर दूसरा और कोई आय-व्ययक नहीं हो सकता था। सन् १९५२ से ५७ तक मेरा इस सदस्य का कुछ अनुभव रहा है और एक वर्ष से इस सदन में मैं फिर से अनुभव कर रहा हूं। पिछले दिनों मैंने देखा कि जब बजट पेश होता था तो उधर से कल्याणकारी राज्य का कल्याणकारी बजट और विरोध में कल्याणकारी बजट के नारे लगते थे। लेकिन दुर्भाग्य से देश के ऊपर संकट आया और संकटकालीन समय में जब आज मनोबल की दुहाई दी जाती है तो बजट को या महामान्य राज्यपाल के भाषण को या अन्य कोई विधेयक को, जिसको भी देखा जाय, मन्त्रिमंडल का विस्तार और मनोबल, इन दो चीजों को लेकर आरोप, प्रत्यारोप चलता है। यह दुर्भाग्य की बात है। जब सुरक्षा का प्रश्न हमारे सामने है तो हमें देखना यह होगा कि आज साढ़े सात करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति जो सभा में बैठे हैं, चाहे वे उधर बैठें चाहे इधर बैठें, यदि इस प्रकार की बातें कहेंगे तो हमारे पीछे जो जनता देख रही है उसके मन का धैर्य कहां तक रहेगा। मैं इस बजट के लिये दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना सुन्दर बजट है कि इसके विचारों को, इसकी भावनाओं को और जो इसके अन्दर योजनायें रखी हैं उनको देखा जाय तो वे सब सुव्यवस्थित हैं और सुन्दर हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि समुद्र से उठने वाला जल जब आकाश में जाकर बादलों के रूप में बरसता है तो वह जल तो जल ही रहता है लेकिन नदी के अन्दर वह मीठा होता है और पय होता है किन्तु समुद्र में पहुंचने के बाद वह खारा हो जाता है और पीने के योग्य नहीं रहता। यहां मैं नीति का एक श्लोक उद्धरित करना चाहूंगा :—

"गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति,
ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः
आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्यः
समुद्रमासाद्य भवन्त्ययेया ।"

अर्थात् जो गुण है वह तो गुण ही है। वह चीज जो अच्छी है वह भी वहां सामने तक पहुंचते-पहुंचते वह समुद्र के जल के रूप में नजर आने लगती है। मैं समझता था कि आज अच्छी चीज को अच्छा कहा जायगा और सुन्दर बात को सुन्दर कहा जायगा और जो हमारी त्रुटियां हैं, कमजोरियां हैं या कमियां हैं उनको दर्शाया जायगा। लेकिन वही

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

पुराना राग और वही पुरानी खंजड़ी। मैं क्या कहूं। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। एक ठाकुर साहब ऊंट पर कहीं जा रहे थे। उनसे लोगों ने पूछा कि कहां जा रहे हैं? तो कहा कि जा तो अलीगढ़ रहे थे लेकिन नकेल टूट गई है पता नहीं यह कहां ले जाय। मान्यवर १०-१० वर्ष तक लोग चुने जाकर विधान सभा में सदस्य रहे हैं और दलों के होकर रहे हैं मगर दल की ओर से यदि दुर्भाग्य से उनको टिकट न मिल पाया तो विरोध में चले जाते हैं। आचार संहिता बनी उसकी भी परवाह नहीं करते और अपनी प्रतिज्ञा को जिस पर उन्होंने टिकट पाने के लिए किया तोड़ते हैं और जो दल के अन्दर दुनिया भर की जिम्मेदारी वे यहां पर निभाते थे वे ही आज दल का टिकट न पाने पर विरोध में आकर दलीयशासन की बखिया उधेड़नी शुरू कर देते हैं और यदि मैं उनको विभीषण की मिसाल दूं तो अतियुक्ति नहीं होगी। कभी-कभी तो माननीय चरणसिंह जी को यहां मुख्य मन्त्री बनाने की दावत देने लगते हैं। जैसे इनके ही हाथ में सब कुछ है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर वे अपना नैतिक बल देखें तो मालूम हो।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य व्यक्तिगत बातों की चर्चा न करें। वैसे जो आपकी इच्छा।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मान्यवर, कल मैंने सुना। माननीय जे० पी० मिश्र भाषण दे चुके थे। माननीय कुंवर श्री पालसिंह जी ने बड़ा प्रभावपूर्ण भाषण दिया और उन्होंने कहा कि वे भी पुराने कांग्रेसी रहे हैं और जेल भी गये थे या जाने वाले थे या जाकर बीच में आ गये जो भी हो। उन्होंने खुद ही कहा था। उन्होंने एक शब्द कहा कि पुराने राजाओं के यहां जो दरबारी दरबारी किया करते थे उनको भी श्री जे० पी० मिश्र ने मात कर दिया। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। जब उन्होंने परिवहन विभाग के बजट का उल्लेख करते हुये कहा कि जिस कर्मचारी ने यह लिखा है मैं उसके हाथ चूम लूं। मैं समझता हूं कि उन्होंने उस समय कमाल कर दिया। जिन कर्मचारियों को रात दिन उनकी ओर से गालियां मिलती हैं, उनका यह सौभाग्य तो है कि उनका हाथ चूमने वाले लोग भी मौजूद हैं। इसमें एक शब्द था ४२० जिसका अर्थ उन्होंने चार सौ बीस का लगा लिया। उदाहरणार्थ एक शब्द 'दीन' ले लीजिये उसके आगे दयाल लगा दें तो दीनदयाल हो जाता है और यदि मुहम्मद लगा दें तो दीन मुहम्मद हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभू मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना होती है उसे वैसा ही नजर आता है अन्यथा उस आंकड़े को सीधा-सीधा चार लाख बीस हजार पढ़ना चाहिये था। सहकारिता विभाग की आलोचना की और अन्य विभागों की भी की। अगर स्मृति पत्र को गौर से देखा होता तो मालूम होता कि जहां मन्त्रियों के खर्चे बढ़ने की बात लिखी है वहां स्थायी समितियों की वजह से खर्चा बढ़ने की बात भी लिखी है। माननीय कुंवर साहब, तो एक समिति के अधिष्ठाता भी हैं, आलोचना करते समय सुझाव भी देने चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

शायद सूचना आपकी गलत है। वे अधिष्ठाता नहीं हैं। शायद आपका आशय उनके आश्वासन समिति के अध्यक्ष होने से है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

कोई हर्ज नहीं है। मेरे "अधिष्ठाता" शब्द को "सभापति" में परिणत कर लें। चेयरमैन समझा जाय, हिन्दी में कुछ वैसा चलता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो विद्वान हैं। आपको तो गलत प्रयोग नहीं करना चाहिये।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

भाई उग्रसेन जी ने योजनाओं को बेकार बताया । प्रधान मंत्री पर भी आक्षेप किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है । आज हम सारे दल चाहे किसी भी विचारधारा के हों, संकटकाल की परिस्थिति में जब एकमत से चल रहे हैं तो उस समय जो हमारे देश का हेड है उसको इस प्रकार के आरोपों से नीचा दिखाने की कोशिश करना उचित नहीं है। विधान सभा के मंच पर बोलने के बाद वह अखबारों में जायगा, विदेशों में जायगा । मैं चुनौती देता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री की बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता का ही यह फल है कि दुनियां के लगभग ७० देश आज हमारी तरफ हैं । यदि हमने ऐसा नेतृत्व न पाया होता तो यह सम्भव न हो पाता। लांछन यह लगाया गया कि नेहरू जी कहते हैं लद्दाख भी दे दिया जाय। किसने कहा है ? क्या प्रमाण है ? लेकिन यहां वाक्स्वतंत्रता है । विशेषाधिकार है । जैसा चाहें तोड़ मरोड़ कर शब्दों का उपयोग करें ।

माननीय रावत जी ने अपने विचार प्रकट किये। मैं उनकी बातों का क्या जवाब दूं ? मैं उनको अपना नेता ही मानता हूं। उन्होंने १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२ के कुछ आंकड़े दिये । मैं रावत जी का आदर करता हू । मैं नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि अगर इससे पहले के सालों के १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ के भी आंकड़े दिये होते तो बड़ी शांति मिलती । लेकिन वह उस वक्त के आंकड़े न बता सके क्योंकि उस वक्त कुछ जिम्मेदारी उन पर भी थी । वह डिप्टी मिनिस्टर थे । पारलियामेंट्री सेक्रेटरी भी पहले रह चुके थे, उन्होंन ला ऐंड आर्डर का भी जिक्र किया । वह डिप्टी होम मिनिस्टर थे । उस समय क्या ला ऐंड आर्डर चल रहा था ? उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री की नैपोलियन से तुलना की और कहा कि वह पूंजीपतियों के सामने अपने घुटने टेक देते हैं । दुर्भाग्य है कि १९५७ में जनता ने मुझे भी कुछ दूसरा सबक दिया था, उनको भी दूसरा सबक दिया था और माननीय मुख्य मंत्री को भी दूसरा सबक दिया था, जिस समय के वे आंकड़े देते हैं। लेकिन एक बात मैं विरोधी पक्ष से जरूर कहना चाहता हूं कि जब रावत जी बोल रहे थे तो मुझे बड़ा विचित्र-सा लगा जब कि विरोधी पक्ष की ओर से तालियां बजायी गयीं । हमेशा औरंगजेबी नीति से सावधान रहना चाहिये। अगर हमारे अन्दर विकल जी, रावतजी या मैं या कोई और भाई हमारे दल की आलोचना करने लगे तो आपकी कुर्सियां सुरक्षित न रह सकेंगी । आपको इस पर दुखित होना चाहिये । अगर हमारे अन्दर आलोचना होती है तो फिर आप कहां रहेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

प्रत्यक्ष बातचीत न हो ।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

मान्यवर, आप शब्द का बहु अर्थ रहता है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रत्यक्ष बातचीत होती है तो वातावरण दूसरे ढंग का हो जाता है । बेहतर होगा कि हमार माध्यम से आप अपने विचारों को रखें ।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

मैं इसका ध्यान रखूंगा। ऐसी गलती न करूंगा कि आपके माध्यम के अलावा कोई बात कहूं मान्यवर, हमें सदन में ऐसी बातें कहनी चाहिये जो वास्तव में उस विषय से संगत हों । आज हम बजट के भाषण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उसी के संबंध में यदि हम अपनी बातें कहें तो ज्यादा संगत होगा । श्रीमन्, शिक्षा, सहकारिता, उत्पादन, कृषि, उद्योगीकरण आदि इन सबके बारे में इस बजट के अन्दर माननीय वित्त मंत्री ने जिक्र किया है । कहा यह गया कि सुरक्षा के नाम पर इतना ढिंढोरा पीटा जाता है और साढ़े तीन परसेंट केवल उस पर व्यय रखा गया है। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि सुरक्षा शब्द का अर्थ केवल यदि मोर्चे पर गोली चलाना है तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मोर्चे पर गोली चलाने वाले जवान के लिये किन-किन चीजों की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, गल्ले की आवश्यकता है, यदि उसको स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिलेगा, भोजन अच्छा नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा और अन्य

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

सामग्री नहीं मिलेगी तो जवान कैसे लड़ेगा ? साथ ही उन जवानों के पीछे जो एक अदम्य उत्साह और प्रबल शक्ति जनता की और जनमत की है यदि हम उसमें किसी प्रकार त्रुटि का अनुभव करने लगेंगे तो कितनी शांति भंग हो जायेगी ? इसलिये आज उत्पादन को बढ़ाना सुरक्षा के अन्दर आता है, उद्योगों को बढ़ाना सुरक्षा के अन्दर आता है, कृषि को बढ़ाना सुरक्षा के अन्दर आता है, डाक्टरों को बढ़ाना सुरक्षा के अन्दर आता है, तो यह सब चीजें कहां छोड़ी गई हैं ? विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने का इसमें जिक्र है, मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ाने का जिक्र है, २५ प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या मेडिकल कालेजों में बढ़ाने का जिक्र है। तो कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ा गया है जो सुरक्षा से संबंध रखता हो । उसकी आलोचना केवल इस दृष्टि से की जाय कि क्रिटिसिज्म फार दि सेक आफ क्रिटिसिज्म है तब तो मैं समझता हूं की यह एक दुर्भाग्य की बात है। क्रिटिसिज्म होना चाहिये कांस्ट्रक्शन के लिये, विरोधी पक्ष की तरफ से रचनात्मक सुझाव आने चाहिये । मुझे खुशी होती यदि सही-सही बातों के बारे में ही थोड़ा सा हमारे माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद भी दिया गया होता, बजट के प्रति थोड़ी सी भी यह बात कहीं कही जाती कि अमुक अंग सही है और अमुक स्थान पर त्रुटि रह गई है, उसको ठीक करना चाहिये ।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संकट काल हमारे ऊपर क्या आया, मैं तो समझता हूं मान्यवर, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, सन् १९६२ में महाप्रलय-काल का नारा सुना था संकट काल चीन की ओर से भारत के ऊपर आया, लेकिन उसके साथ-साथ शायद जनसंघ के ऊपर भी संकटकाल आ गया क्योंकि जब कभी विरोधी दल के नेता बोलते हैं या कुंवर श्रीपाल सिंह जी बोलते हैं तो तुरन्त उधर से ऊदल जी कच्छा तान कर खड़े हो जाते हैं, तो विरोधी दल जो इस बात का दावा करते हैं कि वह इधर बैठने के हकदार हैं, उनमें अगर इस तरह की लड़ाई होती रही तो एक तो उनकी पहले से ही तादाद कम है और ऊपर से इस प्रकार आपस में फूट रही तो उनकी आशा के स्वप्न कैसे पूरे होंगे ? इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं ।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सन् १९६३–६४ का बजट एक परिपाटी के अनुसार घाटे के बजट के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है । इस बजट में ४ करोड़ ९७ लाख रुपये के घाटे का अनुमान दिखाया गया है। विरोधी दलों की ओर से और सरकारी बेंचों की ओर से यह भी व्यक्त किया गया है कि जिस प्रकार से पिछले सालों के बजट घाटे के होने के पश्चात् बचत के बजट के रूप में परिणत हुए उसी प्रकार से यह बजट भी बचत के रूप में कहीं परिणत न हो । लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में इस बात का आश्वासन दिया है कि मेरे ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता है कि मैंने आय के तखमीनों को लगाने में कमी की है और व्यय के आंकड़े अधिक दिखाये हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है । इसका अर्थ यह होता है कि इस चालू वर्ष में ४ करोड़ ९७ लाख के अतिरिक्त कर सरकार जनता के ऊपर लगाने की इच्छा रखती है । दूसरी ओर माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में पूंजीपतियों के संबंध में कुछ बातें कही हैं कि एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में उन्होंने सहयोग नहीं दिया है और दूसरी ओर बकाया धन की भी वसूली नहीं हो पाई है। इसके साथ-साथ एक वर्ग इस प्रदेश में ऐसा और है जिसने न राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में कोई सहयोग दिया है और न वह संकटकालीन स्थिति का अनुभव करता है । वह वर्ग है उच्च वेतन भोगी नौकरशाही का जो उच्च वेतन की नौकरियों में काम करते हैं । आज वास्तव में उसी का शासन इस प्रदेश में चल रहा है । बहुत से मंत्री महोदयों की भी उनके सामने दीन दशा रहती है । उन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया है । मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि यदि वह कर लगाना ही चाहती है तो जो उच्च वेतन भोगी सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको १ हजार से अधिक वेतन मिलता है उनके ऊपर सैलरी टैक्स लगाना चाहिये । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिन पूंजीपतियों को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस राष्ट्रीय संकटकालीन अवस्था में लाभ हुआ है और वह लाभ इस प्रकार से हुआ है कि सैनिक सज्जा सामान के बड़े-बड़े ठेके उन्होंने प्राप्त किये हैं और उन ठेकों को प्राप्त करके वह धन कमा रहे हैं, सरकार को चाहिये कि ऐसे पूंजीपतियों पर अधिक से अधिक कर लगा कर उनसे धन वसूल किया जाना चाहिये ।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार ने पुलिस की बढ़ोत्तरी के संबंध में इस बजट में कुछ वृद्धि की है । पुलिस के संबंध में, उसके भ्रष्टाचार के संबंध में जब पुलिस के बजट पर विवाद होगा तब मैं अपने विचार रखूंगा लेकिन आज तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस शासन की आज क्या दशा है । मैं आगरा का उदाहरण आपके सामने रखता हूं । डकैतों के मारे आगरा जिला त्राहि त्राहि कर रहा है । प्रति दिन एक न एक अपहरण और डकैती वहां पर होती रहती है । माधो और जग्गा डाकू ने एक सभा करके एक संघ बनाया है जिसका नाम डकैत कांग्रेस संघ रखा गया है .....

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

कांग्रेस का नाम आप गलत लेते हैं ।

श्री बालोजी अग्रवाल--

आप इससे इतने चिन्तित न हों । उन्होंने जो अपने संघ का नाम रखा है वह मैं आपको बतला रहा हूं । उसके साथ यदि कांग्रेस है तो संघ का नाम भी तो साथ में जुड़ा हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह से व्यवधान करना वांछनीय नहीं होगा । यह सदन की मर्यादा के विपरीत होगा । माननीय सदस्य अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं । आपको भी जब अवसर मिलेगा तो उस समय अपने विचारों में आप उसका खंडन कर सकते हैं । इस समय बीच में कुछ कहना ज्यादा स्वस्थ न होगा ।

श्री बालोजी अग्रवाल--

मान्यवर, इस समय उन डकैतों की एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई हैं कि उस जिले के अन्दर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है । गांव और कस्बों से लोग शहर की ओर भाग रहे हैं । इसके साथ ही मैं यह सुझाव दूंगा कि शहरों में पी० आर० डी० को पुलिस का विंग बना दिया गया है । वह पुलिस के साथ-साथ थानों और चौकियों में रहता है और उन्हीं के साथ काम करता है । इस प्रकार से काम करने से उनके मन में मनोमालिन्य की भावना पैदा हो गई है और ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई है । मेरा सुझाव यह है कि नगरों में जो पी० आर० डी० विंग है उसको पुलिस से अलग किया जाना चाहिये जिससे वह अपना काम करता रहे ।

इसके बाद नागरिक सुरक्षा की बहुत दुहाई दी जाती है । इस समय सदन में विपक्ष की ओर से समय-समय पर बोलते समय इस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि सन् १९४२ में कौन कहां था और १९४७ में कौन कहां था और अंग्रेजों से युद्ध के समय कौन कहां था । हमें तो इस समय इस बात पर विचार करना चाहिये, इन सब बातों को छोड़ कर कि जब हम चीन से लड़ रहे हैं तब हम सब कहां पर हैं । जो लोग काश्मीर घाटी दे कर समझौता करना चाहते हैं या भारत सरकार को तटस्थता की नीति छोड़ कर पश्चिमी ब्लाक में मिल जाने की सलाह देते हैं या ऐसा कहते हैं कि इस संकटकाल में हमें अपना नेतृत्व बदल देना चाहिये, वह इसी प्रकार देश का अहित कर रहे हैं जिस प्रकार कि चीन को मदद देने वाले हमारे देश के दूसरे गद्दार भाई । मैं कांग्रेसी नहीं हूं और न कांग्रेस में मिलने की मेरी कोई इच्छा है, लेकिन मैं अपने दिल से कहता हूं आज पंडित जवारलाल नेहरू के नेतृत्व को बदलने की बात करना देश को गर्त की ओर ले जाना है और देश का अहित करना है । (तालियां) अब तो खुश हो गये मिश्र जी आप ।

मान्यवर, मंत्रिमंडल घटाने की जब बात कही जाती है तो सरकारी पक्ष की ओर से उसका विरोध किया जाता है । उससे मितव्ययिता हो या न हो, लेकिन इतना अवश्य है कि प्रदेश

[श्री बालोजी अग्रवाल]

की जनता यह चाहती है कि मंत्रिमंडल छोटा होना चाहिये । प्रदेश की जनता में इस बात से असंतोष है कि प्रदेश का मंत्रिमंडल बड़ा है । मान्यवर, हम लोगों की इच्छा है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस बैंचों पर बैठने वाले कांग्रेसी भाइयों की भी यह इच्छा है कि गुप्त जी को हम लोग अपने हीरो के रूप में देखें, लेकिन पंजाब के मुख्य मंत्री कैरों आज अपने प्रदेश के ही नहीं, सारे देश के हीरो बने हुए हैं । मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी भी उसी प्रकार सुरक्षा कोष में धन इकट्ठा कर, मंत्रिमंडल को कम करके हीरो के रूप में प्रदेश के सामने आयें । जिस समय मंत्रिमंडल घटाने की बात कही गयी थी उस समय माननीय मिश्र जी ने अब मैं उनका नाम लेकर ही कहता हूं--इस तरह की बात कही थी कि मंत्रिमंडल और बढ़ना चाहिये । मैं उनके लिये एक उदाहरण देना चाहता हूं । मंत्रि मंडल चाहे जितना बढ़ जाय, लेकिन उस शेरनी के कहने के अनुसार कि जब गीदड़ के बच्चे शेर के पीछे दौड़े तो उसने कहा कि हे गीदड़ के बच्चो, जिस कुलमें तुम पैदा हुये हो उसमें शेर नहीं मारे जाते, माननीय मिश्र जी, आपको मंत्रिपद नसीब नहीं होगा ।

मान्यवर, रक्षा निधि के संबंध में पिछले दिनों यह आरोप लगाया गया था कि जबरदस्ती धन वसूल किया जा रहा है । वह बात अपनी जगह पर है । मैं आपके सामने कुछ दूसरी बात रखना चाहता हूं । इस निधि में जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है उनकी जांच होनी चाहिये । मैं आगरा शहर कांग्रेस कमेटी का उदाहरण रखता हूं । यह रसीदें मेरे पास हैं उन पर न रसीद नम्बर है न बुक नम्बर और न किसी के हस्ताक्षर हैं और इन पर पैसा इकट्ठा किया गया है । कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितनी रसीदें छपीं, इसकी जांच होनी चाहिये । हमारे यहां मेयरफंड में रुपया इकट्ठा हुआ है । उन रसीदों पर बुक नम्बर और रसीद नम्बर है लेकिन किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं । इसका ईश्यू करने वाला कोई नहीं है । यह दोनों रसीदें शहर कांग्रेस कमेटी के प्रधान के प्रेस में छपी हैं । मेरा कहना यह है सरकार से .....

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपा करके ये रसीदें मुख्य मंत्री जी को भेज दें तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री बालोजी अग्रवाल--

अच्छा, अधिष्ठाता जी । तो मेरा कहना यह है कि सुरक्षा निधि जिन नामों से और जिस स्थान पर एकत्रित की गयी हो उसकी जांच होनी चाहिये और उसे जनता के सामने रखना चाहिये जिससे इस राष्ट्रीय संकट-काल में कोई घुटाला न कर पाये ।

होम-गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा के संबंध में जितनी भी बातें कही गयी हैं, उसके अतिरिक्त मैं भी एक दो बातें रखना चाहता हूं । ट्रेनिंग बहुत से लोगों को दी गयी, नाम जरूर ट्रेनिंग का है, लेकिन वास्तव में वह ट्रेनिंग नहीं है । क्योंकि राइफल के हैंडिल कर लेने से, थोड़ी कवायद होने से ट्रेनिंग पूरी नहीं होती । उनके पास बुलेट्स नहीं हैं । जबतक निशाना लगाने की ट्रेनिंग नहीं होगी तबतक किस बात की ट्रेनिंग हुई ? जो प्वाइंट दो-दो (.२२) से भी फायरिंग करायी गयी है उसका पैसा भी ट्रेनिंग पाने वाले लोगों से वसूल किया गया लखनऊ और आगरे में । तो जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाय उनको वह चीज मुहैया करनी चाहिये जिससे वह एमिंग कर सकें जिसका कि लड़ाई के मोर्चे पर मुख्य आधार है ।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं । इस बजट में आगरे की ओर बिलकुल दुर्लक्ष्य किया गया है । आगरे का एक पुल जो कि राष्ट्रीय मार्ग दो पर यमुना नदी पर बनने वाला था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से चला आ रहा है, लेकिन सामने अभी तक नहीं आया है जिसके कारण आगरे को बड़ी असुविधा होती है । हमारी सरकार ने बड़ा पैसा लगाकर यमुना पार एक औद्योगिक बस्ती बनायी है जहां ८० के लगभग इंडस्ट्री खुली हैं लेकिन यातायात का साधन नहीं है । जो बिल्डिग पी० डब्ल्यू० डी० की ओर से बनायी गयीं वह टूट रही हैं । फूलसिंह जी, उद्योगमंत्री जब आगरे गये थे तो उन्होंने देखा था, उनमें दरारें पड़ गयीं हैं । जब हम

उद्योग को पनपाना चाहते हैं और उन्नति करना चाहते हैं तो उनको हर प्रकार की सुविधा सरकार की ओर से दी जानी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त ।

*श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे सामने सन् १९६३-६४ का बजट पेश है, मैं कुछ सुझावों के साथ समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । निस्संदेह आजादी प्राप्त करने के साथ साथ अपने देश को सामाजिक न्याय की ओर बढ़ा ले जाना हमारा ध्येय है, उस दृष्टिकोण से यह बजट रखा गया । आज अपने प्रदेश को उस गिरी हुई हालत से ऊपर उठा लेना हमारा एक लक्ष्य है, जिसके द्वारा हम गरीब किसान मजदूरों को राहत दे सकें, अशिक्षित लोगों को शिक्षित बना सकें, जिन लोगों के पास कोई उत्पादनके साधन नहीं हैं उनको साधन मुहैया कर सकें और प्रदेशके लिये देशमें उच्च स्थान प्राप्त करा सकें । इन सब मनोभावनाओं को सामने रखते हुये यह बजट पेश हुआ । इस जमाने में चीन जैसे देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया, उससे खाली सीमा पर ही आक्रमण नहीं है, यह तो हमारी लोकतंत्र प्रणाली पर एक आघात है और यह हमारी सभ्यता और संस्कृति पर भी एक चोट है । यह हमारी सैद्धांतिक परम्पराओं पर हमला है । इस पर मौलिक रूप से हमें आपको गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है । यह परिस्थिति कुछ दिनों तक ही रहने वाली नहीं है, बल्कि यह एक लम्बे अर्से तक रहेगी । जैसा कि हमारे राष्ट्र नायक पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दोहराया है, जो लोग यह कहते हैं कि अब संकटकालीन स्थिति नहीं है, वे गलती पर हैं और यह वही लोग कह रहे हैं जो कहते थे कि हमारी सरकार चीन के हमले के लिये तैयार नहीं थी । आज जब कि हम उसके लिये पूर्णरूप से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिये अपनी योजनाओं को बना रहे हैं, इस बात को कहना कि अब संकट नहीं है, गलत है और एक भ्रम है ।

प्रश्न अब यह उठता है कि आखिर ऐसा लोग क्यों कहते हैं ? मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार की विरोधी पार्टियां हैं उनका दृष्टिकोण ही किसी दूसरी तरफ है । उनका लक्ष्य तो इस बात का है कि आज सरकार उनकी बननी चाहिये । इसीलिये वे घुमाफिरा कर कांग्रेस और पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिये तरह तरह के रास्ते निकालते हैं । उनके पास कोई इतिहास नहीं है, कोई तथ्य नहीं है ।

दूसरे जो लोग यह कहते हैं कि हमें अपनी तटस्थता की नीति छोड़ देनी चाहिये, वे इसलिये ऐसी बात कहते हैं क्योंकि आज जो दुनियां के देशों में भारत और पंडित नेहरू की ख्याति है, सम्मान है, उसको देखकर उनको ईर्ष्या हो रही है । उनके अन्दर तो आज यह भावना पैदा हो रही है कि किसी तरह से हम उनकी जगह पर आसीन हों । लेकिन यह उनका केवल स्वप्न ही है । यहां तक पहुंचने के लिये बड़े त्याग और बलिदान की आवश्यकता है । कांग्रेस ने बड़े-बड़े त्याग और बलिदान किये हैं । पंडित नेहरू के पीछे एक बड़ी कुर्बानी छिपी है ।

श्रीमन्, आज जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है, उसमें दो बातों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है । एक तो यह कि हमारी योजनाएं शक्तिशाली होना चाहियें, और दूसरी सुरक्षा की ओर हमें विशेष ध्यान देना है । इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है । आज देश की सुरक्षा के लिये कृषि-उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है, उद्योग-धंधों को बढ़ाने की आवश्यकता है, सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है और इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है । आज हमारे देश में यह योजनायें नहीं होतीं तो इस लड़ाई का सामना अच्छी तरह से नहीं कर पाते । हम आज दूसरे देशों के मोहताज नहीं हैं । जो दूसरे देशों से हमें मदद मिल रही है उसके लिये हम उनके आभारी हैं, लेकिन कोई देश दूसरों की मदद पर जिन्दा नहीं रह सकता, तरक्की नहीं कर सकता, उसके लिये जरूरी है कि हम अपनी ही योजनाओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बृजमोहनलाल गुप्त]

को पूरा करें, अपने ही पैरों पर खड़े हों । हमारे देश में शिक्षा, यातायात एवं चिकित्सा की सुविधायें बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है । मेडिकल कालिजों में जो २५ प्रतिशत की वृद्धि की गई है, उससे मालूम होता है कि हमारी नीयत तरक्की करने की है । तो मैं यह देखता हूं कि आज न तो कांग्रस की गवर्नमेंट है और न नेहरू जी की गवर्नमेंट है, यह तो ब्यूरोक्रेसी की गवर्नमेंट है। इसलिये हम सबको मिल कर यह सोचना चाहिये कि इस नौकरशाही में किस प्रकार से तब्दीली लायी जा सकती है । किसी भी पार्टी का मिनिस्टर होगा उसको नौकरशाही चलाने की कोशिश करेगी । पिछले सेशन में यह बात कही गयी थी कि इसके लिये सब दलों की एक कमेटी होनी चाहिये जो नौकरशाही में परिवर्तन लाने पर विचार करे। बार-बार कहा जाता है कि इतने मिनिस्टर यहां क्यों बैठे हुये हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े आफिसर्स बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाते हैं और जिनके पीछे बहुत बड़ा लवाजमा लगा हुआ है, उनकी ओर आपकी निगाह क्यों नहीं जाती । अगर हमने इस नौकरशाही को इस संकटकाल में ठीक न किया तो आगे कभी न कर सकेंगे । दूसरी ओर मैं सब अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अच्छी बात चाहे जिस पार्टी की ओर से कही जाय, उसको पूरा करने की कोशिश करें, प्रदेश की जनता की भलाई के लिये, किसान मजदूरों की भलाई के लिये जो बात हो उसपर अवश्य ही विचार करना चाहिये ।

सुरक्षा के लिये जो कर लगाये गये हैं उनमें किसानों पर, गरीबों पर बहुत कर लग गये हैं । अब वह उस बोझ को बरदाश्त नहीं कर पा रहा है । आज भी लोग कहत ह कि महाराणा प्रताप की भामा शाह ने मदद की । लेकिन आज पूंजीपतियों ने ऐसा नहीं किया, क्या यह देशद्रोह नहीं है ? आज आपको टैक्स भूमिपतियों और पूंजीपतियों पर लगाना चाहिये ।

हमारा सूबा तो एक पूरे शरीर की भांति है। अगर हम किसी एक ही अंग को पोषित करेंगे तो वह मोटा हो जायगा और भद्दा लगेगा। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें पहाड़ी भाग है, पूर्वी भाग है पश्चिमी भाग है, बुन्देलखंड का भाग है। इन सब की साथ-साथ तरक्की होनी चाहिये और सारे शरीर को सुडौल बनाना चाहिये। एक माननीय मित्र ने कहा कि बिजनौर में किसी खास आदमी के लिये ही सड़क बना दी गयी है। मैंने भी बजट में देखा तो मालूम हुआ कि एक आध स्थान पर किसी खास व्यक्ति के लिये ही वास्तव में काम हुये हैं।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

देखिये यह एक सड़क है जो एक लाख से ऊपर खर्च करक बनायी गयी है।

श्री अधिष्ठाता—

यह चीज ठीक नहीं है । सदन में शांति बनाये रखने में आप हमारी मदद करें, तो मेहरबानी होगी।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

मैं जो कह रहा था उसको किसी पर लांछन लगाने के लिये नहीं कह रहा था। मैं जिस इलाके को रिप्रेजेंट करता हूं यानी बांदा को अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां यातायात का कोई साधन नहीं है और अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाय तो उसके लिये डाक्टर १० दिन में वहां पहुंच पायेगा। न वहां कोई डाक्टर है न कोई सड़क है, न कोई स्कूल है। बांदा जहां की आबादी करीब ९ लाख की है वहां एक भी डिग्री कालेज का न होना क्या यह हमारे लिये शर्म की बात नहीं है ? हमारे पश्चिमी व पूर्वी जिलों के एक-एक जिले में आठ-आठ और नौ-नौ-डिग्री कालेज हैं जब कि वहां एक भी नहीं है। वहां कोई ऐसी इंडस्ट्री भी नहीं है जिससे गरीबों को, किसान व मजदूरों को फायदा पहुंच सके।

वहां कोई और ऐसे साधन भी नहीं हैं जिन के द्वारा हम वहां की किसान जनता को फायदा पहुंचा सकें। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या बांदा व बुन्देलखंड को इसलिये नेगलेक्ट किया गया है कि वहां की आबादी कम है या वहां के विधायक कम हैं और वहां आन्दोलन करने की कोई व्यवस्था नहीं है जैसा कि दूसरे जिलों में है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पूर्वी जिलों के लिये एक आयोग मुकर्रर किया गया है कि वह वहां जाकर जांच पड़ताल करें कि वहां किन-किन बातों की जरूरत है, उसी बात को मद्देनजर रखत हुये बुन्देलखंड के लिये भी कमीशन नियुक्त होना चाहिये जो इस बात की जांच पड़ताल करे कि वहां की जनता की तरक्की के लिये क्या-क्या काम किया जा सकता है।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहता हूं। जिन भाइयों की तरफ से यह बात कही जाती है कि इस सरकार द्वारा जितनी खराब बातें की जा रही हैं उनके लिये अकेले श्री चन्द्रभानु गुप्त जिम्मेदार हैं क्योंकि वे मुख्य मन्त्री हैं, मेरा निवेदन यह है कि किसी भी सरकार में अकेले एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती है बल्कि उसकी जिम्मेदारी पूरी पार्टी की होती है, पूरे कैबिनेट की होती है, सब लोगों की ज्वांयट रिस्पांसिबिलिटी होती है। इसलिये सब भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस संकटकालीन अवस्था में आर्थिक परिस्थिति को देखते हुये अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे सुझाव दें और इस बजट का समर्थन करें और आगे के लिये अपने प्रदेश को तैयार करें जिससे वह संकट व मुसीबत का मुकाबला कर सकें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इमर्जेंसी के मौके पर यह जो बजट पेश हुआ है, इस बजट के पेश होने से पहले मुझे उम्मीद थी कि इस साल जो बजट पेश होगा वह कुछ अजीब ढंग का, एक निराले किस्म का होगा और होना चाहिये। इसलिये कि और साल के बजट में और इस साल के बजट में अन्तर है। डिफेंस के मुताल्लिक मेरा कुछ जाती तजुर्बा है क्योंकि मैं चार वर्ष तक डिफेंस के सिलसिले में काम कर चुका हूं और उन सब बातों को इच्छी तरह से समझता हूं। उन सब बातों को देखते हुये जब यह बजट मेरे हाथ में आया और इसको मैंने पढ़ा तो पढ़ कर जितनी मुझे नाउम्मीदी हुई, उसका मैं कुछ बयान नहीं कर सकता।

इस इमर्जेंसी का मुकाबला करने के लिये दो चीजें जरूरी हैं। एक तो यह कि मुकाबले का सामान फराहम करना, उसके लिये रुपया, जवान, खून इन सबका फराहम करना और दूसरा इसके खर्च करने का ढंग। इसमें कोई शक नहीं कि रुपया फराहम करते समय आप ने जो तरीका बरता वह कुछ इस तरीके से बरता कि पहिया ही पटरी से उतर गई। आपकी हालत कुछ घबड़ाहट की हो गई और आपको इसका होश नहीं रहा कि क्या चीज हम ठीक कर रहे हैं और क्या चीज गलत कर रहे हैं। मैं इस बात पर जोर नहीं देता कि सरकार द्वारा वसूली में ज्यादती या गलती हुई लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि हमारी कांग्रेस सरकार रुपया फराहम करने में नाकामयाब रही। यह बड़े शर्म की बात है कि एक छोटा सा सूबा पंजाब तमाम हिन्दुस्तान में रुपये इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा नम्बर ले जाता है और आज इसके मुकाबले में हम पिछड़े हुये हैं। इस सम्बन्ध में मैंने एक खत माननीय मुख्य मन्त्री को लिखा कि क्या कारण है कि हमारा सूबा रुपया इकट्ठा करने में पंजाब व हिन्दुस्तान के दो एक और सूबों से पिछड़ा हुआ है, तो उन्होंने बड़े-फख्र के साथ हमें जवाब दिया कि हमारा सूबा किसी से पिछड़ा हुआ नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया कि वह प्रदेश जिसका १०००, १२०० मील सीमा क्षेत्र हर वक्त खतरे में हो वहां केवल ४ करोड़ रुपया इकट्ठा हो और फिर भी हमारे मुख्य मन्त्री यह कहें कि हमारा सूबा किसी से पिछड़ा हुआ नहीं है। जबकि हमारे बराबर के प्रदेश पंजाब ने देश के सामने मिसाल पेश की है और हम उस पर फख्र से कहें कि हम किसी से पिछड़े हुये नहीं हैं। रुपया वसूल करने का ढंग व तरीका कुछ भी रहे, उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा केवल दो मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे आदरणीय

[श्री रियासत हुसैन]

जगदीशप्रसाद जी यहां पर नहीं हैं उन्होंने बड़े फख्र से कहा था कि वसूली में कोई ज्यादती नहीं हुई। मैं उनको उस मुदारादाबाद जिले की मीटिंग की याद दिलाऊंगा कि जिस में श्री नारायणदत्त जी तिवारी गये थे और उसमें वह खुद मौजूद थे, मैं भी उसमें गया था और उसमें ए० डी० एम० प्लानिंग भी मौजूद थे, वह गजरौले के ब्लाक की मीटिंग थी जो हसनपुर के क्षेत्र में पड़ता है जहां से वह आते हैं। उस ब्लाक की मीटिंग में वहां के सघन क्षेत्र के जो चेयरमैन थे श्री महेंद्रसिंह जी उन्होंने माननीय जगदीशप्रसाद जी की मौजूदगी में कहा था कि पैसा हम दे रहे हैं, आगे भी देंगे, यहां की जनता भी धन देगी और देश की कठिन परिस्थिति की आवश्यकता को समझ कर देती रहेगी, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि इस वसूली के ढंग व तरीके में रद्दोबदल होना चाहिये। उस के बाद वहीं पर ए० डी० एम० प्लानिंग दयाल साहब ने वादा किया कि जिस ढंग से वसूली हुई है वह गलत हुई है और आइन्दा एसा न होगा। एक दूसरी मिसाल और दूंगा, माननीय दाऊदयाल जी यहां नहीं हैं वह जब माननीय मुख्य मन्त्री का प्रोग्राम बना था और बिलारी गये थे गन्ना कोआपरेटिव सोसाइटी से रुपया लेने के लिये तो उन से वहां शिकायत की गई कि हाकिम परगना ने लोगों को पकड़-पकड़ कर पीटा है और थाने में रुपया वसूल किया है। इसका इन्तजाम करने का श्री दाऊदयाल जी ने वादा किया, लेकिन उन्होंने इन्तजाम क्या किया? यह इन्तजाम किया कि उन हाकिम परगना को वहां से हटाकर जिले का डिफेंस आफिसर बना दिया और एक दूसरे एस० डी० ओ० को वहां भेज दिया और कह दिया कि हमने उनको वहां से हटा दिया है। यह दो मिसालें आप के सामने मैंने रखीं। मुझे अफसोस है कि जब चीन का हमला हुआ और जब कि उसका मुकाबला करने के लिये हमको हर तरह से तैयार रहना चाहिय था तो यह प्रदेश जिसका १०००, १२०० मील का बोर्डर खतरे में है और जबकि हम जानते हैं कि तिब्बत में चीन के हवाई जहाजों का अड्डा बना हुआ है और जब चीन ने नेफा और लद्दाख पर हमला किया तो वह आपसे पूछ कर नहीं किया, अब अगर वह फर्भ आप पर हवाई हमला करेगा तो आप से पूछ कर नहीं करेगा। आज एक साल के करीब हो जायगा लेकिन जो हवाई हमले के खिलाफ प्रिकाशनरी मेजर्स होत हैं वह भी आप नहीं कर सके। जब यहां पर हमारे प्रधान मन्त्री जी लखनऊ आये तो उन्होंने कहा कि अब ट्रेंचेज की जरूरत नहीं है, मुझे अफसोस होता है अगर आप आज भी दिल्ली के चांदनी चौक जैसे खूबसूरत बाजार में जाकर देखें तो वहां पर एयर रेड प्रिकाशन के तौर पर दूकानों के सामने दीवारें बनाई गई हैं और नई दिल्ली के चौराहों पर गोल बनाये गये हैं और ट्रेंचेज बनाई गई हैं लेकिन लखनऊ में कहा जाता है कि उनकी जरूरत नहीं है। मैं बरमा के फ्रंट पर एक जमान में था मैं जानता हूं कि एयररेड से बचने के लिये जितनी ज्यादा कारामद यह खन्दकें होती हैं, मैंने बरमा में देखा है कि एयररेड के वक्त हमारे खेमों के बराबर में खन्दक खोदी जाती थीं लेकिन यहां पर उनको भी नेगलेक्टट किया जा रहा है। इन होमगार्ड और सिविल गार्ड की छोटी-छोटी बातों से काम नहीं चलेगा, इन चन्द आदमियों पर आप भरोसा नहीं कर सकते जबतक आप अपनी तमाम जनता को इस काबिल न बना देंगे कि अगर कोई खतरा आता है तो लाखों की तादाद में यहां की जनता हथियार लेकर उस का मुकाबला कर सके। जब फौज में इस तरह की ट्रेनिंग होती है तो वह ६ सप्ताह की होती है, उस ट्रेनिंग के वहां ३ हिस्से होते हैं, पहल एलीमेंटरी ट्रेनिंग होती है जिसमें कि लेफ्ट-राइट और कदम मिलाना चलना सिखाया जाता है, उसक बाद २ सप्ताह की राइफल ट्रेनिंग होती है और फिर उसके बाद होती है फील्ड ट्रेनिंग।

अगर आप जनता को राइफल ट्रेनिंग के लिये भी तैयार कर देते तो दूसरे मुल्कों के सामने यह बात रहती कि यहां की जनता इतनी तैयार है कि अगर हमने हिन्दुस्तान की तरफ आंख उठा कर देखा तो करोड़ों की तादाद में दो हफ्तों के अन्दर फील्ड ट्रेनिंग पा कर हिन्दुस्तान का सिपाही मैदान में आ सकता है। आप पुलिस डिपार्टमेंट से अगर कहते कि

इस दौरान में काम को दुगुना कर दो, .१२, १२ कांस्टेबिल एक थाने में रहते हैं, उनसे कहते कि एक महीने के लिये ६ आदमी थाने पर काम करेंगे और बाकी कांस्टेबिल, एक कांस्टेबिल को ४, ६ गांव देते कि वह वहां जाकर वहां के नौजवान लोगों को परेड कराये, तो १ महीने के अन्दर ऐलीमेंट्री ट्रेनिंग मिल सकती थी। अगर राइफलें नहीं थीं तो बांसों से ट्रेनिंग हो सकती थी और हम किसी भी मुसीबत के लिये तैयार रहते दो हफ्ते में राइफल ट्रेनिंग देकर मैदान में अपने जवान भेज सकते थे। जो पुराने फौज के आदमी थे, जो पुलिस के ट्रेंड आदमी थे उनसे मदद नहीं ले सके और नहीं वह इलाके जो एयर रेड की जद में आते हैं, जैसे मुरादाबाद और काशीपुर है, वहां कोई ऐसी बात नहीं मालूम हुई जिससे इमरजेंसी दिखाई देती। रुपया जरूर इकट्ठा हुआ, लेकिन ट्रेनिंग की बात कुछ नहीं पता चली।

कहा जाता है कि पी० आर० डी० कैम्प्स के लिये रुपया रख दिया और तीन दिन की ट्रेनिंग दी गई। लेकिन सिखाया क्या वहां? तुम इनाम किस तरह से लेने जाओगे। क्या इससे सिपाही आपका मैदान में जाने के लिये तैयार हो जायेगा? कहते हैं अकेले हथियार से ही लड़ाई नहीं होती है। मैं मानता हूं उसके लिये खुराक, खून और रुपये की जरूरत होती है। बड़ा अच्छा होता सरकार यह देख लेती कि कहां से हमें रुपया मिलेगा, कहां से खून मिलेगा, और कहां से जवान मिलेगा। इस चीज को अगर हल कर लेती तो यहां कुल ५ करोड़ रुपया जमा न होता। मुरादाबाद में २०, २२ लाख रुपया जमा हुआ, हमारा जिला डिवीजन में सबसे आगे रहा, लेकिन अफसोस है कि माननीय दाऊदयाल जी ने वहां सभा में कहा, और यहां वित्त मन्त्री ने कहा कि बड़े आदमियों ने रुपया नहीं दिया। माननीय दाऊदयाल जी ने जल्से में कहा १७ लाख रुपया मध्यम वर्गीय और गरीब जनता ने दिया और कुल ३ लाख रुपया बड़े आदमियों ने दिया है। एक तरीका था अगर सरकार अपने ५४ कलेक्टरों को आदेश देती कि जिनसे तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है, जो तुमसे फोन पर बात करते हैं, अपने काम के लिये तुम्हारे पास आते हैं उनसे सख्ती से रुपया वसूल किया जाय और अगर कलेक्टर ऐसा नहीं करेंगे तो उनसे जवाब लिया जायगा, देखिये सब इन्तजाम ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया। जितने एम० एल० ए०, एम० एल० सी०, ब्लाक प्रमुख हैं, उन्हीं की वजह से छोटी जनता से रुपया वसूल हो पाया लेकिन बड़े अफसरों ने इस बात की कोशिश नहीं की कि जो लोग उनके पास अपना काम निकालने के लिये आते हैं उनसे कह सकें कि भाई रुपया दो। अगर आसानी से नहीं दोगे तो सख्ती बरतनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस कि कुल ३ लाख रुपया बड़े-बड़े सेठ साहूकारों से आया है और १७ लाख रुपया नीचे की जनता और मिडिल क्लास से आया है जबकि मुरादाबाद के साहूकारों का रुपया तमाम हिन्दुस्तान में किस्तों की शक्ल में फैला हुआ है।

जहां तक एग्रीकल्चर की बात है गल्ला बढ़ना चाहियें, बिल्कुल ठीक है। जो इलाका मेरा है उसमें ८ महीने से सीमेंट नहीं पहुंची इसलिये कि वहां इरीगेशन का कोई और जरिया नहीं है। मैंने यहां के मन्त्री श्री जगमोहनसिंह नेगी जी को लिख कर दिया कि वहां सिंचाई का छोटा-छोटा सिस्टम, कुओं का है, इतना सीमेंट वहां पहुंचना चाहिये ताकि माइनर रिपेयर्स होकर इर्रीगेशन हो सके। मैंने जिले के ए० डी० एम० प्लानिंग से कहा कि आप वहां से नहीं मंगा सकते तो किसी दूसरी जगह से लेकर हमें दे दीजिये ताकि माइनर रिपेयर हो जायं और कोई एरिया अनइर्रीगेटेड न रह जाय। लेकिन ८ महीने हो गये, कोई नतीजा नहीं निकला। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जरात में पैदावार बढ़ाने के लिये काश्तकारी में सबसे मुख्य चीज पानी है। आप पानी का इन्तजाम कर दीजिये, किसान खाद, बीज का अपने आप इन्तजाम कर लेगा। अगर सरकार अपने ऊपर यह जिम्मेदारी ले ले कि एक-एक इंच जमीन की आबपाशी वह करायेगी तो और चीजों का इन्तजाम किसान खुद कर लेगा। आज आपकी दी हुई खाद किसान इसलिये इस्तेमाल नहीं कर पाता कि अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, नाइट्रेट, इन सब चीजों को देने के बाद उसे पानी भी मिल जायगा या नहीं। नतीजा यह होता है कि जिस खेत को हम पानी देते हैं उसकी पैदावार ढाई, तीन मन बीघा होती है और जिस खेत को पानी नहीं देते उसकी पैदावार २० सेर

[श्री रियासत हुसैन]

और ६ धड़ी बीघा रह जाती है, यानी औसत पैदावार ८ मन फी एकड़ आती है। आज सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा यह होता है कि अमोनियम सल्फेट को इस्तेमाल मत करो, दूसरी खाद इस्तेमाल करो। मैंने अपने मुदारादाबाद के जिलाधिकारी से भी कहा है और आज अगर यहां चौधरी साहब होते तो उनसे भी कहता, लेकिन उन तक मेरी यह बात पहुंचा दी जाय कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि अमोनियम सल्फेट के अलावा आप किसी भी दूसरी खाद को इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ा तो दीजिये, नहीं बढ़ सकती। लेकिन आपके डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल मत करना, इससे अलक्लाइन हो जायगा, जमीन खराब हो जायगी। आज सुबह प्रश्नोत्तर के समय में जो सरकारी फार्मों में नुकसान की बात उठी थी, उसकी यही वजह है कि सरकारी फार्म थ्योरी के ऊपर चलते हैं, प्रैक्टिकल के ऊपर नहीं जबकि किसानी का काम प्रैक्टिकल के ऊपर चलता है, थ्योरी के ऊपर नहीं। इर्रीगेशन के बारे में जब इर्रीगेशन की ग्रांट आयेगी तब मैं कहूंगा लेकिन एक मोटी बात बताऊं कि इसमें कम से कम कुनबापरस्ती नहीं होनी चाहिये। मिसाल के लिये मैनपुरी में एक मिजाजीलाल जी ने एक ट्यूबवेल बनवाया था। दो साल बाद जब उसका डिस्चार्ज कम हो गया तो उन्होंने कहा कि इसे सरकार ले ले। सरकार के इंजीनियर ने रिपोर्ट दी कि इस कुयें का डिस्चार्ज सिर्फ १२ हजार गलन है लिहाजा बेकार है। उसके बाद उन्होंने आप लोगों में से किसी को पकड़ा और सरकार ने वह कुंआ ले लिया। उसके बाद उसकी मरम्मत में आडिट रिपोर्ट के मुताबिक ५१ हजार रुपये का नेट लास गवर्नमेंट को हुआ। यह इसलिये हुआ कि मिजाजीलाल जी को सरकार खुश करना चाहती थी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कुछ दिन पहले इसी सदन में विरोधी दल के नेताओं की ओर से यह ध्वनि आ रही थी कि अब देश में इमर्जेंसी नहीं है और आज वह स्वीकार कर ली गई है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता और सन्तोष है। अब यह कहा गया कि बजट जो प्रस्तुत किया गया है उसमें इमर्जेंसी का भाव नहीं है। माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि किसी प्रकार की इमर्जेंसी नहीं है और नेता विरोधी दल ने अपनी स्वीकृति देने में गलती की। उन्होंने अपने भाषण में कैलाश मानसरोवर से लेकर कन्या कुमारी तक सारे देश को आवाहन किया उससे मैं समझ सकता हूं कि उनके हृदय में भी इमर्जेंसी की भावना है, इसको उन्होंने प्रकारान्तर से स्वीकार कर लिया है। अब सवाल यह है कि इमर्जेंसी के अनुरूप प्रस्तुत बजट में व्यवस्था की गई है या नहीं। इस की व्यवस्था में पहली बात यह है कि डिफेंस परसोनल तैयार करें, डिफेंस का सामान पैदा करें और ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दें जिनका सम्बन्ध सुरक्षा के सामान से है। इसके अतिरिक्त सिविलियन्स के कंजम्पशन के लिये भी एक निश्चित मात्रा सामान की निर्धारित करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे प्रयत्नों में सामजंस्य का अभाव होगा जिसको कोई पसन्द नहीं करेगा।

मान्यवर, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस संकटकालीन अवसर पर सारे देश ने एकता का परिचय दिया और राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। देश की सरकार के और नेताओं के सामने यह सवाल था कि किस प्रकार इसको प्रसाधन के रूप में परिणत करें। सबसे पहली बात यह हुई मान्यवर, कि इसी सदन के सभी सदस्यों ने, लोक सभा में प्रधान मन्त्री तथा अन्य सदस्यों ने और सारे देश ने एक संकल्प लिया कि हम उसको बचाने के लिये जितना भी हो सकेगा त्याग करेंगे, उत्सर्ग करेंगे और अपने जीवन का बलिदान करेंगे और आतताइयों को देश से खदेड़ने के लिये अपने सर्वस्व की बाजी लगा देंगे। इसी संकल्प क अनुसार

सरकार ने कदम उठाये। इसके लिये प्रदेश को सेकन्ड लाइन आफ डिफेंस बनाना आवश्यक हो गया। इसके लिये प्रान्तीय रक्षा दल बनाया गया, होम गार्ड्स की रचना हुई और विलेज वालेंटियर फोर्स के बनाने का प्रयास हुआ। नेता विरोधी दल को भ्रम है कि ये भिन्न-भिन्न चीजें हैं। जहां तक होम गार्डस् का सवाल है यह केन्द्रीय व्यवस्था है लेकिन जहां तक प्रांतीय रक्षा दल और विलेज वालेंटियर फोर्स का सवाल है ये एक ही हैं। इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्री जी के भाषण में इसको स्पष्ट कर दिया गया है।

मान्यवर, इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक था कि विकास योजनायें भी चलाई जायं और उनको प्रायरिटी के आधार पर इस प्रकार से आयोजित किया जाय कि वे सुरक्षात्मक कार्यवाही में अपना योगदान दे सकें और जो मौलिक सिद्धान्त या मौलिक आवश्यकतायें हैं उनका भी परिपालन कर सकें।

मान्यवर, मैं इस चीनी आक्रमण को यह नहीं समझता कि यह केवल हमारी भूमि पर आक्रमण है। मैं अनुभव करता हूं कि यह हमारी परम्परा, हमारी लोकतन्त्र की व्यवस्था, राष्ट्रीयता, हमारी विकास पद्धतियों को एक चुनौती है। ऐसी अवस्था में सोचना होगा कि अगर हम विकास योजनाओं को छोड़ देते हैं, अगर हम उनको पीछे ढकेल देते हैं तो हम सेल्फडिफीटेड स्टैन्ड कर जाते हैं। जो शत्रु की मंशा है वह अनायास ही पूरी कर देते हैं। इन तमाम बातों को दृष्टिगत रखकर जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें इमर्जेंसी की भावना आद्योपान्त ओतप्रोत है। एक बात अवश्य है। पैनिक की भावना, भागदौड़ की भावना, चिल्ल-पों की भावना नहीं है। यह बजट ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत हुआ है जो समर्थवान हैं, जो धैर्य, साहस, विवेक बिना भयातुरता का अनुभव किये हुये दृढ़ता के साथ मुकाबला करने के लिये सन्नद्ध हैं। कृषि, सिंचाई, विद्युत तथा उद्योग के सम्बन्ध में जो अनुदान इसमें प्रस्तुत हुये हैं बजट साहित्य को अध्ययन करने से स्पष्ट है कि यह सरकार बड़ी खूबसूरती के साथ निश्चित लक्ष्यों की ओर प्रदेश को ले जा रही है। इस लिये बजट, में इमर्जेंसी के अभाव की शिकायत निर्मूल है।

एक बात और कही जाती है मितव्ययिता की भावना की युद्धकाल में बड़ी आवश्यकता होती है। मितव्ययिता का एक अर्थ होता है ऐसे मौकों पर, जिसको आस्टेरिटी कहते हैं। अपने निजी खर्चों को कम करना, अपने जीवन की आवश्यकताओं को थोड़ा कम करना यह नितांत आवश्यक है। लेकिन ऐसी मितव्ययिता जिससे एक्सपैंडिंग इकानोमी को धक्का लगे सराहनीय नहीं होती है। आज के विकासमान का मापदंड एफीशेंसी है, एकानोमी नहीं है। इसलिये कार्यक्षमता को भी ध्यान में रखने की परम आवश्यकता है।

मैं उस पचड़े में नहीं जाना चाहता कि मन्त्रिमंडल बहुत विस्तृत है, छोटा करना चाहिये। लेकिन मैं मान्यवर, प्रवृत्तियों की बात अवश्य कहूंगा कि अगर यह प्रवृत्ति बढ़ती गई कि मन्त्रि मंडल कम हो, फिर दूसरा नम्बर क्या है? इस आदरणीय सदन को छोटा किया जाय, तीसरा नम्बर यह है कि डेमोक्रेसी को समाप्त किया जाय। एक तरफ कहा जाता है कि नौकरशाही का राज्य है। दूसरी ओर यदि मन्त्रिमंडलीय व्यवस्था को समाप्त करने की ओर बढ़ेंगे तो किस की ओर आगे बढ़ेंगे? किसको ताकत मिलेगी? मैं समझता हूं कि नौकरशाही आगे बढ़ेगी। यह निर्विवाद है। और उसकी जो शिकायतें करते हैं, वे और प्रज्जवलित रूप में, निर्भीकता के साथ आपके सामने आयेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लोकतन्त्र की पद्धतियों और नौकरशाही में चुनने का मौका दिया जाय तो आप क्या चुनेंगे? मैं समझता हूं कि कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला व्यक्ति समाजवाद में विश्वास करने वाला व्यक्ति, लोकतांत्रिक समाजवाद की विकास प्रक्रिया में विश्वास करने वाला व्यक्ति इन दो बातों में निश्चित रूप से कुछ हानि उठाकर भी लोकतांत्रिक पद्धतियों को जीवित रखने के लिये ही अपना मत देगा, नौकरशाही को अधिक बलवान करने की बात कदापि नहीं सोचेगा।

[श्री रामलखन शुक्ल]

मान्यवर, मैंने नेता विरोधी दल की बात बड़े गौर से सुनी । मैं विरोधी दल के सभी साथियों का आदर करता हूं और नेताओं का विशेष रूप से आदर करता हूं । उनकी बात से मुझे ऐसा लगा मान्यवर, कि नेता विरोधी दल के भाषण में एक सामन्तशाही जोश है, इतस्ततः बिखरे हुए समाजवादी नारों की एक प्रतिध्वनि है और प्रकारान्तर से प्रापर्टी क्लास के बचाव और उसके समर्थन का बड़ा सुन्दर दिग्दर्शन उसमें है, मुझे ऐसा लगा उनके भाषण से । मान्यवर, एक कन्फ्यूज्ड थाट की धारा है । एक तरफ आप फ्री एन्टरप्राइज को फ्री लूट कह गए और फौरन खयाल पड़ा कि कहां जा रहे हैं तो कहने लगे राशन, परमिट और कोटा नहीं चलना चाहिये, सरकारी अफसर उसमें बढ़ेंगे । तो यह ऐसी बातें हैं जिन पर थोड़ा विचार करने की बात है । दूसरी बात नेता विरोधी दल ने यह फरमायी कि तकावी देने की बात बड़ी गलत है और कर्जा लेना भी बड़ा गलत है । मान्यवर, सुनने में बड़ा सुन्दर लगता है लेकिन आप स्वयं भी अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, आप भी जानते होंगे, किसी भी बैकवर्ड एकोनामी में, पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था में कर्जा लेकर उन्नति की जाती है और तकावी देकर उत्पादन की क्षमता बढ़ाना कोई गलत काम नहीं है । हां, एकबात अवश्य है कि यदि किसान उस पैसे को उत्पादन के कार्य में नहीं लगाता, उसको ब्याह शादी में लगा देता है तो वह गलत बात है । लेकिन यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जो पिछड़ा हुआ है जिसके पास स्वयं अपने को बढ़ाने के लिये साधन नहीं हैं, अपने विकास के साधन नहीं हैं, उसको राज्य की ओर से तकावी मिलनी चाहिये । मान्यवर, नेता विरोधी दल कहते हैं कि तकावी नहीं मिलनी चाहिये, ग्रेच्युइटी मिलनी चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि मान्यवर, कि यह उस सामन्तशाही प्रवृत्ति की झलक है कि जो अपने बढ़े हुए सरप्लस में से गरीबों को कुछ जुष्ठान्न देकर उनको तृप्त करके अपना राजकाज चलाता है, वह प्रवृत्ति उनके अनकांश में है । तकावी देकर के उनकी अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करना, उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना, नितान्त आवश्यक ही नहीं है नितान्त सिद्धान्तों के अनुकूल है, लोकतांत्रिक पद्धति के अनुकूल है और हमारी विकास पद्धति के अनुकूल है । इसलिये इस प्रकार की बात जिस सदन के नेता विरोधी दल कहें, उस सदन के लिये सोचना पड़ेगा कि वह अपनी कार्य-व्यवस्था कैसे चलाये । मान्यवर, थोड़ा सा समय और दे दें । मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कहा 'Congress Govt. has soft corner for the capitalist.' यह मैं मान्यवर, नहीं मानता । कांग्रेस सरकार के अन्दर कोई एक व्यक्ति हो, कांग्रेस दल के अन्दर कोई एक व्यक्ति हो, ऐसे एकाध व्यक्ति किसी भी दल के अन्दर हो सकते हैं, जिनको किसी खास पूंजीवादी व्यक्ति के लिये कुछ साफ्ट कार्नर हो, लेकिन जो दल की घोषित नीति रही हो उस नीति के विरुद्ध उसके ऊपर यह आरोप लगाना मैं समझता हूं उचित नहीं है । मैं आरोप लगाना चाहता हूं और जानना चाहता हूं नेता विरोधी दल से कि क्या उनके किसी घोषणापत्र में किसी राष्ट्रीयकरण की बात है, किसी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पब्लिक सेक्टर को वरीयता देने की बात है ? तो उनको यह बात कहना मुनासिब नहीं मालूम होता ।

मान्यवर, बहुत सी बातें थीं, लेकिन अब मैं अपने साथी उग्रसेन जी की बात की चर्चा बड़े अदब के साथ करना चाहता हूं । मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं .....

श्री अधिष्ठाता—

वह आपके पुराने साथी भी तो रह चुके हैं ।

श्री रामलखन शुक्ल—

जी हां, वह तो आप भी रह चुके हैं । और मान्यवर, इसीलिये तो मेरा यह साहस होता है कि मैं उनसे कहूं । उन्होंने कहा कि आज नेहरू बचाओ आन्दोलन छिड़ा हुआ है । मान्यवर, बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय उग्रसेन जी और उनके जैसे सोचने वाले नेताओं क तर्कों के आधार पर कहना चाहता हूं कि क्या नेहरू को बचाने की आवश्यकता है ? Nehru stands self defended. कौन बचायेगा नेहरू को ? हमारे जैसे कांग्रेसी बचायेंगे ? जब चुनाव होता है तब तो यह कहा जाता है कि नेहरू का रोलर चलता है और दूसरी तरफ यह कहा

जाता है कि नेहरू बचाओ आन्दोलन छिड़ा हुआ है । इसलिये यह बात नितांत भ्रमात्मक है । नेहरू को बचाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, उसकी हिफाजत, उनका चरित्र, उनकी लोकप्रियता करेगी । उनकी विद्वत्ता, उनकी शक्ति, उनका मनोबल, उनकी हिफाजत करेगा । हमारे जैसे लोग उनकी हिफाजत नहीं कर सकते । एक बात मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करूं कि यह नेहरू बचाओ आन्दोलन नहीं है । यह नेहरू गिराओ आन्दोलन की भूमिका तैयार की जा रही है । उस भूमिका को तैयार करने में समाजवादी दल, जो अपने को समाजवादी दल कहता है, अपने साथ प्रतिक्रियावादी शक्तियों को लेकर यह काम करने में तनिक भी हिचकता नहीं है । यह नेहरू गिराओ आन्दोलन आज कौन कर रहे हैं। जितनी प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं और जो फ्रस्ट्रेडेट लीडरशिप में आते हैं और जो आज इन राजनैतिक नेताओं की ओर प्रतिक्रियावादी शक्तियों को समझने में असमर्थ हैं वे यह चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की शक्ति समाप्त हो । वह देश को बहुत पीछे ले जाना चाहते हैं और मध्यकालीन स्थिति को देश में पनपाना चाहते हैं । इसी कारण से आज एक अनहोली अलायन्स किये हुये हैं । मैं उन समाजवादी बन्धुओं से निवेदन करूंगा कि वह इस बात को महसूस करें कि आज उनकी यूनिट के अन्तर दरार पड़ चुकी है । वे ही ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से यह शिकायत की गई थी कि जिला परिषद् के अन्दर चुनाव में अधिकारियों को वोट देने का अधिकार क्यों दिया गया और पहले कहा गया कि उनको अधिकार दिया जाय । तो इसमें कितना बड़ा विरोधभास है । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, हमारे सामने १९६३–६४ का जो बजट पेश किया गया है, उसको देखने के बाद मुझे मायूसी हुई। राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में जब हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत थी, हम यह समझते थे कि एक संतुलित बजट पेश किया जायगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि ४ करोड़ से ऊपर के घाटे का बजट पेश किया गया है। श्रीमन्, घाटे का बजट पेश करना कोई बड़ी और खास बात नहीं है लेकिन जब रुपया कम पड़ता है तो उस घाटे को पूरा करने के लिये जनता पर टैक्स का भार और डाला जाता है । पिछले सेशन में किसानों पर २५ फीसदी लगान में बढ़ोतरी हुई । राष्ट्रीय संकट था तो हम लोगों ने सरकार का साथ दिया । हमारा देश खतरे में था इसलिये हमने साथ दिया । हमने अपनी जिन्दगी के अनुभव से इधर ३, ४ महीने के अंदर क्या देखा कमाने वाले किसान और मजदूर तथा मध्यम वर्ग ने दिल खोलकर राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में मदद की । जनता के ऊपर टक्स बढ़ाया गया। उसने टैक्स भी दिया । बहुत सी जगह से यह खबर आई है कि जबरदस्ती की जा रही है, लेकिन उस जबरदस्ती को सहकर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सहायता की । जब इस बजट को देखा जाता है तो मालूम होता है कि पूंजीपतियों पर, राजे, रजवाड़ों और सरमायादारों पर इस सरकार का टैक्स बकाया है, कर्ज़ का बकाया है और सरकार की तरफ से उन लोगों की आरजू और मिन्नत भी होती हैं । वित्त मंत्री जी कहते हैं कि उन लोगों से अगर आप लोग अपने उस कर्जे को दे दें तो आप लोगों की बड़ी इनायत हो ।

हम लोग, कमानेवाली जनता किसान और मजदूरों ने, जिन्होंने देश की आजादी के लिये खून पसीना एक किया, यह महसूस किया कि जब देश पर संकट है, हमारी आजादी खतरे में है और उस आजादी की रक्षा होनी चाहिये तो हम लोगों ने देश की रक्षा में जी-जान से हिस्सा लिया । लेकिन यह पूंजीपति, सरमायेदार, सामन्तवादी, राजे, रजवाड़े जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया है, उसने इस समय भी देश की हिफाजत में अपने को पीछे कर लिया । इस बजट में ४ करोड़ से ऊपर का घाटा है लेकिन पूंजीपतियों के ऊपर आप ज्यादा टैक्स लगाने की बात नहीं सोच रहे हैं मैं ऐसा महसूस करता हूं। जिनके ऊपर सरकार का कर्जा है, किसान मजदूरों की गाढ़ी कमाई से जिनकी तिजोरियों में धन भरा हुआ है, सोना भरा हुआ है इस संकट काल में उनसे अपना रुपया वसूल कीजिये। मैं सरकार से यह मांग कर रहा हूं ।

एक बात मैं आपकी आज्ञा से सरकार को बतलाना चाहता हूं । समाजवाद का एक मामूली सिद्धांत है और यह सरकार अपने को समाजवादी कहती है । आज संसद् और प्रदेश की असेम्बलियों

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

में इजारेदार पूंजीवाद की घुसपेठ हो रही है। समाचार पत्र उनके कब्जे में हैं, धन उनके पास है और वे अपने प्रतिनिधियों को यहां भेज कर सरकार की बुनियादी नीतियों को भी बदलने की सोच रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनका यह प्रयत्न बहुत दूर तक कामयाब होते होते रुका है। हमारे मंत्रिमंडलों में भी ऐसे लोग हैं जो उनके प्रवक्ता हैं। समाजवाद का एक बुनियादी उसूल है जिसमें मुझे प्रजा समाजवादी और समाजवादी में कोई फर्क नहीं है। कहा गया है कि "अकेला पूंजीवाद ही इस तथ्य के लिये जिम्मेदार है कि २० वीं शताब्दी उत्पादन शक्तियों की अथाह अभिवृद्धि और महान् वैज्ञानिक प्रगति की शताब्दी, करोड़ों लोगों की गरीबी का खात्मा नहीं कर सकी है, धरती पर बसने वाले तमाम लोगों के लिये नैतिक और आत्मिक मूल्यों की प्रचुरता की व्यवस्था नहीं कर सकी। उसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि सम्पूर्ण आबादी के लिये सभी चीजों की प्रचुरता को सुनिश्चित करने के लिये, उन्नत अर्थतंत्र, विज्ञान और इंजीनियरिंग का उपस्थित होना ही पर्याप्त नहीं है। सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि उन सभी पर किसका स्वामित्व है और फलस्वरूप उनसे लाभ कौन उठाता है।" इसी से ये सरकार पूंजीपतियों पर हाथ उठाने में डरती है। मैं वित्त मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि हम लोगों ने, देश की जनता ने सुरक्षा फंड में दिया है और देश की जनता अपनी आजादी को जाने भी न देगी, लेकिन यह जो ४ करोड़ का घाटे का बजट है इसके लिये उनको आप पहले पकड़िये और उनकी पूंजी को सुरक्षा के लिये इस्तेमाल कीजिये।

एक दूसरी बात भी कहनी है। मुझे दुख है कि एक सांप्रदायिक पार्टी आज मुख्य विरोधी दल के रूप में यहां बैठी है। मुझे उम्मीद थी कि प्रजासमाजवादी और समाजवादी पार्टियां मिल जाने के बाद यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी मुख्य विरोधीदल के रूप में यहां काम करेगी, लेकिन दुख है कि आज भी वही पार्टी यहां बैठी है जिससे हमारा कोई मेल नहीं खाता। कल की ही बात है, जनसंघ के नेता राजा कुंवर श्रीपाल ने बड़े जोश-खरोश से भाषण दिया। तमाम चीखे-चिल्लाये। यहां से निकलने के बाद मैंने पूछा कि हमको गद्दार कहते हो, ठीक है, कह लो लेकिन १९४८–४९ की यह आपकी जो पलटन यहां असेम्बली में बैठी है वह १९४२ में कहां चली गयी थी? कौन जेल गया था? उन्होंने कहा राजा मनकापुर मैंने कहा कि वह आपकी पार्टी के नहीं स्वतंत्र पार्टी के हैं और मैं समझता हूं कि जन संघियों के पास देश भक्ति का कोई प्रमाण भी नहीं है। हमारे साथी संतसिंह यूसुफ साहब ने कहा था कि जनसंघ को बैन करना चाहिये, मैं जनसंघ के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेक संघ को भी बैन करने की बात कहता हूं। हमारे पास कुछ प्रमाण हैं। वित्त मंत्री और सरकार के सदस्य बैठे हैं। गत तीन, चार महीनों में जनसंघ के प्रमुख पत्र "आर्गनाइजर" ने कैसे कैस घात किये हैं उनके कुछ उद्धरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उनके गुरु गोलवलकर ने २७ अगस्त, १९६२ के ईश्यू में पृष्ठ तीन पर कहा था कि "चन्देबाजी या कोष एकत्र करना हमारा काम नहीं है।"

गुरु गोलवलकर ने ३ दिसम्बर, १९६२, के मुख्य पृष्ठ पर कहा है "सोना स्त्री धन है। सोना मत छुओ। भारतवर्ष में आदि काल से सोना परिवार का मुख्य बचत धन और विपत्ति काल में सहायक माना जाता रहा है। सोने का अधिकांश भाग स्त्री धन है जिसे पति को भी लेने का अधिकार नहीं है जबतक कि वह पति पतित न हो जाय। इसलिये हम यह सलाह देते हैं कि सरकार जो सोना लेने का प्रयास कर रही है वह अपना हाथ हटावे। सरकार हमारे सारे अधिकारों को छीन रही है। अब इसे हमें और अधिक नष्ट करने का अधिकार नहीं है। सरकार हमारे मां के सोने से अपना हाथ दूर रखे।"

उसके बाद उनके गुरु गोलवलकर का एक लेख और है १२ नवम्बर, सन् ६२ के "आर्गनाइजर" के पृष्ठ ५ पर—"आज हमारे पास छोटी फौज, पहले से कम हथियार, तथा और भी कम गोलियां हैं। लड़ाकू जहाजों और फौजी सामान ढोने वाले जहाजों के उत्पादन की उपेक्षा की गई है। यहां तक कि हमारे पास एक भी एंटी एअर क्राफ्ट गन नहीं हैं।"

इसके अतिरिक्त पृष्ठ ९ पर "गांधी जी और सोना। इंडिया दैट इज भारत मैत्रीक्लास द्वारा। "हमारे देश के लोग सुरक्षा कोष के लिये पैसा इकट्ठा करते रहे हैं, दान देते रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि सोना देना रुपये देने से अधिक आवश्यक है क्योंकि सोने से बन्दूक, मशीनगन और हथगोले खरीदे जायेंगे। अगर आज इस मौके पर गांधी जीवित होते तो अपने इस अहिंसा के देश में देखते कि आज सोने की क्षमता को प्राथमिकता दी जा रही है प्रभावकारी हिंसात्मक हथियारों को खरीदने के लिये।"

फिर कहते हैं "नेहरू पवित्र गाय नहीं है (इसका मतलब है कि गाय पवित्र है और सब अपवित्र हैं)" 'इससे किसी को परेशान होने की क्या बात है यदि कोई यह कहता है कि यह अच्छा होता यदि जवाहरलाल भी चले गये होते। निश्चित रूप से जवाहरलाल कोई पवित्र गाय नहीं हैं।" किस तरह से इन हत्यारों ने गांधी जी को मारा है उसी तरह से जवाहरलाल को भी मारने की साजिश है। इसलिये हम नारा देते हैं कि जनसंघ के साथ आर० एस० एस० को भी बैन किया जाय। जवाहरलाल जी ने कहा था कि आर० एस० एस० फासिस्टवाद का भारतीय रूप है। और ये लोग देश में गैर कानूनी तरीके पर आर० एस० एस० के रूप में फौजी संगठन तैयार कर रहे हैं।

हमसे कहा गया कि तुम देश भक्ति का सबूत दो। यह कम्युनिस्ट पार्टी से कहा जाता है जिसमें भगतसिंह के साथी हैं, जिसमें काकोरी केस के षडयंत्र के साथी हैं, गदर पार्टी के लोग हैं चटगांव षडयंत्र और सहजनवां, पिपरी डीहं और नन्दगंज इत्यादि के क्रांतिकारी हैं। जिसमें १९४२ के सतारा की पत्री सरकार के साथी हैं। हमसे कहा गया कि तुम देशभक्ति का सबत दो क्योंकि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन का लिंक है। हमने कहा कि ठीक है, हम इम्तहान देने के लिये तैयार हैं और श्रीमन्, हम इम्तहान में खरे भी उतरे। हमारी नेशनल कौंसिल ने फैसला किया कि देश के डिफेंस के लिये हर एक कम्युनिस्ट कन्धे से कन्धा मिलाकर जुट जाय हमने देश की सुरक्षा के लिये गांव गांव और गलियों गलियों में और एक एक कदम पर सुरक्षा के काम में डट कर योग दिया। डांगे ने पूर्वी योरोप और कम्युनिस्ट देशों में जाकर चीन की गलत नीति के खिलाफ फ्रंट तैयार किया। बख्शी गुलाम मुहम्मद तक ने कहा है कि आज देश की तटस्थ नीति जो कायम रही है उसी का परिणाम है कि आज चीन के साथ कोई देश है तो वह है अल्बानियां और पाकिस्तान सिर्फ दो देश। जो लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान को अमेरिका और इंगलैंड के गुट में चले जाना चाहिये तो उन्हें यह सोचना चाहिये कि पाकिस्तान क्यों चीन के साथ है। चीन जो चाहता है वही चीज पाकिस्तान कर रहा है। क्योंकि रूस और चीन में आज संघर्ष है और अमेरिका का मुख्य दुश्मन रूस है और वह चाहता है कि रूस और चीन में मत-भेद बना रहे। जो काम पाकिस्तान चीन के लिये कर रहा है, अमेरिका के दोस्त आर० एस० एस० वाले उसी चीन का काम हिन्दुस्तान में कर रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि इन पर बैन होना चाहिये क्योंकि ये ही पंचमांगी हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य सीधा आक्षेप न करें तो अच्छा होगा।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

अधिष्ठाता महोदय, हमारी मजबूरियों को आप समझते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप हमारे माध्यम से केवल अपने विचारों को रखें।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

अब आखरी बात मुझे अपने गाजीपुर जनपद के बारे में कहनी है। वहीं से मैं आता हूं। हमारे जिले के लिये इस बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है। हमारे माननीय वित्त मंत्री और नियोजन मंत्री भी वहीं के करीब से आते हैं। जब मैं पूर्वी जिलोंकी बात करता हूं तो यह बात नहीं कि मुझे पश्चिमी जिलों का तरक्की देख कर कोई दुख होता है, मुझे उससे भी खुशी होती है, वे जिले

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

दूधों नहायें, पूतों फलें, मगर इस जिले की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये था। गाजीपुर जिले की आबादी १३,२१,५७८ है, आबादी का घनत्व १०१२ व्यक्ति प्रति वर्गमील है। ६६.६ प्रतिशत आबादी ग्रामीण अंचलों में बसती है। प्रति यक्ति भूमि .६१ एकड़ पड़ती है। वास्तविक जोत की भूमि का .५० प्रति व्यक्ति औसत है। ७० प्रतिशत जोत ३ एकड़ से भी कम है। इस जनपद में जोत में आई धरती में ३७.३ प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित हो पाता है। इस जनपद में ८४,००० एकड़ क्षेत्र में पानी जमा रह जाता है। इस जनपद की चारों तहसीलों में २५,६५१ एकड़ ऊसर भूमि है। इस जनपद में ७६.५ मील पिच रोड, ६५ मील कंकड़ रोड और ३६१ मील कच्ची रोड है। पुलों के अभाव में बनारस तथा बलिया से संबंध कटा रहता है। यहां पर १ लाख के पीछे १२ मील पक्की सड़क है जबकि राज्य का औसत १७ मील है। यह ग्रिड एन्ड स्टार फारमूले के अनुसार १६.५ मील होना चाहिये। आज वहां पर एक पुल न होने के कारण उसका संबंध कई जिलों से कटा हुआ है। मैं मांग करता हूं कि गाजीपुर में रेल रोड पुल परमेठ, हाटा लठदीख, शादियाबाद में नदियों पर पक्का पुल बने जमनियां से सैदपुर का लिक जोड़ने के लिये पक्की सड़क बनाई जाय। कल कारखानों के नाम पर वहां पर केवल एक छोटी सी ओपियम की फैक्ट्री है। हमारे यहां पानी की आवश्यकता है, हमारे यहां कल कारखानों की आवश्यकता है, हमारे यहां यातायात के साधनों की आवश्यकता है, हमारे यहां पुलों की आवश्यकता है, पक्की सड़कों की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हुआ।

कारागार मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

श्रीमन्, कल से जो विवाद इस सदन में चल रहा है, उसको मैंने बड़ी गंभीरता पूर्वकसुना। इस संकटकाल के समय माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उस पर विवाद के लिये मैं समझता था कि कम से कम समय लिया जायेगा। मेरा विश्वास था कि विरोधी दलों के नेतागण थोड़े समय में अपने आवश्यक सुझावों को प्रस्तुत कर इस विवाद को समाप्त करेंगे, किन्तु श्रीमन्, ऐसा न हो सका। मैंने माननीय विरोधी दल के नेता, श्री दुबे जी के निस्तार और लचर भाषण को भी सुना। मैंने बहुत कोशिश की कि उनके भाषण से मैं कुछ प्राप्त करूं, किन्तु वह व्यर्थ रहा। श्रीमन्, उन्होंने जो बातें कहीं उनका कुछ तो संबंध सुरक्षा से था जिसका कि अधिकांश भार केन्द्रीय सरकार के कन्धों पर है। कुछ योजनाओं के संबंध में कहा। एक बात और भी उन्होंने कही कि यू० पी० में बन्दूक बनाने के कारखाने शुरू किये जावें। साथ ही यह भी कहा कि ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे राइफिल बनाना जानते हैं। इस प्रकार के कारीगरों को सहायता की जाय। मैं समझ नहीं पाया कि क्या राइफिल के उद्योग को वह कुटीर उद्योग में बदलना चाहते हैं। क्या उन लोगों के लिये जो आज आगरा और मध्य प्रदेश की कछारों में छिपकर डकैती डालते हैं उनके कार्य को पनपाना चाहते हैं। मैं उनका अभिप्राय नहीं समझ पाया।

इस बजट में सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली तकावी की बात को भी उन्होंने आलोचना की और कहा कि इस प्रकार उन्हें अपनामित करना है। किन्तु शासन का कर्तव्य है कि इस प्रकार के लोगों को अधिक से अधिक सुविधायें दे। यदि उन्होंने इस ओर संकेत किया होता तो मुझे बड़ी खुशी होती, कि सैनिकों के परिवारों को जो रणक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गये हैं या अपाहिज हो गये हैं, उन्हें कुछ जमीन मैं अपने फार्म में से दूंगा। यदि ऐसी घोषणा वह करते तो हमारे सैनिकों का उत्साह बढ़ता। शासन के द्वारा मिली सहायता का उनको उतना आकर्षण नहीं है जितना जनता के द्वारा दी जानेवाली सहायता में होता है। यदि उन्होंने २,४,६ परिवारों को इस तरह की सहायता देने का आश्वासन दिया होता, तो मेरे पास भी मेरे बाप-दादाओं की जो २,४,१० बीघा जमीन है उसे मैं भी देने की घोषणा करता।

उन्होंने सुलह की बात को भी बड़ी तिरस्कार की दृष्टि से देखा और उसकी आलोचना की। कुंवर श्रीपालसिंह जी का भाषण भी मैंने सुना। उनके ओजस्वी भाषण को सुनकर मुझे एक पुरानी

बात याद आ गई । एक दिन बरसात के मौसम में एक साथी ने कहा कि आपको आल्हा सुनवाई जाय । मैंने कहा कि भाई, वह तो इतिहास के परे की चीज है । उसे सुनवा कर क्या करोगे । तो उन्होंने कहा कि ऐसा सुनानेवाला है कि उसने अमरसिंह की आल्हा जब सुनाई तो जोश में आकर एक आदमी का तलवार से सिर काट दिया । लेकिन मुझे संतोष इस बात का था कि श्रीपालसिंह जी के हाथ में तलवार नहीं थी, केवल कुछ कागज ही थे । मैंने उनकी इस आलोचना को भी सुना जो उन्होंने सांस्कृतिक आधार पर सुरक्षा योजनाओं की! की । अब से ३० वर्ष पहले हमारे देश में आर्य समाज और सनातन धर्म के बड़े शास्त्रार्थ हुआ करते थे, जिनमें लोग वेदों की बड़ी दुहाई देते थे । वह किसी विवाद में कोई वेद का उद्धरण दिया करते थे, उससे आगे की बात को वहीं छोड़ दिया करते थे और अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया करते थे । हमारे माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने इसी प्रकार का प्रयास किया । उन्होंने वीर गाथाओं का उदाहरण देते हुये इस बात पर भी आपत्ति की कि हमने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है । वह महाभारत की उस बात को भूल गये जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि गुरू जी, अर्जुन पर बड़ा स्नेह मालूम होता है, हमारे सेनापति बराबर वीर गति को प्राप्त होते जा रहें हैं, अर्जुन आज तक भी जीवित हैं । तो उन्होंने कहा था कि अच्छा, इसका इन्तजाम किया जायगा और दूसरे दिन चक्रव्यूह की रचना की । किन्तु कृष्ण ने अर्जुन को वहां से हटाकर संतप्तों को ओर लगाया और उस चक्रव्यूह में एक सेनापति वीर काम में आया । श्रीमन् युद्ध खाली बातों से नहीं लड़ा जाता है । इसके लये बुद्धि, कौशल और नीति की भी आवश्यकता होती है । बड़ी दुहाई दी गई कि हमारी परम्परा रही है कि न दैन्यं न पलायनम् । इस प्रकार सरकार ने इस परम्परा को तोड़ा है कि तु हमने कभी भी इस बात को नहीं अपनाया है कि हम कमजोरी दिखावें या हट जावें । मुझे स्मरण है कि सन् १९४२ के आन्दोलन के सिलसिले में हमारे बहुत से साथी जेलों में बन्द थे तो उनसे अंग्रेज शासकों ने कहा था कि इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दो, जिसमें लिखा था कि हमारा हिन्सा पर विश्वास नहीं है । हम तोड़ फोड़ की घटनाओं को उचित नहीं समझते, हमको छोड़ दिया जाय । मुझे याद है कि लोगों ने कहा था कि हम अहिंसा की बात को प्रत्येक २६ जनवरी को दोहराते हैं, हमारा विश्वास है अहिंसा पर लेकिन छूटने के नाम से हम कलम नहीं उठा सकते । मुझे वह दिन याद है कि जब कांसपरेसियों में लोगों को फांसा जाता था और उनसे कहा जाता था कि मुखबिर बन जाओ, सरकारी गवाह बन जाओ, तुम छोड़ दिये जाओगे, परन्तु लोग उससे नहीं हटे और हंसते हंसते फांसी की रस्सी को चूमा और न दैन्यं न पलायनम पर डटे रहे ।

उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है । सुरक्षा के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व से केन्द्रीय सरकार पर है, लेकिन इस आपातकालीन समय में इस प्रदेश में जिसकी सीमायें ६०० मील लम्बी हैं, पिछली बार जब एक वायुयान खरीदने की बात आई तो उसकी बड़ी अयलोचना की गई । जिस उपहास के साथ माननीय श्रीपालसिंह जी ने उसकी खिल्ली उड़ाई वह आपतकालीन समय के लिय कुछ उचित नहीं था । सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर है और आप पर भी है, प्रत्येक नागरिक पर है । लेकिन मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जहां हम अपनी आजादी की रक्षा करना चाहते हैं वहां हम आजादी को बेचकर या उसे, गिरवी रखकर,ऐसा नहीं कर सकते । हम इसके लिये कतई तैयार नहीं हैं कि पश्चिमी या किसी गुट में मिलें या अमरीका की सेना को यहां बुलावें। हमारे पास हथियारों की कमी होगी तो हम १०,१० सिपाहियों को एक बन्दूक से लड़ने के लिये आगाह करेंगे देश की रक्षा इससे नहीं हो सकती है कि हम देश की स्वतंत्रता को बेचकर, उसे दूसरे राष्ट्रों को गिरवी रखकर, उन लोगों का अपने ऊपर अधिपत्य कायम करें । सुरक्षा की तैयारी इस देश के नागरिकों को स्वयं अपने बलबूते पर करनी होगी । सुरक्षा की तैयारी की बात कहते समय पाकिस्तान बनवाने की बात भी कही गयी । मैं उन बातों को सामने लाना नहीं चाहता था लेकिन अब केवल इतना ही कहूंगा कि आज जो बड़े बड़े नेतागण उस की आलोचना करते हैं, वह उस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान को स्वीकार कर लेने की वकालत की थी, जिस समय महात्मा गांधी अहमदनगर फोर्ट में बन्द थे, उनके पास भी यह सुझाव ले जाया गया कि इसको मान लिया जाय । हम उसको स्वीकार करना नहीं चाहते थे और न उसको स्वीकार करने के पक्ष में थे लेकिन जो लोग आज इस बात को कहते हैं

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

वे ही उसके जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके द्वारा फैलाई गई साम्प्रदायिक भावना के कारण ही इस देश का विभाजन हुआ है ।

यह बात भी कही गयी कि पंचमांगियों को फांसी दे दी जाय । आज तक कोई ऐसा पैमाना नहीं बन पाया कि हम पता लगा सकें कि कौन पंचमांगी है और कौन नहीं । लेकिन एक बात जरूर है कि देश की सुरक्षा का नाम लेकर देश के वातावरण को दूषित करना, जनता का मनोबल गिराना भी एक बहुत बड़ा अपराध है ।

श्रीमन्, मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था और जवाब भी देना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण आपके माध्यम से केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि जो लोग शासन में हैं वे समय आने पर देश के लिये सब कुछ बलिदान करने के लिये तैयार हैं । यह बजट फौजी नहीं, योजनाओं का बजट है । आइये हम सब मिलकर योजना के इस दूसरे मोर्चे पर लड़ें । जिससे देश की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

अधिष्ठाता महोदय, यद्यपि समय बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैं इस बात पर खेद प्रकट किये बिना नहीं रह सकता कि जो वादविवाद यहां चल रहा है, उसमें थोड़े से माननीय सदस्यों के भाषणों को छोड़कर, सभी का स्तर नीचा रहा है । मुझको शिकायत केवल इस बात की है कि नीतियों और कार्यक्रम की आलोचना के बजाय व्यक्तियों और उनकी नीयत पर आक्रमण करने की ओर ही लोगों का ध्यान अधिकतर रहा किसी ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगा दिया जाय,किसी ने कहा जनसंघ पर रोक लगनी चाहिये, कुछ लोग इस विचार के थे कि जो सन् ४२ में जेल नहीं गया वह देशभक्त नहीं हो सकता, कुछ लोगों ने कहा कि जो राजे और महाराजाओं के यहां जन्मे हैं वे देशभक्त नहीं हो सकते इस प्रकार की बातें संकीर्णता की द्योतक हैं । हम छुआछूत को मिटाना चाहते हैं, उसको पुरानी बात समझते हैं । परन्तु इस तरह की बातें करना कि किसी वर्ग या किसी पार्टी में खराब लोग ही हैं यह नये जमाने की छुआछूत है और उतनी ही मूर्खता पर आधारित है, जितनी पर पुरानी छुआछूत ।

व्यावधान

श्री अधिष्ठाता--

मैं बार बार शांति रखने का आग्रह कर रहा हूं, लेकिन बहुत स जिम्मेदार लोग भी उसकी ओर ध्यान न देकर बराबर व्यवधान उपस्थित कर रहें हैं । (श्री बैजनाथ सिंह जी के कुछ कहने का प्रयत्न करने पर) माननीय बैजनाथसिंह जी, मैं यह शोभनीय नहीं समझता कि किसी माननीय सदस्य का नाम लेकर कहूं कि उनकी वजह से अशांति हो रही है ।

श्री भानुप्रताप सिंह--

हम लोग इस बात का वचन देकर यहां आये हैं कि हम जनतंत्र की रक्षा करेंगे परन्तु जिस प्रकारके यहां भाषण होते हैं, उससे मुझे यह भय लगता है कि जनतंत्र की रक्षा के लिये नहीं बल्कि हम गृह युद्ध तैयारी कर रहें हैं यह इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है यदि इस सदन में इस प्रकार की बातें चलती रहीं वे और देश में फैलेंगी, इनसे एक तरह से गृह युद्ध की नींव पड़ेगी । यद्यपि मै साम्यवादी दल की नीति से बिलकुल असहमत हूं फिर भी स्पष्ट कहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि उस पर कोई बैन लगाया जाय। क्योंकि इसके बाद हमें मानना पड़ेगा कि उनके विचारों में इतनी शक्ति है कि हम उनको अपने विचारों से बदल नहीं सकते । यह हमें मान लेना पड़ेगा कि सिवा इनको जेल में बन्द करने के और कोई उपाय नहीं है कि हम उनके विचारों को देश में फैलने से रोक सकें । तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं और इसीलिये किसी भी विचारधारा को इस देश में बैन किये जाने के मैं विरुद्ध में हूं ।

इतना कह लेने के बाद कुछ बातों में जो अन्य लोगों से मेरी सहमति है, उसके विषय में भी कुछ कह देना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देना है कि इस बजट में उन्होंने कम से कम कृषि के लिये कुछ अधिक धन दिया है। जहां तक मैं समझ पाया जितना, देना चाहिये, उससे बहुत कम ही दिया गया है, फिर भी एक कदम ठीक दिशा में बढ़ने वाला उठाया गया है, जिसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

इसके बाद मैं माननीय उग्रसेन जी को बधाई और धन्यवाद दोनों देता हूं क्योंकि उन्होंने आज जो भाषण दिया उस भाषण के बाद मुझे स्वतंत्र पार्टी की तरफ से कहने के लिये बहुत कम बातें रह गयी हैं। उन्होंने हमारी सुरक्षा और विदेशी नीति का पूर्ण रूप से समर्थन किया ही, और यहां नहीं बल्कि पार्लियामेंट में भी उसका समर्थन कर रहें हैं। परन्तु आज मुझे यह सुन कर विशेष रूप से प्रसन्नता हुई कि उन्होंने कहा 'यह योजना गरीबों पर टैक्स बढ़ाने वाली बेरोजगारी बढ़ाने वाली है।" वे हमसे अब बहुत निकट आगये हैं, थोड़ी ही कसर बाकी है। (हंसी)

श्रीमन्, कल दो बातें और कही गयीं। साम्यवादी पार्टी की तरफ से माननीय यूसुफ जी ने एक प्रस्ताव रखा कि जिस किसी की १,५०० रुपये से ज्यादा आमदनी हो, वह ले ली जाय सुरक्षा कार्य के लिये या राष्ट्रीय कार्य के लिये। माननीय मिश्रा जी ने एक सुझाव दिया कि गांव वाले छोटे किसानों की मालगुजारी में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसे माफ कर दिया जाय और बड़े किसानों से वसूल करके उस कमी को पूरा किया जाय। श्रीमन्, मैं इन दोनों प्रस्तावों को एक में मिला कर उसे थोड़ा व्यापक बना देता हूं। वह इस प्रकार कि गांव वाले छोटे किसानों को, जिनके ऊपर भी आपने सरचार्ज लगाया है, उनको छोड़ दीजिये और १,५०० रुपये से अधिक जिसकी भी आमदनी हो, वह चाहे किसी व्यवसाय, उद्योग या करोबार से होती हो, उसकी अतिरिक्त आमदनी यदि वह उसे उत्पादक कार्यों में न लगायें, तो उसको आप अवश्य ले लीजिये। स्वतन्त्र पार्टी की तरफ से मैं इसका अनुमोदन करने के लिये तैयार हूं और हमारी तरफ के इधर बैठने वाले जितने भी माननीय सदस्य हैं, उनमें कोई भी ऐसा न होगा जो इस प्रस्ताव का समर्थन न करे। क्या आपकी सरकार इसके लिए सहमत है? क्या सरकार में इतना साहस है इस सुझाव को स्वीकार कर ले यदि वह उसे स्वीकार कर ले तो उसे मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा।

उसके बाद मैं अब बजट के विषय में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। जिस समय यह सरचार्ज लगा तो उस समय हमारे माननीय मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री, सभी ने यह आश्वासन दिया था कि बहुत बड़े पैमाने पर मितव्ययिता की जायगी। लेकिन वही कहावत चरितार्थ हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। ठीक उसी के अनुसार वह १,९७३ करोड़ के बजट में केवल सवा करोड़ की किफायत करने में सफल हुये हैं। जोड़ने पर मालूम होगा कि यह १०० रुपये में ६५ नया पैसा यह होता है। गरीब से गरीब किसान और मजदूर की अनपढ़ गृहिणी भी इससे अधिक अपने घर के बजट में किफायत कर सकती है जितनी कि वित्त मंत्री जी ने कर के दिखाई है। मैं उन लोगों में से हूं जो नियत पर विश्वास करते हैं, मैं यह नहीं कहता कि माननीय वित्त मंत्री जी जानबूझकर फजूलखर्ची करते हैं या सरकार को इस में कुछ मजा आता है कि गरीबों से टैक्स लेकर उसका दुरुपयोग किया जाय। मैं इसको नहीं मानता। वह एक प्रकार के शिकंजे में फंसे हुये हैं। जब तक वह उससे नहीं निकलने पायेंगे तब तक इसके सिवा कोई दूसरा नतीजा नहीं निकल सकता कि हर साल टैक्स बढ़ता चला जाय। वह शिकन्जा क्या है? मैं समझता हूं कि यह सरकार कहने के लिये तो सरकार है लेकिन वास्तव में यह दो चक्कियों के पाटों के बीच पिस रही है। ऊपर से प्रधान मंत्री नेहरू और प्लानिंग कमीशन और नीचे से ब्यूरोक्रेसी। इन की सारी योजनायें ऊपर से बनकर आती हैं, जिनमें कि इन को मामूली सा संशोधन करने का भी अधिकार नहीं है, चलाती इनको ब्यूरोक्रेसी है यह तो बीच में केवल पोस्ट आफिस का काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी के लिये क्या कहा जाय, एक कहावत है, 'मैन प्रोपोजेज गाड डिस्पोजेज' वही यहां पर भी इस रूप में लागू है कि 'मिनिस्ट्री प्रोपोजेज ब्यूरोक्रेसी डिस्पोजेज'। यह करना भी कुछ चाहें तो नहीं कर सकते। मेरा अपना अनुभव है मैं कई मंत्रियों से मिला, उन्होंने आदेश दिये

[श्री भानुप्रताप सिंह]

कि इस प्रकार से काम होना चाहिये। उसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूं लेकिन जितने कार्यों के लिये आजतक उन्होंने आदेश निकाले, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ जिले में। यह दशा है ब्यूरोक्रेसी की।

मैं यह बताना चाहता था कि वास्तव में कठिनाई क्या है। जैसा मैंने बताया उनको आदेशों का पालन करना पड़ता है, प्लानिंग कमीशन के और विशेष रूप से प्रधान मंत्री नेहरू के। मैं प्रधान मंत्री नेहरू के विषय में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हमारे मंत्रिमंडल के मंत्रिगण का आधे से ज्यादा समय यह अनुमान लगाने में लग जाता है कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो प्रधान मंत्री नेहरू की उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। अभी ५ जनवरी को नेहरू जी यहां आये थे। उन्होंने कहा कि यह जो ब्लैक आउट का प्रबन्ध किया जाता हैऔर ट्रेन्चेज खोदी जाती हैं वह मूर्खता है। मैं इस प्रश्न के मेरिट्स पर नहीं जाता लेकिन एक सबसे विचित्र बात जो मुझे लगी वह यह कि दूसरे ही दिन मुझे दो मंत्रियों और दो सरकार के उच्च अधिकारियों से मिलने का अवसर मिला और जिस प्रकार से प्रधान मंत्री जी ने इस ब्लैकआउट और ट्रेन्चेज की खिल्ली उड़ाई थी ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी माननीय चन्द्रभानु गुप्त की खिल्ली उड़ाई। वह मंत्री जो, उनको पहले से सलाह दे सकते थे, जब कि उन की निगाह में गलत काम यहां हो रहा था, उसको वह उनसे कह कर रोक सकते थे परन्तु उनमें उस समय इतना साहस नहीं था पर जैसे ही प्रधान मंत्री नेहरू ने कहा वैसे ही उन्होंने मजाक उड़ाना आरम्भ कर दिया। प्रधान मंत्री का आज से ४० वर्ष पहले यह विचार बन गया था कि देश की समृद्धि और हित इसी में है कि अधिक से अधिक कारोबार, खेती, और उद्योग धंधों पर सरकार का अधिकार हो जाय। इसी विचार धारा के अनुसार सारे देश का काम चलाया जा रहा है। जब तक यह विचार धारा नहीं बदलेगी तब तक सरकारें सारे कामों को स्वयं करने की कोशिश करेंगी। जैसे खेती, उद्योग धंधे, रोजगार, यहां तक कि ताल पोखरों में मछली पकड़ना आदि भी तब तक यह निश्चित है कि सरकार का खर्चा बढ़ता जायगा। उनका कार्य-क्षेत्र जितना ही बढ़ेगा उसी के अनुसार खर्चे का भी उनको प्रबन्ध करना पड़ेगा। जो लोग इस पक्ष के हैं कि अधिक से अधिक सरकार का कार्य क्षेत्र बढ़ना चाहिये उनको कोई अधिकार नहीं है कि वे इस बजट की आलोचना करें। यदि आप समाजवाद की ओर बढ़ेंगे तो मैं कहता हूं ऐसे बजट से, टैक्सों की वृद्धि से, नौकरशाही की वृद्धि से, बेरोजगारी की वृद्धि से छुटकारा नहीं हो सकता। मैंने अपनी बुद्धि के दरवाजे को बन्द नहीं किया, मैं समाजवाद के सामने आज भी नतमस्तक हो सकता हूं, यदि देश को उससे लाभ होने की आशा हो लेकिन समाजवाद ने इस देश में १५ वर्षों के अन्दर क्या किया है। इन १५ सालों के समाजवादी कार्यक्रम के बाद औसत भारतीय को जितना भोजन पहले मिलता था उससे १ छंटाक भी बेशी नहीं मिलता है, जितना कपड़ा वह पहनता था वह, यानी १६ गज प्रतिवर्ष, उससे आज उसको १ फिट भी ज्यादा कपड़ा नहीं मिलता है। बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। यदि इन चीजों की दवा समाजवाद ने की होती तो मैं भी उसे स्वीकार कर लेता। हमारे साम्यवादी मित्रों को यह शिकायत है कि कांग्रेस का समाजवाद तो नकली है, असली समाजवाद उन्हीं का है। भारत को जब स्वराज्य मिला उसके एक साल बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनी परन्तु आज वहां जितनी गरीबी और भुखमरी है उतनी शायद भारत में न कभी थी और न शायद कभी होगी। उन्होंने अपने तरीके से क्या प्राप्त किया है? अगर आज जिनको वह पूंजीवादी देश कहते हैं, आस्ट्रेलिया, कैनाडा, इत्यादि से चीन को गेंहूं न मिले तो वहां के करोड़ों निवासी मर जायं तड़प तड़प कर और फिर भी हमारे साम्यवादी मित्र कहते हैं हमारा तरीका ठीक है। मैं पूंजीवाद की वकालत नहीं करता, मैं स्वयं पूंजीवाद में, जैसा वह प्रचलित रहा है, उसमें विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन यह मैं कहता हूं समाजवाद ने भी हमको कोई रास्ता नहीं दिखाया है। हमको और आपको मिल कर तीसरा रास्ता ढूंढ़ना पड़ेगा। समाजवाद व्यवस्था की स्थापना करने का जब भी प्रयत्न होता है तो सरकार की शक्ति बढ़ती है, टैक्सेज बढ़ते हैं, खर्चा बढ़ता है। १९५०-५१ में ६४ करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया था। इस वर्ष २४३ करोड़ रुपया खर्च करने का प्रस्ताव है पूंजीगत और राजस्व दोनों मिलाकर। यह वृद्धि ३८० प्रतिशत की हुई है।

१२ सालों के अन्दर । और औसत नागरिक की आय में कितनी वृद्धि हुई है १.३ प्रतिशत की । समाजवाद की विशेषता है कि सर्वसाधारण नागरिक तो वहीं का वहीं बना रह जाता है परन्तु सरकार की शक्ति बढ़ती रहती है। श्रीमन् इतनी बातों के बाद मैं कुछ कृषि के विषय में भी कहना चाहता हूं क्योंकि यह मेरा प्रिय विषय है। जैसा मैंने पहले कहा, सरकार कुछ हद तक ठीक दिशा में चली है । हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि खाद, पानी और बीज, पहुंचाने की सरकार कोशिश करेगी और इन्हीं तीन बातों को उन्होंने मुख्य माना है । मैं उनसे सहमत हूं कि ये तीन बातें आवश्यक हैं । परन्तु मैं उनसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । पहली बात तो यह कि इस साधारण से तीन, चार शब्दों के सबक को कि अच्छी खाद दो, अच्छी सिंचाई करो और अच्छा बीज बोओ यह सरकार क्या, पहले की भी सरकार बहुत दिनों से किसानों को सिखा रही है और करोड़ों, अरबों रुपया इस सबक को सिखाने पर व्यय हो चुके हैं परन्तु क्या कारण है कि किसान इस सबक को नहीं सीख पाये । सरकार को इस पर विचार करना चाहिये क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है। यद्यपि एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा कि टार्गेट भले ही न पूरे हुये हों परन्तु उत्पादन बढ़ा है। मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है । तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्ष बिल्कुल बेकार चले गये। स्थिति कितनी गंभीर है इसका अनुमान इससे होता है कि प्रथम और द्वितीय योजनाओं में कृषि का उत्पादन केवल ३.६ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ा जिसमें से २.०५ प्रतिशत क्षेत्रफल के बढ़ने के कारण और विकास के उपायों के कारण केवल १.५ प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है । यदि हमको तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्राप्त करना है तो अगले तीन वर्षों में ८ प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि होनी चाहिये, यानी जो हमारी गति अबतक रही है उसकी तुलना में ५ से ६ गुना यदि हम रफ्तार बढ़ा पायेंगे तो संभव है कि हम कृषि उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंच सकें ।

(इस समय ४ बजकर २५ मिनट पर, श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

मैं और कुछ न कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं सरकार इस पर गहरा अध्ययन करे वह इस मामूली से सबक को जो दो तीन, चार शब्दों का है आज तक किसान को क्यों नहीं सिखा पाई और वह आगे इस प्रयत्न में कैसे सफलता प्राप्त करने वाली है । दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या कोई सरकार चाहे जितनी भी हितैसी हो किसानों की, क्या वह जितने खाद, बीज और पानी की आवश्यकता किसानों को होगी आज सब का वह पूरा प्रबन्ध कर सकती है ? कदापि नहीं कर सकती है । यह इतनी बड़ी समस्या है कि कोई सरकार इसको पूरी नहीं कर सकती चाहे जितनी नेक नियती के साथ वह इसको करे । जब तक किसान को स्वयं इस योग्य नहीं बनाया जाय कि वह अपने लिये इन चीजों का प्रबन्ध कर सके तब तक कोई सरकार पर्याप्त मात्रा में इनका वह प्रबन्ध नहीं कर सकती श्रीमन्, यह एक पुस्तिका है फूड ऐन्ड ऐग्रीकल्चरल आर्गेनाइजेशन की तरफ से छपी है । इसका नाम है "Essential Steps in National Agricultural Improvement" श्रीमन आपकी आज्ञा से मैं इसकी दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं :

"The quantity of farm commodity that farmers can produce depends in part on their willingness to work hard and to invest additional capital in their enterprises. To be willing to do this the farmers must have incentive. In many countries agricultural inprovement is still impeded by obstacles which suppress the farmers normal urge to better the conditions in life through improved conditions."

इसका अर्थ केवल इतना ही है कि कृषक कृषि उत्पादन को तभी बढ़ा सकता है जब उसको इस बात का भरोसा हो कि जो वह अधिक पैदा करेगा उस अधिक उत्पादन का लाभ उसे ही मिलेगा और अन्य किसी को नहीं मिलेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी व्यवस्था इस राज्य में कायम कर रखी है कि किसानों का जो अधिक उत्पादन हो उसका लाभ उन्हें ही मिले ? मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किये हैं और मै आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में किसानों ने ३५ प्रतिशत उत्पादन बढ़ाया लेकिन उनकी वास्तविक आमदनी केवल ५ प्रतिशत बढ़ी है । ऐसी दशा में किसको उत्साह हो सकता है कि वह अधिक उत्पादन में पूंजी लगाये । मैं केवल किसानों की दृष्टि से

[श्री भानुप्रतापसिंह]

जाने दीजिये। यह राष्ट्र के हितमें है कि किसान को अपनी फसल का ऐसा मूल्य मिले जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में समता में हो जब ऐसा होगा तब उनकी बचत हो सकेगी और जब बचत होगी तो वह कृषि में पूंजी लगायेंगे और सारी चीजों का प्रबन्ध स्वयं कर लेंगे और सरकार के मुहताज नहीं रह जायेंगे ।

श्रीमन्,सदन में मनोबल बढ़ाने की बहुत चर्चा हुई । माननीय गोविन्द सहाय जी ने पायनियर में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने विरोधीदल के नेताओं पर आरोप लगाया कि जन साधारण के मनोबल गिराने की उनकी बहुत जिम्मेदारी है । मैं कहता हूं कि न कांग्रेसी नेताओं का भाषण जनता का मनोबल बढ़ाता है और न हमारा भाषण मनोबल गिराता है। यदि कोई चीज मनोबल गिरा सकती है तो वे सरकार के कारनामें हैं । मनोबल बढ़ाने के लिये सब से प्रथम आवश्यकता यह है कि राष्ट्र का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिये । आज तक हमारी सरकार यह निश्चय नहीं कर पाई है कि चीनियों से युद्ध करेंगे या सुलह मश्विरा करके किसी प्रकार फेस सेविंग करेंगे । आपको जनता के सामने स्पष्ट उद्देश्य रखना चाहिये था । प्रधान मंत्री ने कहा था कि चीनी ८ सितम्बर, १९६२ के पीछे चले जायेंगे तो वार्ता की जायगी । लेकिन प्रधान मंत्री जी ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करके अपने वचन को भी भंग किया है और उससे पीछे हट गये हैं । लद्दाख के क्षेत्र में वार्ता के समय तक के लिये चीनियों के साथ साथ चैक पोस्ट कायम करने की उन्होंने अनुमति दे दी है और इस प्रकार से हिन्दुस्तान के एक भाग पर उन्होंने शासन में चीनी साझेदारी स्वीकार कर ली है । श्रीमन्, मनोबल गिराने की बात कही गई है । अगर कोई जिम्मेदार है इस मुल्क का मनोबल गिराने के लिये तो वह प्रधान मंत्री नेहरू हैं और दूसरे नम्बर पर मैं कहूंगा कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी है ।

मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं । हमारे कम्युनिस्ट भाई एक कागज दिखा रहे थे जिसमें कहा गया है कि प्रधान मंत्री नेहरू को अपदस्थ करने की साजिश चल रही है । साजिश का कोई प्रश्न नहीं है हम समझते हैं कि प्रधान मंत्री की नीति प्रदेश के लिये अहितकर है हम उनको हटाने के लिये जनतांत्रिक उपायों से प्रयत्न करेंगे । जनतन्त्र में प्रधान मंत्री को हटाने का प्रयत्न करना कोई दोष नहीं है। हम सभी के लिये जो कुछ भी संभव होगा वह करेंगे। (व्यवधान) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोबल तोड़ने की बात मैं क्यों करता हूं, इसके विषय में थोड़ा कहना चाहता हूं । मैं इस बात को मानता हूं कि इस प्रदेश के किसानों और मजदूरों ने काफी दिल खोलकर सुरक्षा कोष में धन दिया । यह उनके लिये और हमारे लिये गौरव की बात है । परन्तु इधर जिस ढंग से चन्दा वसूल किया जा रहा है वह इस सरकार के लिये शर्म की बात होनी चाहिये । लेकिन जब कभी चन्दे की वसूली में गड़बड़ी की बात कही जाती है उसका कोई मुनासिब उत्तर देने के बजाय उसको टालने की कोशिश की जाती है । अभी कुछ दिन पहले एक तार बस्ती जिले का पढ़ा गया । समाजवादी पार्टी के किसी सदस्य ने पढ़ा । वह तार सब से पहले मुझे मिला । लेकिन मैंने उसको नहीं पढ़ा केवल इसलिये कि इससे सरकार की बदनामी होगी । मैंने उसे ले जाकर गृह मंत्री जी को दिया । उसी दिन वित्त मंत्री जी ने कहा कि आपके पास जितनी शिकायतें हैं, हमको दीजिये । हम जांच पड़ताल करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे लेकिन आज तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला । मैं यह जानता हूं कि उत्तर यही मिलेगा कि शिकायत निराधार थी फिर भी इतना तो होना ही चाहिये था कि जो शिकायत की गयी थी उसका कुछ न कुछ उत्तर दिया जाता लेकिन एक हफ्ता हुआ जा रहा है, कोई उत्तर नहीं मिला है । मैं आज भी कहता हूं कि जो चन्दा देना चाहते हैं बड़ी खुशी से चन्दा दें । देना चाहिये लोगों को । परन्तु जिस तरह से चंदा आज वसूल हो रहा है वह नितांत अनुचित है । जैसा कि वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि चन्दे से सरकार लड़ाई नहीं लड़ सकती । आपको जितने रुपये की आवश्यकता हो, सुरक्षा के लिये, उसके लिये आप टैक्स लगायें । लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है कि चालान कर दिया जाय कस्बे के कस्बे का । हमारी तहसील डुमरियागंज के अन्दर दो महीने के अन्दर जितने चालान हुये हैं उतने पहले दो वर्ष में नहीं हुये थे । उद्देश्य यह है कि ज्यों ही चन्दा मिल जायगा चालान वापस हो जायंगे । हमारे बस्ती जिले में अध्यापकों से बिना उनकी रजामन्दी के वेतन काट लिया गया । नयी नौकरी देने के पहले कहा गया कि ५० रुपये जो देगा

उसी उम्मीदवार, को अप्वाइंटमेंट आर्डर मिलेगा । यह सब चीजें ऐसी हैं अगर आप में साहस हो तो चल कर जांच कीजिये । वहां साबित की जा सकती है । मैं नहीं चाहता कि गड़े हुये मुर्दों को उखाड़ा जाय, लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप भी सहमत हैं कि इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती तो फिर इस तरह चन्दा वसूली खत्म कीजिये । मैंने माननीय मुख्य मंत्री से पूछा था कि क्या चन्दा वसूली का यह सिलसिला चलता रहेगा तो मुझे आशा थी कि वह कहेंगे कि अब समाप्त किया जायगा । लेकिन उन्होंने कहा कि जबतक इमर्जेंसी रहेगी तब तक चन्दा वसूल होता रहेगा । इस सदन को यह भी याद होगा कि जिस समय सरचार्ज बिल उपस्थित हुआ था, उस समय राजस्व मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस बिल के पास हो जाने पर किसानों को किसी तरह से परेशान न किया जाय । यह भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास सर्कुलर भेजा जायगा लेकिन वह कुछ भी नहीं हुआ । उनसे चन्दा भी वसूल किया जा रहा है और सवाया भी वसूल किया जा रहा है । जो आश्वासन दिया जाता है उसको पूरा होना चाहिये । इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है । इस दोहरी वसूली को अब समाप्त करने की आवश्यकता है ।

श्री रामभजन (जिला खीरी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो यह बजट हमारे सम्मुख पेश किया है, उसके संबंध में आपको मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया । आज आप जानते हैं कि हमारा देश संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है । इस दृष्टि से आज हमारे देश के सामने जो समस्यायें हैं, उनको सामने रखकर बिलकुल समयानुकूल बजट पेश किया गया है । इससे अच्छा बजट कोई दूसरा आ ही नहीं सकता था । लेकिन इस देश के अन्दर जनतांत्रिक प्रणाली होने के कारण विरोधी दल के लोग इसकी इस तरह से आलोचना करते हैं । बड़े अफसोस की बात है कि वह उस जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते और जिम्मेदारी से इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न नहीं करते । हमारे देश के ऊपर हमला हुआ । उस हमले के बाद हमारे देश के अन्दर इस तरह की जागृति पैदा हुई, इस तरह की 'एकता' की भावना पैदा हुई जिसकी वजह से हमारे देश का मस्तक ऊंचा हुआ । लेकिन अफसोस है कि असेम्बली में बैठे हुये विरोधी दल के लोग हमारे मनोभाव को नीचा गिराने के लिये और हमारी समस्याओं के ऊपर मिट्टी डालने के लिये और कुर्सियों की तरफ निगाह रखने के लिये इस तरह से लालायित हैं कि वह हमारे राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, राष्ट्रनायक और प्रधान मंत्री में अन्तर है । जवाहरलाल नेहरू हमारे राष्ट्रनायक नहीं हैं, प्रधान मंत्री हैं, यह माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से बीच में टोकना यह बड़ी गलत बात है । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री रामभजन---

बड़े अफसोस की बात है कि हमारे विरोधी दल के लोग जरा भी सहनशीलता से बात सुनने की क्षमता नहीं रखते । आपको मालूम होना चाहिये कि हमारे सामने देश की जो समस्यायें हैं, उनके ऊपर हम बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ विचार कर रहे हैं और उनसे जूझ रहे हैं । हम जानते हैं कि देश की रक्षा हमीं को करनी है और कोई भी दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो देश के भार को किसी तरह से सम्हाल सके । आज अगर आप में ताकत होती तो आप पंडित नेहरू को अपदस्थ कर देते और हम बड़ी खुशी के साथ इसको स्वीकार कर लेते । लेकिन हम देखते हैं कि विरोधी दल में बैठे हुये लोग तरह तरह की टोपियां और तरह तरह के बिल्ले लगाये हुये हैं और तरह-तरह की बात करके, तरह तरह से अपने भावों और विचारों को प्रकट करके वह हमारी एकता को बढ़ा नहीं सकते । इस समय हमारे देश के अन्दर इमर्जेंसी है इस समय में बहुत ही एकता की जरूरत थी, बहुत ही संगठन की जरूरत थी और एक वक्त पिछले मर्तबे असेम्बली में ऐसा प्रतीत

[श्री रामभजन]

भी हुआ था कि विरोधी दल के लोगों का दिमाग कुछ सही हुआ है, वह कन्धे से कन्धा मिलाकर हमारी समस्याओं को हल करने के लिये चलने को तैयार हैं। लेकिन थोड़ा समय गुजरते ही, जैसे ही सीज फायर हुआ, विरोधी दलों को इस बात की चिन्ता हुई कि कहीं ऐसा न हो कि हम कांग्रेस के अन्दर मर्ज हो जायं, और कांग्रेस की ताकत और उसकी शक्ति के सामने हम झुक जायें। लिहाजा इस बात की जोरों से कोशिश होने लगी कि हम किसी न किसी तरीके से अपनी पार्टी का प्रोपेगेंडा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने नेता विरोधी दल का जो भाषण हुआ, वह आलोचना से भरा हुआ था। कोई सुझाव की बात उसमें नहीं थी। उसके बाद माननीय उग्रसेन जी ने जो भाषण दिया वह ऐसा मालूम होता था कि सुरक्षा के ऊपर उनका भाषण हो रहा है और ऐसा मालूम होता था कि वह पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। पार्लियामेंट का यह विषय हो सकता था कि हमारी स्कीमें क्या हों। यह चीजें यहां का विषय नहीं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी इस पर इतना जोर यहां दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि हम देश में हिमालय बचाने के लिये नारा बुलन्द कर रहें हैं और उधर नेहरू को बचाने का आन्दोलन हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमें नेहरू को बचाने की फिक्र नहीं है। हम जानते हैं कि नेहरू खुद इतने शक्तिशाली हैं, खुद इतने बुद्धिमान और इतने जनप्रिय हैं कि जिनके बचाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि खुद जिनकी बुद्धिमत्ता से हमारा देश बच रहा है। हमें इस बात का बड़ा गौरव है कि हमारे देश के अन्दर इस तरह का एक नेता मौजूद है। आज अगर हमारे बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू न होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग अपनी इस तरह की भावनाओं से और इस तरह के विचारों से देश की समस्या हल नहीं कर सकते थे। हमें इस बात का गर्व है। अभी भानुप्रतापसिंह जी ने बताया कि हम दो चक्कियों के बीच में पिसे जा रहें हैं। एक चक्की जवाहरलाल नेहरू की है और एक प्लानिंग कमीशन की है। इन दोनों चक्कियों में हम पिसे जा रहे हैं।

हम ऊपर के आदेश मानते हैं, लेकिन नीचे से कोई विचारधारा नहीं है। मैं उनसे सवाल करता हूं कि वह क्या राजगोपालाचार्य की चक्की के नीचे नहीं पिसे जा रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि भाषा के बारे में उनके क्या विचार हैं? राजगोपालाचार्य ने कहा यह था कि हमारी जिन्दगी में यह अभिलाषा है कि हिन्दुस्तान को अमेरिका के साथ मिल जाना चाहिये। इसके माने यह हैं कि जो हमारी नानएलाइनमेंट की पालिसी है उसको स्वतन्त्र पार्टी के नेता पसन्द नहीं करते हैं। मैं आप से पूछता हूं कि क्या यह रोज रोशन की तरह आयां नहीं है कि नानएलाइनमेंट की हमारी पालिसी ने देश को बचा लिया? अगर हम किसी गुट के साथ होते जिस तरह से कि पाकिस्तान है तो आज हमारी भी वही हालत होती। आज पाकिस्तान भी हमारी पालिसी पर चलने की कोशिश कर रहा है कि चीन और रूस से उसके भी उसी तरह से सम्बन्ध हो जायं जैसे हमारे हैं। यह बात सारे देश के राजनैतिक और विचारशील लोगों ने अच्छी तरह से मान ली है कि हमारी नानएलाइनमेंट की पालिसी सफल रही है। यही वजह है कि संसार के अन्दर डेमोक्रेटिक देशों ने ही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट देशों ने भी हमारा साथ दिया है। कम्युनिस्ट देशों के बारे में जो कुछ धारणा है वह सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज इस तरह का प्रोपेगन्डा किया जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सन् १९४२ के आन्दोलन में बड़ी गलत बातें की थीं। बड़ी दगाबाजी का काम किया था। मैं कहूंगा कि एक पार्टी एक बार कोई ग़लत काम करने से हमेशा के लिये बदनाम नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि जनसंघ ने सन् १९४२ के आन्दोलन में कौन सा पार्ट अदा किया था। जनसंघ तो उस समय अपनी मां के हमल से भी नहीं निकला था। उसी तरह से पी० एस० पी० के लोग जब हमारे देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तो वे लोग कारखानों में हड़ताल करा रहे थे। देश में उत्पादन को कम करने के लिये काम कर रहे थे और देश के ऊपर तरह तरह की मुसीबत डालने के लिये परेशान कर रहे थे। क्या वह देशद्रोह का कार्य नहीं था? आज हम इस बात को देखते हैं कि कम्युनिस्ट देश भी हमारे साथ हैं। आज संसार क लगभग ८०, ९० देश हमारे साथ हैं। यह

हमारी नानएलाइनमेंट पालिसी का, निष्पक्षता का, हमारे नेताओं की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। यही वजह है कि जिस रूस को चीन के साथ मिलना चाहिये वह रूस स्वतन्त्र है और वह निष्पक्षता के साथ हमारी मदद कर रहा है। हमारा और उसका जो मुआहिदा है उनको अच्छी तरह से अमली जामा पहना रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस सदन में जो कुछ स्पीचें हुईं वह बजट के ऊपर नहीं हुईं बल्कि अपनी पार्टी के बचाव के लिये हुईं। मैं कहता हूं कि उग्रसेन जी ने जो भाषण दिया था वह क्या ऐसे वक्त में उनका भाषण करना मुनासिब था? उनकी पार्टी का जो मेनीफेस्टो था उसको ही वह बतला रहे थे और वह इस तरह की बातें करके जनता को और देश को बरगलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसे मौके पर देश को जवाहरलाल के खिलाफ कर दें। हम जनतन्त्र को मानते हैं और जनतन्त्र प्रणाली में विश्वास करते हैं। इसमें हम अपना अगुवा इंगलैन्ड की जनतन्त्र प्रणाली को मानते हैं। जिस वक्त सेंकिड वर्ल्ड वार हुई थी, तो उस समय मिस्टर चर्चिल इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री थे। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जिस तरह से उन्होंने जंग का संचालन किया वह दुनियां की हिस्ट्री में अमर है। उस वक्त वहां के लोगों ने यह समझा कि चर्चिल की पालिसी उस देश के लिये हितकारी रही तो वहां की जनता ने युद्ध के दिनों में चर्चिल के खिलाफ आवाज नहीं उठाई लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो चर्चिल को अपदस्थ कर दिया गया। दूसरी हकूमत वहां पर बनी। इस वक्त हमारे देश में इमर्जेंसी है। इस समय इस तरह का सवाल करना कि एक पार्टी की हकूमत मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि आप आयें और हकूमत को सम्भालें लेकिन आप लोग ५ जगहों पर बैठे हुए हैं और ५ ही आप की बोलियां हैं। आप लोगों में आपस में मतभेद है, लड़ाई है। हम समझते हैं कि इस समय इमर्जेन्सी में हमारे देश में एकता होनी चाहिये। विरोधीदल के अन्दर भी एकता होनी चाहिये। विरोधीदल एक आवाज में बोले तभी हमारे देश की सुरक्षा हो सकती है। हमारे विरोधीदल के लोग इस बात पर विचार नहीं करते। यह भी कहा जाता है कि हमको डेफिसिट बजट पेश करने की आदत है। यह कोई बुरी नीति नहीं है। जितने भी प्रगतिवादी देश हैं, डेफिसिट बजट पेश करते हैं। अंग्रेजों ने जिस हालत में हमें छोड़ा था उसमें हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते थे यदि हम में काम करने की प्रेरणा न होती। डेफिसिट बजट पेश न कर के हम लोगों को खुश रख सकते थे, लेकिन हम देश की प्रगति के साधन न जुटा पाते। यह स्थिति है। हम काम करना चाहते हैं, देश और देहात का नकशा बदलना चाहते हैं इसलिये हमारी यह नीति है। जो अंग्रेजों की हकूमत में किसान का खून चूसने वाले थे आज उसके बड़े हमदर्द बने हुये हैं, लेकिन हम जानते हैं कि "हम को उनसे वफा की है उम्मीद, जो जानते नहीं वफा क्या है।" वह समझते ही नहीं कि देश के सामने क्या समस्या है, क्या मुसीबत है और हमको क्या करना चाहिये। पार्टी की शाक्ति तो जनता में काम करने से बढ़ेगी, खाली प्रोपेगेन्डा करने से कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस इमरजेंसी पीरियड में अगर हम ईश्वर के लिए खामोश हो जायं और देश की रक्षा के लिये, उसकी स्वतन्त्रता के लिये कटिबद्ध हो जायं तो बड़ा काम हो जाय। याद रखिये कि पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश को कोई खतरा नहीं है। उनके साथ मिल कर खड़े हो जाना ही आज सच्ची देशभक्ति है। यदि पंडित नेहरू फिसल गये तो आप में से कौन है कि जो उनका स्थान ले सके? लोहिया जी हैं? या गुरू जी हैं? किसी में ऐसी क्षमता है कि जो देश को अपनी ओर आकर्षित कर सके? उनकी सी शक्ति किसी नेता या पार्टी में नहीं है। इसलिये जब तक यह ताक़त किसी में नहीं आती तब तक ईश्वर के लिए शान्ति रख कर कटिबद्ध हो जायं और संगठित हो कर देश के बचाव के लिये कोशिश करें। चीन हमारे लिये एक महान खतरा है। अगर वह न हो तो जनसंघ या कम्युनिस्टों के लिये कोई भय की बात नहीं है और यह भी समय साबित करेगा कि देश में पंचमांगी कौन है? देश की आजादी के समय हम ने गुरू जी बचाओ आन्दोलन देखा, फैक्टरियों में हड़तालों का आन्दोलन देखा, एक तबके को दूसरे का खून चूसते देखा, लेकिन आज तो देश का कम्युनिस्ट भी यह नहीं चाहता कि देश की भूमि चीन हड़प ले जाय। जिस प्रकार रूस का हिस्सा चीन नहीं हड़प सकता उसी प्रकार यहां के कम्युनिस्ट भी यह नहीं चाहते कि देश के

[श्री रामभजन]

किसी भाग पर चीन कब्जा कर ले और यही वजह है कि संसार के कम्युनिस्टों ने चीन की प्रसारवादी नीति की निन्दा की है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप का समय समाप्त हुआ ।

श्री शिवेन्द्र प्रताप (जिला सीतापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया। १६६३-६४ का बजट मैंने पढ़ा। इसमें ६ करोड़ ५५ लाख की धनराशि सड़कों के लिये नियत की गयी है। सड़कें देश के लिये बहुत आवश्यक होती हैं, लेकिन इस वक्त हम को इस आइटम पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। श्रीमन्, सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक स्टार एंड ग्रिड फार्मूला अप्लाई किया और अभी तक उत्तर प्रदेश में करीब १४ हजार मील सड़कें बन चुकी हैं। जिस समय सड़कें बनायी गयी थीं उस समय कहा था कि ६ टन की वेहिकिल्स के लिए वह थीं। लेकिन पता नहीं कैसे उस पर १५ टनर्स के परमिट ईश्यू कर दिये गये हैं और जो सड़कें १० साल के लिये बनायी गयीं थीं उनकी लाइफ अब ढाई साल रह गयी है।

मैं माननीय वित्त मंत्री का इस ओर ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे पास जो रोलर और सीमेंट मिक्सर थे उनमें ७० रोड रोलर डिफेंस डिपार्टमेंट ने ले लिये हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बारे में बजट के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं की गयी है कि वह रोड रोलर यू० पी० में बनाये जायेंगे या बाहर से मंगाये जायेंगे। अगर रोड रोलर ही नहीं हुए तो जो, ५५ लाख की प्लान है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उस पर काम होगा। इसलिए आवश्यक है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

श्रीमन्, अभी भानु बाबू ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी स्ट्रांग हो गयी है और यहां का अगर कोई मिनिस्टर कुछ करवाना चाहे तो नहीं करवा सकता है। लेकिन एक चीज शायद वह भूल गये कि जो मिनिस्टर करवाना चाहता है वह तो करवा लेता है, लेकिन जो चीज नहीं कराना चाहता है उसके लिये मजबूरी हो जाती है।

इसमें कहा गया है कि विकास योजनाओं की ओर विशेष ध्यान देना है। पहली और दूसरी योजनाएं चलीं और तीसरी चल रही है, लेकिन क्या उससे जनता का विकास हो रहा है और जितना जनता को हम देने का वादा करते हैं उतना उस को मिल रहा है ? मैं तो जानता नहीं, देहात से आया हूं और ऐसा देहात है कि बम्बई जाना आसन है, लेकिन हमारी कांस्टीट्यूएंसी में जाना मुश्किल है। वहां ब्लाक खुले हुये हैं, लेकिन एक विशेष वर्ग का चाहे फायदा होता हो, जनता को उससे क्या फायदा हुआ, मेरी समझ में नहीं आता। मिसाल के तौर पर इनके यहां एक लोन होता है जो जानवर रखने के लिये, कुआं बनाने के लिए। कायदा यह है कि मशीन वगैरह के लिए कुछ रुपया सरकार देती है। जिस किसान के पास ३-४ एकड़ से ज्यादा नहीं है और १५ रुपया मालगुजारी देता है, तो समझ में नहीं आता है कि वह कुआं बनाने के लिये अपने पास से क्या लगा सकता है ? सरकार कहती है कि तीन चौथाई या आधा तुम लगाओ, लेकिन उसके पास खाने को पैसा नहीं है, वह कहां से लायेगा ? नतीजा यह होता है कि जिस वर्ग को प्लानिंग से फायदा होना चाहिए वह नहीं हो रहा है बल्कि उस को फायदा हो रहा है जो कुछ विशेष वर्ग हैं।

हमारे मिश्र जी और कुछ सज्जनों ने मनोबल पर जोर दिया और कहा कि मनोबल विरोधी पार्टियां नीचे गिरा रही हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हम कैसे गिरा रहे हैं। अगर सरकार ऐडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग करे तो वह अपने आप उठ जायगा। सरकारी अफसर कहते हैं कि मिनिस्टर कुछ नहीं करते हैं। बजट में श्रीमन्, हर चीज का वर्णन होता

है। हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन इतनी हद तक बढ़ गया है, उसको रोकने के लिए इसमें कोई चार्ज नहीं कही गयी। आज जनता के अन्दर यह मनोभावना पैदा हो गयी है कि जिसके पास पैसा है वही अपना काम करा सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका काम नहीं बन सकता। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस करप्शन को रोकने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं? आज एक किसान को सब से ज्यादा टैक्स और चन्दा देना पड़ता है। लेकिन उस को अपने छोटे-छोटे कामों के लिये जगह जगह की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसका कहीं काम नहीं होता। कभी पटवारी नाराज है, कभी कानूनगो, तो कभी थानेदार। इसलिये सरकार को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिये कि किसान को कुछ सुविधा मिल सके।

अब मैं थोड़ा सा सरकार का ध्यान जंगलात की तरफ और दिलाना चाहता हूं। जो ठेकेदार लोग होते हैं जब उनको टिम्बर का ठेका दिया जाता है तो १० या ५ परसेंट उनसे जमा करा लिया जाता है और जब आखिरी इन्सटालमेंट वे निकालते हैं तब वह क्लियर हो जाता है। यह ठेकेदार लोग करते क्या हैं? यह रेन्जर इत्यादि से मिल कर पहले ही अच्छी अच्छी लकड़ी निकलवा लेते हैं और खराब खराब छोड़ देते हैं। नतीजा यह होता है कि सरकार उनसे रुपया वसूल करने में असमर्थ हो जाती है। आज उसी कारण से सरकार का ५०.९ परसेंट रुपया ठेकेदारों पर बकाया पड़ा हुआ है और उसकी वसूली का कोई प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है।

मैं अब थोड़ा सा ध्यान अपने क्षेत्र की ओर भी दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां एक स्कीम यूटीलाइजेशन आफ मैन पावर स्कीम चली थी। उसके लिये यू० पी० भर से प्लान मांगे गये। हमारे यहां से भी रामपुर से महमूदापुर तक सड़क बनाने की स्कीम आई। उसके लिये मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र भी लिखा। लेकिन उस ओर कोई खयाल नहीं किया गया। हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। हर साल ५०-६० हजार मन गल्ले का नुक्सान हो जाता है। जब इमर्जेन्सी डिक्लेयर हुई तो मैंने कई बार माननीय मन्त्री जी को पत्र लिखा कि विशेष परिस्थिति में इस क्षेत्र की ओर खयाल करें। उसका जवाब तक नहीं दिया गया, जब कि माननीय मन्त्री जी के पास हर साधन फ्री मोहइया हैं, हमको तो टिकट आदि में पैसा भी खर्च करना होता है। श्रीमन्, इमर्जेन्सी का जहां तक सवाल है वह तो है ही। लेकिन मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं जनता से चन्दा मांगने से ही कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप उनके लिए इतना तो करें कि उनको अपने छोटे छोटे कामों के लिये, इन्तखाब आदि के लिये, जगह जगह दौड़ना तो न पड़े। आप यह चाहते हैं कि काश्तकार आपको सहयोग दे, तो आप को यह करना पड़ेगा कि उन को आप अधिक से अधिक सुविधायें दें। श्रीमन्, इस बजट के अन्दर करीब ४.९७ करोड़ रुपया का घाटा दिखाया गया है। पिछले चार पांच साल से यही हो रहा है कि हर साल घाटे का इस्टीमेट किया जाता है, लेकिन न जाने कहां से वह रुपया आ जाता है कि वह सरप्लस हो जाता है। दुहाई दी जाती है कि मितव्ययिता के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन इस साल फिर वही किया गया है। जो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और दूसरे कर जो बकाया हैं, अगर आप उनको वसूल कर लें तो नये टैक्सों के लगाने की आपको आवश्यकता ही न हो। पिछली बार सरकार ने किसानों पर २५ परसेंट का सरचार्ज लगा दिया, उसकी वजह से ग्रामवासियों में बहुत असंतोष हो गया है। एक ओर तो आप उनसे चंदा मांगते हैं, उनसे लड़ाई के लिये उनके लड़के को मांगते हैं लेकिन दूसरी तरफ केवल उन्हीं पर टैक्स भी लगाते हैं। जो टैक्स बढ़ाया गया है वह काश्तकारों पर ही बढ़ाया गया है। इमर्जेन्सी पीरियड में इस तरह से असंतोष पैदा होना किसी भी देश के लिये घातक सिद्ध हो सकता है, ऐसा मेरा अन्दाजा है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री यादवेन्द्रसिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आप ने पूरे एक दर्जन दंड बैठक करने के बाद मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। मैं सन् १९६३-६४ के बजट के लिये अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना संतुलित बजट हमारे सामने पेश किया है। मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं

[श्री यादवेन्द्रसिंह]

जिन्होंने इस सदन में डिबेट के समय अच्छा वायुमंडल बनाये रखा। वे भी धन्यवाद के पात्र हैं जिनको सुनने के बाद मैं यह सोचने लगा कि यह फाग का मौसम है, कभी यह मालूम हुआ कि सुरक्षा के ऊपर यह बहस चल रही है। विशेषरूप से मैं माननीय शिवेन्द्रप्रताप को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने वादविवाद को बजट तक ही सीमित रखा कि दूसरे सुरक्षा और इमर्जेन्सी की ओर ही अग्रसर रहे। मैं समझता हूं कि यह समय और धन दोनों का अपव्यय हुआ। विरोध वालों को बजट की कमियों और समर्थन करने वालों को बजट की अच्छाइयों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहिये था। मैं तो यह समझ ही न सका कि यह सदन सुरक्षा, पंडित नेहरू आदि विषयों पर विचार करने के लिये समर्थ भी था या नहीं। यह तो केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। बहरहाल उस में बड़े-बड़े महारथी उतर आये लेकिन माननीय शिवेन्द्रप्रताप जी ने मुझे वाकई यह याद दिलाया कि बजट पर बोलना चाहिये।

यह फाग का मौसम जरूर है और लोग फाग तथा छुट्टी के मूड में हैं क्योंकि हमारे सब माननीय सदस्य २१ तारीख से सदन के उठ जाने के कारण जा रहे हैं। यह छोटी मोटी बात नहीं है। इस समय भी यह सदन इसका गवाह है, ये कुर्सियां इसकी गवाह हैं कि हम इमर्जेंसी को कितना अनुभव कर रहे हैं जिसके बारे में सरकार पर बार बार आक्षेप होता रहता है। लेकिन श्रीमन्, आप के द्वारा मैं इस आदरणीय सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इमर्जेंसी के काम के लिये केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि भारतवर्ष में बसने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इस सदन में रहने वाला प्रत्येक सदस्य, चाहे वह विपक्ष का हो चाहे सरकारी पक्ष का हो, वह जिम्मेदार है जनता के पैसे को बचाने के लिये, जनता के समय को बचाने के लिये और ज्यादा से ज्यादा रकम सुरक्षा की तरफ ले जाने के लिये। यह कहना समय के विपरीत नहीं होगा कि जिस समय हम घाटे की बजट की बात करते हैं, तो अपने आप को उस जिम्मेदारी से बरी नहीं कर सकते। जब हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में भी जहां ८२ से ८५ दिन तक ही बजट सेशन होता है, ऐसे विषयों पर नहीं उलझा जाता, हम ऐसे विषय पर बात करना छोड़ कर भी बजट पर बात कर सकते हैं, हम ऐसे विषय को छोड़ कर भी सरकार की गल्तियों को प्वाइंट आउट कर सकते हैं, और जनता का समय बचा सकते हैं। इससे जनता का पैसा भी बच जायगा और सदन की कार्यवाही भी जो लम्बी हो जाया करती है उसको भी हम रोक सकेंगे। इसका अल्टिमेट रिजल्ट यह होता कि बजट की तरफ हमारा कदम और उस बजट को हम घाटे की रकम में दिखा कर घाटा कम कर सकते हैं। इसके पहले पूरक बजट हमारे सामने आया था, जिसमें यह बतलाया गया था कि कई साल रुपये की डिफिसिट केवल इसलिये हो गयी कि हमारी विधान सभा नियत समय से ज्यादा दिनों तक चली। तो उसके हम जिम्मेदार हैं जो यहां जनता के प्रतिनिधि चुन कर आये हैं। यह कहने में मुझे जरा हिचक नहीं है।

अब मैं बजट के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, जिसके लिये आज मुझे यह मौका मिला है। यह बजट और इस बजट को बनाने वाले और इस बजट को कार्यान्वित करने वाली सरकार, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बजट में कमी का होना इस बात का द्योतक है कि हम प्रगति की तरफ जा रहे हैं। रवानी जब आती है तो वह जिन्दगी देती है। उसी तरह से हमारी योजना हमें पूर्ति की तरफ ले जा रही है। हम एक-एक कदम आगे चल रहे हैं और हमारी जनता यह महसूस कर रही है कि उसका रास्ता ठीक है। प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में अन्तर यह है कि प्राइवेट सेक्टर वाला पहले अपनी पाकेट को देखता है तब अपनी बर्जटिंग करता है और पब्लिक फाइनेंस में पहले जनता की जरूरतों को देखा जाता है, वक्त की पुकार को देखा जाता है, अपने कर्त्तव्य को देखा जाता है, और तब पब्लिक फाइनेंस के ऊपर बर्जटिंग होती है। इस बजट में यह बतलाया गया है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को महसूस करती है और हम एक तरफ से अपनी योजना की पूर्ति की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। यह इमर्जेंसी का समय है, इसके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने तर्क किया कि इमर्जेंसी

समाप्त होनी चाहिये। इसके पक्ष में जो तर्क दिया गया मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अगर वे स्वयं अपने सीने पर हाथ रख कर पूछें तो उन्हें मालूम हो जाय कि उनके इस तर्क में कहां तक सार है कि इमर्जेंसी समाप्त होनी चाहिये। इसके ऊपर गम्भीरता पूर्वक विचार करना है कि यह समय आपतकालीन है। अब मैं यह सूचना दूंगा कि क्या आपत्ति हमारे सामने है।

दुश्मन आज हमारी सीमा पर चढ़ा हुआ है। उसने हमारे बहुत से इलाके धूर्तता से छद्मरूप से अपने कब्जे में कर लिया है। हमारे लिये आवश्यक है कि हम उससे सीमा पर लड़ें, हमारे लिये आवश्यक है कि हम अपने घरों में, अपने खेतों में, अपने मिलों में और उत्पादन के क्षेत्र में लड़ें। योजना की सिद्धि व समृद्धि के लिये भी हमें लड़ना है क्योंकि योजना की प्रगति पर ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। लड़ाई के बाद भी हमें फिर वहीं लौट कर आना है। इसलिये हम चाहते हैं कि अपने देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार पैदा करें और सुरक्षा की तरफ सोचने के लिये हमें तो बाद में मजबूर होना पड़ा अपने उन नादान दोस्तों की वजह से जिन्होंने हमें धोखा दिया है और जिन्होंने मानवता पर हमला किया है। हमारे लिये उनकी बर्बरता का मुकाबला करना जरूरी है लेकिन हम उनके मुकाबले के लिये सन्नद्ध हो सकें, इस योग्य बन सक इसके लिये हमें अपनी योजना की पूर्ति करना है ताकि हम अपनी योजना को पूरा करें और देश की समृद्धि को कायम रख सकें। मुझे प्रसन्नता है कि इस बजट में कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और मैं इसका कृषक होने के नाते स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में यह बहुत जोरदार और एफेक्टिव कदम है। यह भी आवश्यक था कि जहां खाद पानी और बीज आदि की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है वहां उत्पादन के मार्केटिंग के बारे में भी कुछ सोचना चाहिये था। जो अनाज आज पैदा होता है किसानों के यहां उस की खपत के बारे में क्या व्यवस्था होगी, गन्ने और चीनी का क्या होगा और किसान जो मर खप कर आज रकम अनाज की शक्ल में पैदा करता है उस को किस तरह से उसका ठीक मूल्य मिलेगा, कहां उस को ठीक मार्केट मिलेगा इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा।

आप के द्वारा इस बजट के मौके पर मैं खास तौर से अपनी कांस्टीटुएंसी तिलपुर और विनायकपुर की सड़क के बारे में जो कदम उठाया गया है, उसको सुरक्षा, प्रगति और बहबूदी की दृष्टि से सोच समझ कर जो मंत्री जी ने बजट में स्थान दिया है उसके लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं। नौतनवा से ठूठी सड़क के लिये जो रुपया बजट में है जिसको कि आप इस बजट में मंजूर करेंगे। जो लोग उस इलाके को जानते हैं, माननीय नेता विरोधीदल ने भी उस को देखा है वह भी इसकी आवश्यकता को महसूस करते हैं और इस पर खुश होंगे हो सकता है कि उधर की कुर्सी के नाते वह कुछ न कह सकते हों लेकिन उनका दिल अवश्य बधाई देता होगा। इस बारे में जब वह सिसवा बाजार की मीटिंग में गये थे तो उसी वक्त माननीय वित्त मन्त्री जी ने महसूस किया कि सड़क बनना चाहिये और उसको बजट में उन्होंने स्थान दिया।

इसके साथ ही मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान बस्ती, गोरखपुर, देवरिया आदि जिलों को तबाह करने वाली बाढ़ की विभीषिका की तरफ भी दिलाऊंगा। नेपाल बांध जिसका बनना बड़ा जरूरी है, नेपाल जो हमारा मित्र है, जिसको हम मित्र मानते हैं, उससे हमें विश्वास है कि वह नेपाल बांध बनाने की इजाजत देने में कोई तग़ाफुल न करेगा। लेकिन जब तक उनका बनाने का आदेश आये और बांध का काम शुरू हो, उससे पहले मैं वहां पर जो बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न हो सकती है उस की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे उस इलाके में मुखमरी का सामना करते हुये वहाँ के किसान जिनका कि मैं प्रतिनिधि हूं, हां प्रतीक मैं नहीं हूं उनके विषय में आशा है कि सरकार कुछ सोचेगी कि अगर बरसात से पहले बाढ़ से बचने के लिये वह बांध न बन सके तो वहां के लोगों की आर्थिक दशा और हालत बहुत अधिक बिगड़ जायगी। वह लोग पिछले ४ साल से वहां एक भी फसल नहीं पाये हैं, सरकार ही उनकी जिन्दगी कायम रखे हैं। मैं सरकार से विनती करूंगा कि अगर बांध जल्द न बंध सके जिस की कि आशा नहीं है क्योंकि वह ३ मास में नहीं बंध सकता और अभी चूंकि नैपाल सरकार की आफिशियल परमिशन भी नहीं आई है तो उससे किसानों को बचाने के

[श्री याज्ञवेन्द्र सिंह]

लिये अभी से वहां पर टेक्निकल लोग, इंजीनियर्स लगाये जायं जो देखें कि पानी ने जो पिछले सालों से रास्ता बनाया है या पानी ने ग़लत सही सड़कों को और खेतों को काटा है उन जगहों को देखकर मुनासिब कार्यवाही की जाय ताकि पानी के रास्ते में अवरोध न पैदा हो और जो पानी बड़ी गन्डक से आने वाला है उस पानी से बचने के लिये पहले ही प्रबन्ध हो जाय, उसके लिये रास्ता दिया जाय। छोटी गन्डक जो उस पानी के बहुत बड़े भाग को बहा कर ले जाती है और जो इरोजन आफ स्वायल से ऊंची हो गयी है। जिसको काट कर सीधे करने और गहरी करने की स्कीम सरकार चला रही थी। उस स्कीम को और तेजी से चलावे ताकि छोटी गंडक पानी के वौल्यूम को जल्द से जल्द उस इलाके से निकाल सके और उस क्षेत्र को पानी से बचाया जा सके।

हमारे इलाके में एक रेलवे लाइन की पैमायश हो रही है, यह सदन रेलवे लाइन पर विचार करने के लिये उपयुक्त स्थान नहीं है, लेकिन मैं सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि उस रेलवे लाइन के बनने की वजह से उस इलाके की तरक्की तो निश्चित है और नैपाल से हमारा संबंध दृढ़तर हो जायगा। लेकिन ध्यान रखा जाय उस रेलवे लाइन के बनने से गोरखपुर की स्थिति ठीक वैसी होने जा रही है जैसी मुगलसराय और खंडवा की है। ईश्वर न करे अगर खंडवा पर कुछ हो जाय तो उत्तर भारत दक्षिण भारत से बिल्कुल कट सकता है। इसी तरह से मुगलसराय पर कुछ हो जाय तो पूर्वी भारत पश्चिमी भारत से अलग हो जायगा। आज गोरखपुर भी उसी तरह से रेलवे का नाट बनने जा रहा है। जैसे आज बगहा से सिसवा बाजार को वाया भैसा लोटन त्रिवेणी होकर(जो ग्रेट गंडक का बैराज बनने जा रहा है) उसके ऊपर से रेलवे लाइन निकाल कर कनेक्ट किया जा रहा है यह जरूर होना चाहिये। इससे नैपाल और हिन्दुस्तान का संबंध मजबूत होगा और महत्वपूर्ण भी है। लेकिन यह भी देखा जाय कि बरौनी जंक्शन तक बड़ी लाइन आ चुकी है, बरौनी से नरकटियागंज मिलने जा रहा है। मैं चाहता हूं नरकटियागंज से बड़ी लाइन सिसवा बाजार को कनेक्ट करती हुई आनन्द-नगर तक मिला दी जाय और आनन्दनगर से जो लूप लाइन गोंडा होते हुये सीतापुर जाती है और सीतापुर से जो लाइन बाराबंकी को आती है अगर इस पर नैपाल बार्डर के पैरेलल बड़ी लाइन लायी जाय तो गोरखपुर जो रेलवे नाट बनने जा रहा है वह बच जायगा। इस तरह से उस इलाके को काफी बल मिलेगा।

भगवान कृष्ण जो ईश्वर के अवतार थे नारद से कहने लगे कि हम सिंसियरिटी से यादव गण-तंत्र की बेहबूदी के लिये काम करते हैं मगर फिर भी अक्रूर जो हमारे विरोधी पक्ष में बैठे हैं वह बुरी तरह से हमको क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिये यदि ऐसा कृष्ण के लिये हुआ था तो उनसे बड़ी तो यह सरकार है नहीं, इससे सरकार को इज्जत ही मिलती है। अगर उधर बैठे अक्रूर कृष्ण पर आक्षेप करें।

श्री गया प्रसाद (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, मैं वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट पर पक्ष और विपक्ष के भाषणों को सुनता रहा। बजट को देखने से पता चला सकता है कि किसी सरकार की क्या नीति है और उसका कार्य क्रम क्या है। ऐसी अवस्था में बजट की दो, तीन मदों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मालगुजारी में पिछले साल से ७ करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है और आबकारी में करीब सवा दो करोड़, बिक्री कर में तीन करोड़, स्टैम्प में सवा करोड़ की बृद्धि इस साल की गयी है। यह सब मिला कर करीब १३ करोड़ की वृद्धि हुई है और इस तरह तेरह करोड़ का भार गरीबों पर ही पड़ता है, और पिछले साल से बजट ८ करोड़ बढ़ा है। ८ करोड़ बजट बढ़ा और १३ करोड़ गरीबों पर टैक्स बढ़ा। इससे स्पष्ट होता है कि जो ५ करोड़ और ज्यादा बजट बढ़ा वह अमीरों को करों से मुक्त कर के गरीबों पर बढ़ा दिया गया। ऐसी स्थिति में ऐसा आभास इस बजट को देख कर नहीं होता जैसा कि वित्त मंत्री के भाषण से हुआ

कि यह बजट गरीबों को स्वर्ग पहुंचाने वाला और देश को तरक्की देने वाला है। भाषण कुछ है और बजट के आंकड़े कुछ कह रहे हैं। लेकिन मंत्री जी ने अपनी शैली में इस गन्दे और रद्दी बजट को भी अच्छे रूप में पेश करने की कोशिश की।

सुरक्षा की बातें इस सदन में कही गईं। मैं उस संबंध में ज्यादा न कह कर इतना कहूंगा कि सुरक्षा के नाम पर धन और खून गरीबों ने दिया और गरीबों के बेटे सीमा पर लड़े और उन्हीं गरीबों पर १३ करोड़ का भार इस वर्ष बढ़ा दिया गया। तो आप देखें कि गरीब, जिनके बल से यह सरकार और देश चल रहा है उनके लिये इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। इस बजट को देखने से साफ पता लगता है कि देश में बेकारी बढ़ेगी, देश में रिक्शा चलाने वालों की तादाद बढ़ेगी, खाने कपड़े के लिये देश तरस-तरस कर मर जायगा।

अब मैं बजट के ऊपर ज्यादा न कह कर कुछ अपने जिले की बात कहना चाहूंगा। वित्त मंत्रीजी बनारस जिले से आते हैं। सुरक्षा कोष की इतनी दुहाई दी गयी और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि यदि सुरक्षा कोष के लिये वसूली में कोई धांधली हुई है तो उसकी वे जांच करायेंगे। उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि मैं भी बनारस का हूं और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बनारस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव मिश्र जी हैं जो आज ५–६ वर्षों से राजकीय चुर्क सीमेंट फैक्टरी के स्टाकिस्ट हैं लेकिन बिक्री-कर के रजिस्टर में वे दर्ज नहीं किये गये हैं हालांकि ५–६ वर्षों से वे बिक्री-कर को सीमेंट की बिक्री पर वसूल कर रहे हैं जिसकी तादाद इस समय ५०–५५ हजार के हो चुकी है।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न। माननीय ब्रह्मदेव जी मिश्र कौंसिल के सदस्य हैं और यहां मौजूद नहीं हैं। तो क्या उनका नाम लेकर यहां आरोप लगाना ठीक होगा ?

श्री गया प्रसाद—

वाराणसी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को मैं जानता हूं कोई ब्रह्मदेव मिश्र हैं। वह परिषद् के सदस्य हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। वहां के अधिकारी ब्रह्मदेव जी मिश्र के विरुद्ध कोई ऐक्शन लेने से डरते हैं।

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—

यह इस सदन और सभी सदनों की परम्परा है कि जो सदन के फ्लोर पर अपने को डिफेंड नहीं कर सकता, उसके बारे में कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो ठीक है। जो सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं और अपने को डिफेंड नहीं कर सकते अतः उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाना चाहिये।

श्री गयाप्रसाद—

मैं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बारे में कह रहा हूं ....

श्री उपाध्यक्ष—

उनके खिलाफ और कार्यवाही करिये, लेकिन यहां सदन में उनके बारे में न कहिये।

श्री गयाप्रसाद—

श्रीमन्, मैं आप से कह रहा था कि सुरक्षा कोष में वाराणसी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से २–३ दिसम्बर, १९६२ को ८३ हजार रुपया दिया गया। जिसमें से २०,००० रुपया कलेक्टर का वसूल किया हुआ था २,००० रुपया असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा वसूल किया हुआ था जो प्रधान मंत्री के नाम में चेक था, १०,००० रुपया अंतरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा वसूल किया हुआ भी उसमें शामिल था। इस तरह से कांग्रेस द्वारा जमा की हुई ८३,००० रुपये की रकम थी। वहां इस तरह की धांधली हो रही है कि अंतरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष ने अध्यापकों और कर्मचारियों की एक–एक महीने की तनख्वाह काट ली है। और स्थिति यह

[श्री गयाप्रसाद]

है कि आज तक उनको उसकी रसीद नहीं मिली है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे अध्यापक और कर्मचारी हैं कि जिनकी ३-४ महीने की तनख्वाहें काटी गई हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों से तथा उनके अभिभावकों से भी पैसा वसूल किया गया है और रसीद नहीं दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस पैसे में से कितना पैसा सरकार के पास जमा हुआ, सुरक्षा कोष मे और कितना रुपया उनकी जेब में पड़ा हुआ है। इसकी जांच कराई जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अगले दिन अपना भाषण जारी रखें। मुझे कुछ सूचना देनी है।

अधिष्ठाता मंडल के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष ने इस सत्र के अधिष्ठाता मंडल के लिये निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत किया है।

(१) श्री जगदीशशरण अग्रवाल
(२) श्री जगदीश प्रसाद
(३) श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट
(४) श्री रामजीलाल सहायक
(५) श्री कृष्णानन्दराय
(६) कुंवर श्रीपालसिंह
(७) श्री चन्द्रजीत यादव
(८) श्री ब्रह्मदत्त मायर
(९) श्री कमलासिंह यादव
(१०) श्री भानुप्रतापसिंह

अब हम उठते हैं और कल १०–३० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१९ फरवरी, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५६ पर)

तालिका

फार्म का नाम	वर्ष	आय	व्यय	उपज
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	मनों में
चन्दौली ..	१९५७–५८ ..	११५१३	१२०५१	६०७
	१९५८–५९ ..	१२०२७	१११३०	५९१
	१९५९–६० ..	१२७३१	११६६५	६२१
	१९६०–६१ ..	११३६२	१२००२	५३३
	१९६१–६२ ..	१२३९१	१३७८४	७३४
मडुआडीह फार्म ..	१९५७–५८ ..	१६३८३	१४५२३	८९१
(क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र)				
	१९५८–५९ ..	३१२८०	२५०७३	१३२४
	१९५९–६० ..	२७९८१	२५४२५	१४४५
	१९६०–६१ ..	२८०३३	२७१२५	१५९१
	१९६१–६२ ..	२९०५४	३१९८६	१६१९
राजकीय पशुधन एवं				
कृषि क्षेत्र आराजी लाइन्स	१९५७–५८ ..	११७७८६	१८११४७	५५६८
	१९५८–५९ ..	१६०९७४	२०८२४५	४८४८
	१९५९–६० ..	१८३३४२	२०७७९४	५४८८
	१९६०–६१ ..	२०९७२५	२१७५५१	६९७०
	१९६१–६२ ..	१९०१२९	२२४६३९	६४१५

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३२२ एल० ए०—१९६३—८५० । (प्रो०)